श्रम की दुनिया

आईएलओ की पत्रिका, संख्या 41, अप्रैल 2011

अंतरराष्ट्रीय
श्रम
कार्यालय

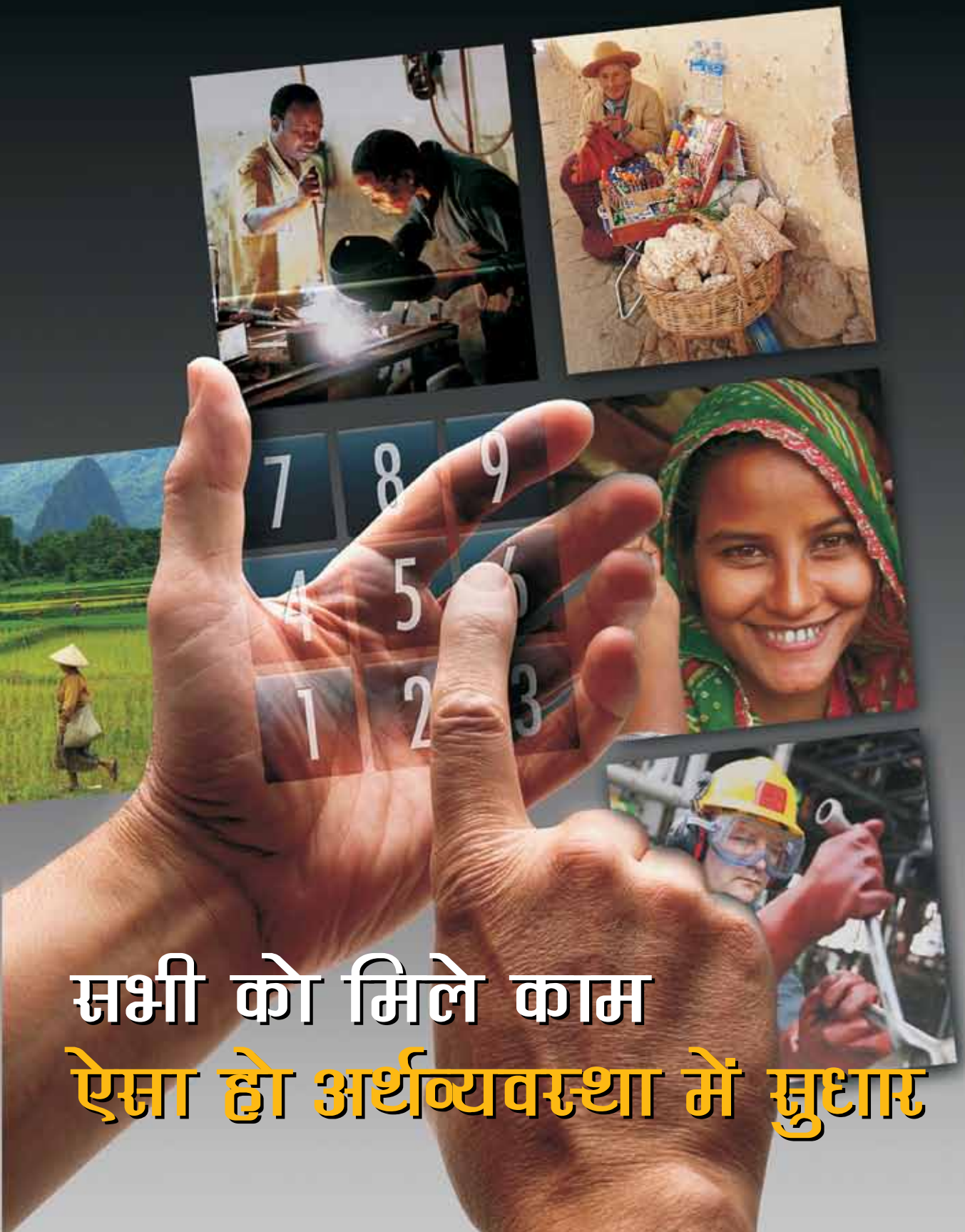

सभी को मिले काम
ऐसा हो अर्थव्यवस्था में सुधार

श्रम की दुनिया

आईएलओ की पत्रिका

श्रम की दुनिया पत्रिका का प्रकाशन जेनेवा में आईएलओ के जन संपर्क ब्यूरो द्वारा किया जाता है। इस पत्रिका का प्रकाशन चाइनीज़, चेक, डेनिश, अंग्रेज़ी, फ़िनिश, फ़्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, जापानी, नार्वेजियन, रूसी, स्लोवाक, स्पैनिश और स्वीडिश भाषाओं में भी होता है।

सम्पादक
हैन्स वॉन रोलैंड

स्पैनिश संस्करण
आईएलओ कार्यालय, मैड्रिड के सहयोग से

प्रोडक्शन मैनेजर
किरन मेहरा - कर्पलमन

प्रोडक्शन असिस्टंट
कोरीन लुचीनी, मार्टिन जैक्विनॉड

फ़ोटो संपादक
मार्सेल क्रोज़ेट

कला निर्देशन
एमडीपी, आईएलओ, ट्यूरिन

कवर डिज़ाइन
मेतो मॉन्तेसानो, लुका फिओरे, आईएलओ ट्यूरिन

कवर फोटो
आईएलओ फोटो

संपादकीय बोर्ड
टामस नेट्टर (अध्यक्ष), शारलट बोशां, किरन मेहरा-कर्पलमन, कोरिन पर्थ्रिस, हैन्स वॉन रोलैंड

यह पत्रिका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं है। पत्रिका में व्यक्त विचार आवश्यक रूप से आईएलओ के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हैं। पत्रिका में अभिव्यक्त विशिष्ट उल्लेख किसी भी देश, क्षेत्र या उपक्षेत्र और उनके प्रशासन या उनकी सीमाओं के बारे में आईएलओ के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हैं।

पत्रिका में कंपनियों या वाणिज्यिक उत्पादों या प्रक्रियाओं का उल्लेख आईएलओ द्वारा उन्हें मान्यता देना नहीं है और किसी निश्चित कंपनी, वाणिज्यिक उत्पाद या प्रक्रिया का उल्लेख रह जाना उनके प्रति आईएलओ की असहमति नहीं है।

पत्रिका के आलेखों या छायाचित्रों (फ़ोटो एजेंसियों के छायाचित्रों को छोड़कर) का, स्रोत का उल्लेख करके स्वतंत्रता से पुनःउपयोग किया जा सकता है। लिखित सूचना का स्वागत होगा।

सभी पत्र व्यवहार निम्न पते पर किये जाएं:-
Neelam Agnihotri
Communications & Information Unit INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
Subregional Office for South Asia
Theatre Court, 3rd Floor
India Habitat Centre
Lodi Road, New Delhi-110003
Tel: 011-24602101-02-03
email: sro&delhi@ilodel.org

मुद्रक: विवा प्रेस प्रा. लि.,
नई दिल्ली-110020
आईएलओ ट्यूरिन द्वारा प्रकाशित
आईएसएसएन : 1020-0010

इतिहास में आईए

वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामाजिक आधार के लिए लंबा संघर्ष

इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बीस और तीस के दशक के दौरान अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा था। बीसवे दशक से पहले और तीसवें दशक के ठीक बाद, दुनिया ने दो बड़े विश्वयुद्धों का सामना किया था। यह महामंदी (ग्रेट डिप्रेशन) से एकदम पहले का दौर था। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया का असर साफ देखा जा रहा था। ऐसे में आईएलओ के सामने यह एक बड़ी चुनौती थी कि सामाजिक प्रगति को किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया जाए। मौजूदा दौर भी संगठन के सामने ऐसे ही हालात पेश कर रहा है। हाल के दो दशकों में उत्पादन, वित्त और व्यापार के क्षेत्र में वैश्वीकरण ने कदम रखा है और दुनिया के बहुत से देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक बार फिर आर्थिक मंदी से जूझना पड़ा है। इसीलिए आईएलओ के सामने फिर वही स्थिति है। संगठन के सामने अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक प्रगति को एकीकृत करने का उद्देश्य है। साथ ही पूर्ण रोजगार का लक्ष्य भी हासिल करना है।

जब वर्ष 1919 में आईएलओ की स्थापना की गई थी, तब संगठन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों का निर्माण करना था। इन मानकों के माध्यम से सभी देशों में आर्थिक वृद्धि के साथ–साथ काम करने की स्थितियों को सुधारने का उद्देश्य था। संगठन के सबसे पहले निदेशक अल्बर्ट थॉमस का कहना था, 'यह संगठन का अधिकार, या यूं कहें, कर्तव्य है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि उसके सामाजिक सुधार कार्यक्रमों को आर्थिक आयाम अवश्य मिले।'

आईएलओ ने हमेशा आर्थिक और सामाजिक नीतियों के बीच समन्वय को महत्व दिया है। तीसवें दशक में आईएलओ ने सामाजिक और आर्थिक मसलों को लक्षित करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तब महामंदी ने इस विश्वास को मजबूत किया था कि आर्थिक और सामाजिक नीतियों के बीच सामंजस्य बहुत जरूरी है। दुर्भाग्यवश, लीग ऑफ नेशंस, जो कि आईएलओ का परवर्ती संगठन था, अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को समन्वित करने में असफल रहा था। इस दौरान अनेक लोगों ने आईएलओ पर विश्वास जताया था। उन्हीं में से एक थे, केयेन्स जिन्होंने *द जनरल थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी* में संगठन के कदमों की प्रशंसा की थी।

तीसवें दशक में आईएलओ ने आर्थिक समन्वय का अभियान चलाया जिसके केंद्र में रोजगार को बढ़ावा देना था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1944 में फिलाडेल्फिया घोषणापत्र मंजूर किया गया। इस घोषणापत्र में कहा गया कि आईएलओ को मूलभूत उद्देश्यों के मद्देनजर सभी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय नीतियों और उपायों की जांच करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है।[1]

[1] *घोषणापत्र में आईएलओ के लिए एक एकीकृत लक्ष्य निर्धारित किया गया है : सभी मनुष्यों को नस्ल, रंग या लिंग से इतर, स्वतंत्रता और सम्मान की स्थितियों में अपने भौतिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास का, आर्थिक सुरक्षा और समान अवसर का अधिकार है।*

लओ

17 मई 1944 को वाशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में फिलाडेल्फिया घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करते आईएलओ के तत्कालीन निदेशक एडवर्ड जे फेलेन। फोटो में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं, (बैठे हुए– बाएं से दाएं)अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, वाल्टर नाश, ई. जे. फेलन, (खड़े हुए– बाएं से दाएं), अमेरिकी विदेश सचिव कॉर्डेल हल, अमेरिकी श्रम सचिव फ्रांसिस पार्किन्स, आईएलओ सहनिदेशक लिंडसे रॉजर्स।

फिर भी युद्ध के तत्काल बाद नई बहुपक्षीय प्रणाली की संरचना के आग्रह ने संगठन के व्यापक आर्थिक पहल के विचार को हाशिये पर डाल दिया। गैर कम्यूनिस्ट देशों में आर्थिक और वित्तीय मसलों को ब्रेटेन वुड इंस्टीट्यूशन को सौंप दिया गया और विश्वव्यापी आर्थिक और सामाजिक नीतिगत मुद्दों का दायित्व संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (इकोसॉक) को दिया गया।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के शुरुआती दशकों में शीत युद्ध के कारण एक व्यापक, विश्वव्यापी दृष्टिकोण बरकरार रखना मुश्किल होने लगा। व्यापार और पूंजीगत नियंत्रणों ने विभिन्न देशों, खासकर सबसे अधिक विकसित देशों, की आर्थिक संभावनाओं पर कब्जा कर लिया। बीसवीं शताब्दी के अंत में विश्वव्यापी आर्थिक अंतर्निर्भरता ने विभिन्न देशों के सामने यह चुनौती रखी कि वे आपस में समन्वय बढ़ाएं।

> “यह संगठन का अधिकार, या यूं कहें, कर्तव्य है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि उसके सामाजिक सुधार कार्यक्रमों को आर्थिक आयाम अवश्य मिले।”

© रून कॉगस्रो

पिछले साल सितंबर में ओस्लो में आयोजित सम्मेलन की मेजबानी नार्वे के प्रधानमंत्री जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने की, सम्मेलन को आईएमएफ और आईएलओ ने सह प्रायोजित किया था

अंतरराष्ट्रीय सामाजिक नीति की बहाली

अस्सी के दशक तक यह सिलसिला जारी रहा। इसके बाद के सालों में विश्व परिदृश्य बदला। इस दौरान और नब्बे के दशक के शुरुआत में दो ऐसे बदलाव हुए जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय सामाजिक नीति का प्रादुर्भाव हुआ। एक तो विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सामाजिक आयाम को प्रस्तावित करते हुए एक नई बहस की शुरुआत की। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में एक व्यापक पहल की पेशकश की गई जिसमें सामाजिक विकास की अंतरराष्ट्रीय नीति पर जोर दिया गया था। शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को इन दोनों प्रस्तावों में शामिल नहीं था, लेकिन आखिरकार संगठन ने अपना रास्ता तलाश ही लिया।

शुरुआत कैसे हुई? डब्ल्यूटीओ में श्रम मानकों और व्यापार के बीच कोई औपचारिक संबंध नहीं था। लेकिन अंततः अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस बात पर आम सहमति बनाई कि श्रम मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी आईएलओ की है। दूसरे मामले में, आईएलओ की भूमिका वर्ष 1995 में तय हुई। इस साल संयुक्त राष्ट्र में आयोजित विश्व सामाजिक शिखर सम्मेलन के दौरान सभी देशों ने मुख्य श्रम मानकों को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए व्यापक और समन्वित विचार था। इसके माध्यम से आईएलओ के सभी प्रमुख समझौतों को मान्यता मिली। इस सम्मेलन को हुआन सोमाविया द्वारा प्रस्तावित और प्रस्तुत किया गया था। तब श्री सोमाविया संयुक्त राष्ट्र में चिली के राजदूत थे।

इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि सम्मेलन के माध्यम से आईएलओ के पूर्ण रोजगार, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक एकीकरण से संबंधित मानकों को मान्यता मिली। सामाजिक आयामों पर कायम गतिरोध समाप्त हुआ। इस सम्मेलन के बाद वर्ष 1998 में कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों के घोषणापत्र की मंजूरी दी गई। विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के लिए सार्वभौमिक सामाजिक धरातल तैयार करने की दिशा में यह पहला कदम था। इस घोषणापत्र की विशेषता उसकी सार्वभौमिकता में छिपी थीः घोषणापत्र में उन सिद्धांतों और अधिकारों की आधारशिला रखी गई थी जिनके तहत सभी देश आईएलओ की सदस्यता का सम्मान करें, भले ही उन्होंने किसी खास समझौते को संपुष्टि दी हो अथवा नहीं।

सभी के लिए उत्कृष्ट श्रम

वर्ष 1998 में श्री हुआन सोमाविया संगठन के महानिदेशक चुने गए। उन्होंने सामाजिक शिखर सम्मेलन को प्रस्तावित और आयोजित किया था और यह निर्वाचन उनकी उस भूमिका की तार्किक परिणति थी। पद संभालने के बाद उन्होंने उत्कृष्ट श्रम कार्यसूची को प्रस्तावित किया और विभिन्न कार्यक्रमों को चार रणनीतिगत उद्देश्यों में समूहबद्ध किया। ये उद्देश्य हैं, कार्यस्थल पर श्रमिकों के अधिकार, रोजगार, सामाजिक संरक्षण और सामाजिक संवाद।

लेकिन आईएलओ की संरचना में उत्कृष्ट श्रम का समावेश करना पर्याप्त नहीं था। सबसे बड़ा काम संगठन के भीतर और बाहर के लोगों को इस बात के लिए राजी करना था कि उत्कृष्ट श्रम के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण रखना जरूरी है। इसी के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक नीतियों को जोड़ा जा सकता है।

सबसे पहला कदम अंतरराष्ट्रीय कार्यसूची में उत्कृष्ट श्रम को शामिल करना था। वर्ष 1999 में श्री सोमाविया ने सिएटल में आयोजित डब्ल्यूटीओ की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। फिर वर्ष 2000 में बैंकाक में यूएनसीटीएडी–एक्स की बैठक और इसके बाद विश्व आर्थिक मंच और विश्व सामाजिक मंच की वार्षिक बैठकों में उन्होंने उत्कृष्ट श्रम के अपने संदेश को मजबूती से पेश किया। इसके साथ–साथ, आईएलओ के अन्य अधिकारियों ने विभिन्न देशों में विश्व बैंक के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में उत्कृष्ट श्रम के लक्ष्यों को आत्मसात किया।

अनेक संगठनों, जैसे यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, अमेरिकी राज्यों के संगठन और एशियाई विकास बैंक ने अपने वक्तव्यों में क्षेत्रीय स्तर पर उत्कृष्ट श्रम के

लक्ष्य को व्यापक स्तर पर स्वीकृत किया। वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में विश्व के शीर्ष नेतृत्व ने इस दृष्टिकोण का अनुमोदन करते हुए सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की समीक्षा की।

इसी दौरान विश्व नेता इस बात पर सहमत हो चुके थे कि राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक प्रगति बहुत कुछ भूमंडलीकरण की गति और प्रवृत्ति पर निर्भर करने लगी है। सिएटल में जिस तरह का विरोध अभियान चलाया गया था, वह ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्शंस और डब्ल्यूटीओ के भी खिलाफ था। उनके खिलाफ यह आरोप था कि उन्होंने सामाजिक स्तर पर भूमंडलीकरण की विनाशकारी प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के आयात और नौकरियों की ऑफशोरिंग में वृद्धि से रोजगार प्रभावित हुआ और श्रमिकों के बीच असंतोष और असुरक्षा बढ़ने लगी। विकासशील देशों में बढ़ती गरीबी और निम्न आय वर्ग के अनेक देशों के विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था से बाहर निकलने पर चिंता व्यक्त की जाने लगी।

इस संबंध में आईएलओ पहल करने को तैयार था। भूमंडलीकरण के सामाजिक स्तंभों को किस प्रकार मजबूत किया जाए और किस प्रकार एक स्थिर और विनियामक विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाए, इस संबंध में संगठन के पास एक दूरदृष्टि थी। वर्ष 2001 में आईएलओ ने विश्व आयोग की स्थापना का प्रस्ताव सफलतापूर्वक रखा। आयोग की कार्यसूची में विश्वव्यापी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक नीतियों को एकीकृत करने का लक्ष्य था। इस आयोग ने वर्ष 2004 की अपनी रिपोर्ट में कई प्रकार की सिफारिशें कीं जिनके केंद्र में भूमंडलीकरण की निष्पक्ष की प्रवृत्ति थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत सुसंगति की ओर बढ़ते कदम

रिपोर्ट के एक निष्कर्ष में कहा गया था कि जिन संगठनों की प्रणाली बहुपक्षीय है, उनमें अधिक 'नीतिगत सुसंगति' की आवश्यकता है। संगठन ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र की अन्य संस्थाओं के सहयोग से वृद्धि, निवेश और रोजगार के लिए समान अंतरराष्ट्रीय नीतिगत संरचना के निर्माण के लिए 'पॉलिसी कोहेरेंस इनीशिएटिव' की शुरुआत की।

शुरुआत में प्रगति की रफ्तार धीमी थी। समस्या का खुलासा तब हुआ, जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक प्रतिनिधि ने एक बैठक में यह पूछ लिया कि 'सुसंगति का क्या अर्थ है? हम आपके साथ सुसंगति बैठाएंगे या आप हमारे साथ?' इसके बाद अनेक संयुक्त कदम उठाए गए। आईएलओ और डब्ल्यूटीओ ने मिलकर व्यापार और रोजगार पर कई अध्ययन किए।

बदलाव शुरू हो चुके थे। पिछले साल सितंबर में ओस्लो में आयोजित किए गए ऐतिहासिक सम्मेलन में– जिसे नार्वे के प्रधानमंत्री जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने आयोजित और आईएमएफ–आईएलओ ने प्रायोजित किया था– विभिन्न देशों के सरकारी प्रतिनिधियों और श्रम, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि वर्ष 2008 के आर्थिक संकट के बाद से बेरोजगारी और अल्परोजगार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। सम्मेलन के दौरान आईएमएफ और आईएलओ के बीच इस बात पर सहमति बनी कि दोनों संगठन नीतिगत विकास पर संयुक्त रूप से काम करेंगे, विशेषकर दो क्षेत्रों में। वे रोजगार वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने की नीतियों और गरीबी और संवेदनशील स्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

आर्थिक बहाली और रोजगार सृजन के बीच के अंतराल को कम करने के लिए जून 2009 में एक और प्रयास किया गया। इस साल अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में स्वीकृत की गई विश्वव्यापी रोजगार संधि के माध्यम से इस अंतराल को कम करने की अंतरराष्ट्रीय पहल की गई। विश्वव्यापी आर्थिक और सामाजिक संकट के परिणामस्वरूप, इस संधि में ऐसी व्यावहारिक, जांच की गई सामाजिक और आर्थिक नीतियों को प्रस्तुत किया गया था जिन्हें अनेक देशों में उपयोग में लाया जा चुका है। किसी खास देश की स्थितियों के अनुसार, इन नीतियों में संशोधन भी किए जा सकते हैं। पिट्सबर्ग में सितंबर 2009 में आयोजित किए गए जी 20 शिखर सम्मेलन में इस संधि का स्वागत किया गया और इस बात पर सहमति जताई गई कि भविष्य में आर्थिक वृद्धि के लिए रोजगारोन्मुखी संरचना तैयार करना कितना महत्वपूर्ण है।

इस समय बहुत से अर्थशास्त्री बीस और तीस के दशक से सबक सीखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में विश्व बेरोजगारी, संरक्षणवाद और राष्ट्रवाद के गर्त में गिरने से बच सके। एक सबक तो यह है कि अगर आईएलओ की चेतावनी और प्रस्तावों पर ध्यान दिया जाए तो महामंदी के बाद महाबहाली का रास्ता साफ होगा। अधिक नीतिगत सुसंगति के प्रयास संभावना जगाते हैं और आईएलओ इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन बहाली की प्रतीक्षा है और भविष्य की संभावनाओं पर लंबे समय से कायम रोजगार संकट के बादल छाए रहने की आशंका है। ■

अगर आप समसामयिक विषयों पर आईएलओ इतिहास की प्रासंगिकता के बारे में अधिक जानने चाहते हैं तो *द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस 1919–2009* (लेखक– जैरी रॉड्रिग्स, ली स्वेप्टसन, एडी ली और जैसमीन वान डाले) का अध्ययन करें (जेनेवा, आईएलओ, 2010)।

विषय सूची

अप्रैल 2011, संख्या 41

कवर स्टोरी

8 **रोजगार केंद्रित सुधार को प्रोत्साहन**

वित्तीय संकट के तीन साल बाद विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में सुधार देखा जा रहा है, लेकिन मौजूदा सुधारों के माध्यम से पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। जितना रोजगार उपलब्ध हो रहा है, वह भी बहुत अच्छे स्तर का नहीं है। उसकी गुणवत्ता को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। *श्रम की दुनिया* के इस अंक में अपने संपादकीय में आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया ने लिखा है : वित्तीय और सामाजिक स्थिरता साथ–साथ होनी चाहिए। इसके अभाव में न केवल विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था, बल्कि सामाजिक संसुगति को भी खतरा होगा।

प्रिय पाठकों,

आपकी प्रिय पत्रिका *श्रम की दुनिया* का कवर बदल गया है। यह नया कवर अधिक आधुनिक, स्पष्ट और विशिष्ट है। पत्रिका के भीतरी पृष्ठों में भी हमने बदलाव किए हैं। पठनीयता बढ़ाने के लिए हमने पत्रिका के लेआउट और डिजाइन में परिवर्तन किया है, साथ ही पत्रिका में तस्वीरों को अधिक महत्व देना शुरू किया है। आपको पत्रिका के कई नियमित स्तंभ अलग लगेंगे। हमने सही संतुलन बनाने के लिए स्पेस और इलस्ट्रेशनों का उपयोग किया है। हमें उम्मीद है कि हमारे बदलाव आपको पसंद आएंगे। आप अपनी टिप्पणियां और फीडबैक हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं, ilo_magazine@ilo.org.

1919 में गठित, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) अपने 175 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक मंच पर लाता है ताकि विश्व भर में जीवन और कार्य की परिस्थितियों तथा संरक्षण में सुधार के लिए एक समान कार्रवाई की जा सके। जेनेवा में स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, संगठन का स्थायी सचिवालय है।

© एम.क्रोजेट / आईएलओ

श्रम की दुनिया की स्थिति

12 अब दूसरे संकट का सामना

14 विश्वव्यापी रोजगार प्रवृतियां

16 नौकरियों का घाटाः सामाजिक सुसंगति को खतरा

20 आर्थिक बहाली के लिए योजना निर्माण

25 वित्तीय बाजार की बहालीः लुढ़कने की प्रवृति

28 युवा बेरोजगारी उच्चतम स्तर तक पहुंची

सामान्य लेख

30 पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ः नए जीवन और नई जीविका का सृजन

32 ट्री ने दिया एक युवा को नया जीवन

35 स्कोर को बरकरार रखने के लिए छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमों को सहायता

38 निर्माण क्षेत्र में हरित रोजगारः छोटा बदलाव – बड़ा असर

42 गुंडो लाशू (हमारी जीत): दक्षिण अफ्रीका में आम लोगों ने बनाई अपनी राह

47 भविष्य के शिक्षक और प्रशिक्षक

64 हाथों में हुनर, चेहरे पर खुशी

फीचर

समाचार

50 जी 20 देशों ने रोजगार, सामाजिक संरक्षण की प्रतिबद्धता को लागू करने की अपील की

51 मिशेल बाचेलेटः 'सामाजिक संरक्षण का धरातल देता है अगला ठोस कदम'

52 आईएमएफ/एलओ ने रोजगार केंद्रित आर्थिक बहाली की प्रतिबद्धता दर्शाई

54 आईएलओ महानिदेशक को मिला एमडीजी पुरस्कार

54 आईएलओ महानिदेशक ने चिली के खान मजदूरों के बचाव अभियान की प्रशंसा की

55 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में साल 2010 का नोबल पुरस्कार

56 विशेषज्ञों ने कृषि क्षेत्र में सुरक्षा और स्वास्थ्य पर आईएलओ की नई व्यवहार संहिता को मंजूरी दी

© ए. अबानोज़

फीचर

महाद्वीपों के इर्द गिर्द

58

फीचर

नए प्रकाशन

60

62 जीएसएसडी साउथ–साउथ एक्सपो

कवर स्टोरी

रोजगार केंद्रित बहाली

आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया

विश्वव्यापी वित्तीय संकट ने बेरोजगारी को चरम पर पहुंचा दिया है। इस समय विश्व में बेरोजगारों की संख्या 21 करोड़ 10 लाख के लगभग है। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने यह चिंता व्यक्त की थी कि विश्व के विभिन्न देशों में पर्याप्त उत्कृष्ट श्रम सृजित करने में विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था असफल रही है। आज स्थिति पहले से अधिक भयावह है।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेरोजगारी के आधिकारिक आंकड़े सिर्फ संकेत भर हैं। दुनिया के लाखों लोग गरीबी की स्थितियों में जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसे बहुत से पुरुष और महिलाएं हैं जो पूर्णकालिक काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अल्पकालिक अनुबंधों पर काम करने को विवश होना पड़ता है। उन्हें पूर्णकालिक काम नहीं मिलता। बहुत से लोग हतोत्साहित होकर काम तलाशना ही बंद कर देते हैं। विश्व की आधी श्रमशक्ति संवेदनशील रोजगार कर रही है। हर पांच में से चार व्यक्तियों को मूलभूत सामाजिक संरक्षण नहीं मिल पाता है।

हर साल श्रम बाजार में साढ़े चार करोड़ युवा दाखिल होते हैं। वर्ष 2010 की हमारी रिपोर्ट *ग्लोबल इंप्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ* कहती है कि 15 से 24 वर्ष के बीच के आर्थिक रूप से सक्रिय 62 करोड़ युवाओं में से 8 करोड़ 10 लाख युवा वर्ष 2009 के अंत तक बेरोजगार थे। यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वर्ष 2007 में कुल बेरोजगारों की संख्या से यह 78 लाख अधिक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि युवा बेरोजगारी की दर वर्ष 2007 में 11.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009 में 13.0 प्रतिशत हो गई।

रिपोर्ट में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि मौजूदा संकट फिर कहर बरपा सकता है। इसमें युवाओं की एक ऐसी लुप्त पीढ़ी का जिक्र किया गया है जो श्रम बाजार से गायब हो रही है क्योंकि उसने अच्छे जीवन की उम्मीद छोड़ दी है।

यह धुंधला परिदृश्य भूमंडलीकरण के असंतुलन के कारण उत्पन्न हुआ है, जो कि गलत दिशा में जा रहा है। इसके बावजूद बहाली के संकेत देखे जा रहे हैं। हां, यह जरूर है कि दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ ही उद्यमों के लिए भी संकट अभी टला नहीं है। हमें रोजगार केंद्रित वृद्धि की रणनीति को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो आर्थिक बहाली का लाभ उन्हें बहुत देर से मिलेगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। संभव है, उन्हें लाभ मिले ही नहीं।

© आईआरआईएन

को प्रोत्साहन

वास्तविक अर्थव्यवस्था से नीतियों को जोड़ना

हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें अपनी नीतियों को वास्तविक अर्थव्यवस्था से जोड़ना होगा। हमें उन नीतियों के माध्यम से उन लोगों को लाभ पहुंचाना होगा जो उत्कृष्ट रोजगार पाने की इच्छा रखते हैं।

इसीलिए हमने सितंबर 2009 में ओस्लो में आईएलओ/आईएमएफ सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में आईएमएफ के निदेशक डोमिनिक स्ट्राउस–कान, विश्व के नेता, नियोक्ता व श्रमिक संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, शिक्षाविद, आईएलओ प्रतिनिधि शामिल हुए थे। मैंने भी उस सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य न केवल तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना था, बल्कि भविष्य के लिए तैयारी करना भी था। क्योंकि हम अतीत के असंतुलन को खत्म करके ही दीर्घकालीन, संतुलित और सभी को सम्मिलित करने वाले विकास को हासिल कर सकते हैं।

> “आर्थिक संकट से एक पूरी पीढ़ी के लुप्त होने की आशंका है। एक पूरी पीढ़ी श्रम बाजार से गायब हो रही है, क्योंकि उसने अच्छे जीवन की उम्मीद छोड़ दी है।”

मैं समझता हूं कि इस संबंध में यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण था। यह ऐसे समय में आयोजित किया गया था जब आर्थिक बहाली के माध्यम से नए रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहे। दुनिया भर के देशों की सरकारें, श्रमिक और उद्यमी समुदाय यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रोजगार संकट के मानवीय मूल्य को कैसे कम किया जाए।

© आईआरआईएन

यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें ग्रीस, लाइबेरिया और स्पेन ने हिस्सा लिया था। ये तीनों देश संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। अब इन देशों में संकट के असर को कम करने के लिए साहसी और नए किस्म के उपाय किए जा रहे हैं। हमें सम्मेलन के दौरान उन उपायों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर जानने का मौका मिला। पर सबसे ज्यादा उल्लेखनीय बात यह थी कि 66 सालों में यह पहली बार था कि आईएमएफ और आईएलओ ने एक साथ मिलकर काम किया था। सम्मेलन के जरिए उन्हें यह जानने का मौका मिला था कि किस प्रकार वे मिलकर किसी भी जटिल समस्या का समाधान कर सकते हैं।

सम्मेलन का मुख्य संदेश यह था कि आर्थिक बहाली के केंद्र में रोजगार सृजन होना ही चाहिए। सम्मेलन में इस बात पर सामान्य सहमति बनी कि निम्न मुद्रास्फीति और दुरुस्त वित्तीय परिकलन के साथ–साथ पूर्ण रोजगार एक वृहद आर्थिक उद्देश्य होना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण और संबंधित निष्कर्ष यह रहा कि कि रोजगार और सामाजिक नीतियों को वृहद आर्थिक मुद्दों से अलग करके न देखा जाए। विश्व व्यापी अर्थव्यवस्था उससे भी कहीं अधिक जटिल है। हमें नीतियों के बीच बेहतर और गहरे समन्वय, साथ ही संस्थानों और विभिन्न देशों के बीच समन्वय बढ़ाने की जरूरत है। इस दिशा में भी सम्मेलन ने एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया।

सम्मेलन के अंत में आईएलओ और आईएमएफ के बीच इस बात पर सहमति बनी कि दोनो संगठन विशेषकर दो क्षेत्रों में संयुक्त रूप से काम करेंगे। सबसे पहले तो हम सभी देशों के सबसे संवेदनशील लोगों को न्यूनतम सामाजिक संरक्षण प्रदान करने के विचार पर काम करेंगे। यह संयुक्त राष्ट्र की अवधारणा है और आईएलओ ने इस पर काम करना शुरू किया है। अब इस काम में आईएमएफ की वित्तीय विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा। दूसरी ओर, हम एक साथ मिलकर ऐसी नीतियों पर काम करेंगे, जो रोजगार समृद्ध वृद्धि को केंद्र में रखें।

इस बात पर भी सामान्य सहमति बनी कि संकट के दौर में सामाजिक संवाद भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परस्पर बातचीत करके ही जटिल मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाई जा सकती है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि संकट के सामाजिक परिणामों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अंततः दोनों संगठन भविष्य में जी 20 देशों और उनकी परस्पर आकलन प्रक्रिया के साथ सहयोग जारी रखेंगे जिससे मजबूत, दीर्घकालीन और संतुलित विश्वव्यापी वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

ओस्लो में आईएलओ–आईएमएफ सम्मेलन के बाद क्या?

हालांकि आईएमएफ और आईएलओ के अपने–अपने अध्यादेश और नीतिगत उपाय हैं, लेकिन हम साथ मिलकर वृद्धि, रोजगार और सामाजिक संबद्धता की चुनौतियों का सामना करेंगे।

इस जुड़ाव की शुरुआत मार्च 2009 में हुई। मार्च 2009 में आईएमएफ के प्रबंध निदेशक डोमिनिक स्ट्राउस–कान ने आईएलओ के संचालन निकाय का दौरा किया। इसके बाद हमने न्यूयार्क में सहस्राब्दि

विकास लक्ष्य पर केंद्रित शिखर सम्मेलन और नवंबर में सियोल में जी 20 की बैठक में भाग लिया।

अगले साल श्री कान ने अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को संबोधित किया। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस सम्मेलन ने हमें इस बात का अहसास कराया कि हमें साथ–साथ मिलकर काम करना चाहिए। इससे कई महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दों को सुलझाना आसान होगा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एक संगठन के नजरिए से काम करना आसान नहीं है।

हमें जिन क्षेत्रों पर साथ–साथ काम करना है, वे हैं बढ़ती असमानता, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बढ़ना, पर्याप्त रोजगार न उत्पन्न करने वाली वृद्धि, उत्पादकता लाभ और स्थिर वेतन, बुनियादी सामाजिक संरक्षण का अभाव आदि। ओस्लो बैठक में हमने ऐसे अनेक समाधान तलाशे जिनकी मदद से हम लाखों लोगों को श्रम बाजार में वापस ला सकेंगे। रोजगार संकट का समाधान करने से न केवल अर्थपूर्ण आर्थिक बहाली संभव होगी, बल्कि इससे सामाजिक सुसंगति और शांति भी कायम होगी।

आईएलओ की उत्कृष्ट श्रम की कार्यसूची समाज के लिए उल्लेखनीय है। इससे व्यक्तिगत सम्मान वापस मिलेगा। परिवार में स्थिरता आएगी। समुदाय में शांति स्थापित होगी। लोग सरकार और कारोबारी जगत पर भरोसा करें, संगठनों की विश्वसनीयता बढ़े, तभी समाज अच्छी तरह से चलता है। श्रम उत्पादकता के मूल्य से कहीं बढ़कर है। सभी सर्वेक्षण बताते हैं कि राजनैतिक कार्यसूची में इस बात को प्राथमिकता

आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया और आईएमएफ के प्रबंध निदेशक डोमिनिक स्ट्राउस–कान

मिलनी चाहिए कि लोगों को अच्छा रोजगार करने का मौका मिले।

अब चुनौती इस बात की है कि ओस्लो सम्मेलन के बाद काम की गति धीमी न पड़े। सियोल में हाल ही में हुए जी 20 शिखर सम्मेलन में पुष्टि की गई थी कि आर्थिक बहाली के केंद्र में अच्छा रोजगार सृजन होना चाहिए। मैं जी 20 देशों से आग्रह करता हूं कि वे इस प्रतिबद्धता को लागू करें और आईएलओ के साथ पूरा सहयोग करें।

संकट से बाहर निकलने के लिए यह जरूरी है कि सभी के साथ न्याय किया जाए। अगर लोगों को यह भरोसा होगा कि सभी लोग समान रूप से दबाव झेल रहे हैं तो वे विषम विकल्पों को भी स्वीकार कर लेंगे। विभिन्न देशों की सरकारों को ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए जब उन्हें वित्तीय बाजार की मांगों और अपने नागरिकों की जरूरतों के बीच में से किसी एक को चुनना पड़े। वित्तीय और सामाजिक स्थिरता साथ–साथ आनी चाहिए। अन्यथा, विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के साथ–साथ सामाजिक संबद्धता भी खतरे में पड़ जाएगी। ■

श्रम की दुनि

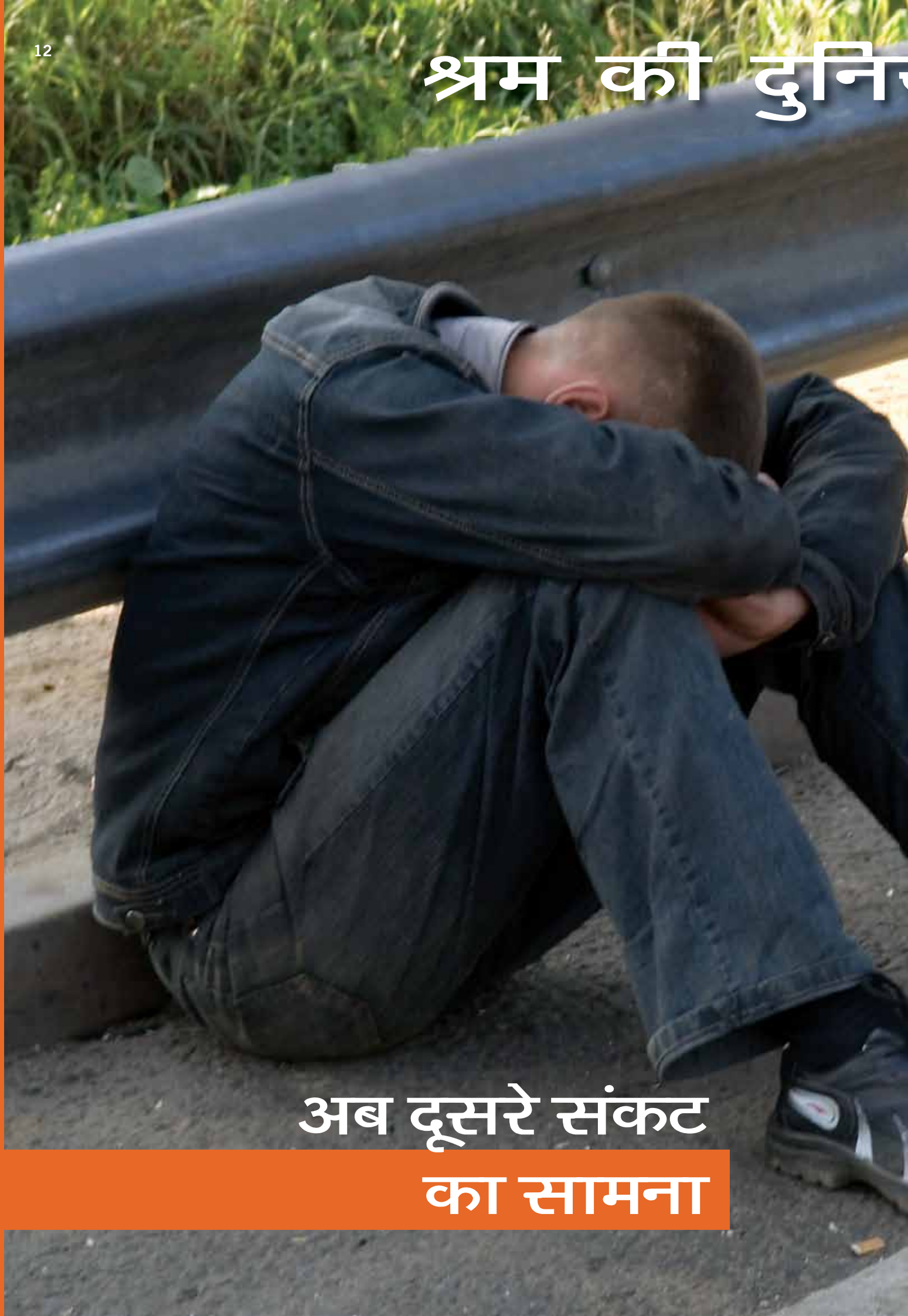

अब दूसरे संकट का सामना

या की क्या है हालत

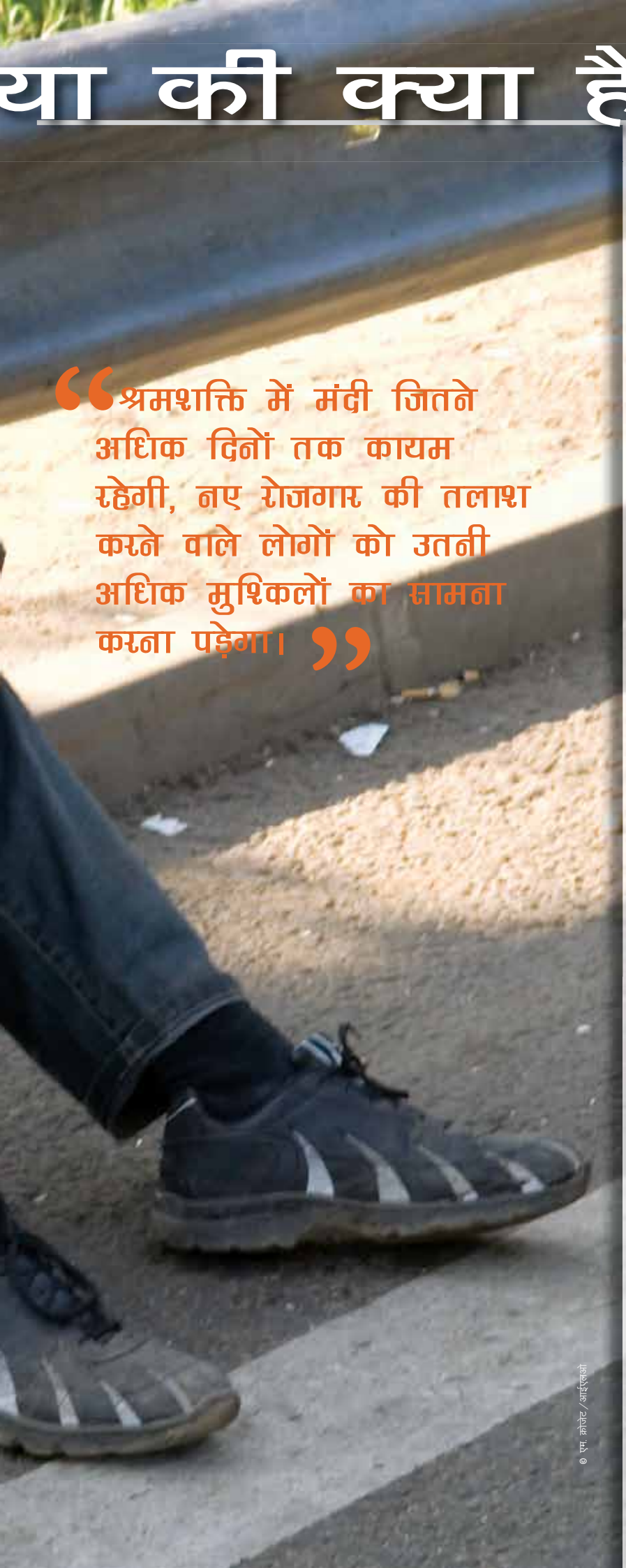

"श्रमशक्ति में मंदी जितने अधिक दिनों तक कायम रहेगी, नए रोजगार की तलाश करने वाले लोगों को उतनी अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।"

© एम. क्रोजेट/आईएलओ

आईएलओ की अनुसंधान शाखा की सितंबर माह की रिपोर्ट कहती है, 'श्रम बाजार में लंबे समय से छाई मंदी' ने अनेक देशों में सामाजिक परिदृश्य को बदतर किया है।'

वर्ल्ड ऑफ वर्क 2010–फ्रॉम वन क्राइसिस टू द नेक्स्ट नामक इस रिपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। यह संस्थान आईएलओ की एक शाखा है। इसमें कहा गया है कि वित्तीय संकट के तीन साल बाद विश्व व्यापी अर्थव्यवस्था में बहाली देखने को मिल रही है लेकिन 'इन महत्वपूर्ण परिणामों के बावजूद रोजगार के क्षितिज पर निराशा के बादल छाए हुए हैं।'

आईएलओ की इस रिपोर्ट के अनुसार, अगर मौजूदा नीतियां जारी रहती हैं तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार की स्थिति, आर्थिक मंदी के दौर से पहले वाले स्तर पर वर्ष 2015 तक पहुंचेगी। पिछले साल अनुमान लगाया गया था कि इन क्षेत्रों में वर्ष 2013 तक रोजगार की स्थिति पूर्ववत हो जाएगी। उभरते हुए और विकासशील देशों में मंदी से पहले की स्थिति को हासिल करने के लिए अब भी 80 लाख से अधिक नौकरियों की जरूरत है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रमशक्ति में मंदी जितने अधिक दिनों तक कायम रहेगी, नए रोजगार की तलाश करने वाले लोगों को उतनी अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिन 35 देशों के आंकड़े उपलब्ध हैं, वहां रोजगार की तलाश करने वाले लगभग 40 प्रतिशत लोग एक साल से भी अधिक समय से बेरोजगार हैं। नतीजतन, उनका हौसला टूट रहा है। उनका आत्मसम्मान घट रहा है जिसकी वजह से वे मानसिक रोगों का शिकार हो सकते हैं।

हाल ही में आईएलओ और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने एक सम्मेलन में अपील की है कि आर्थिक बहाली के केंद्र में रोजगार होना चाहिए और मुद्रा–स्फीति को कम करने और सुनियोजित वित्तीय नीतियों को लागू करने के साथ–साथ पूर्ण रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करने की बात को दोहराया गया है।

आईएलओ की यह रिपोर्ट मंदी के दौर से निकलने के लिए तीन स्तरीय पहल की बात कहती है। सबसे पहले रोजगार केंद्रित नीतियों को मजबूत किया जाना चाहिए जिससे लंबे समय तक बेरोजगारी बरकरार रहने की आशंका समाप्त हो। इन उपायों में संवेदनशील समूहों को समर्थन देने के उपाय करने, बहाली के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और रोजगार केंद्रित सामाजिक संरक्षण शामिल हैं। इन उपायों के माध्यम से श्रमिकों की भागीदारी और रोजगार की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहेगी। इनकी वजह से सरकारी व्यय कम होगा और अधिक राजस्व की उगाही होगी।

दूसरी पहल यह की जा सकती है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में वेतन और उत्पादकता लाभों के बीच की कड़ी को मजबूत किया जाए। इससे इन देशों और घाटे के शिकार देशों में लंबे समय के लिए रोजगार सृजन किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, इससे मुद्रा का अवमूल्यन नहीं करना पड़ेगा और विश्व अर्थव्यवस्था को संतुलित करना अधिक कारगर होगा।

तीसरी पहल... ऐसे वित्तीय सुधारों को लागू किया जाए जिनके तहत बचत को उत्पादक निवेश में लगाया जाए और अधिक स्थिर नौकरियों का सृजन किया जाए। ■

विश्वव्यापी रोजगार प्रवृतियां

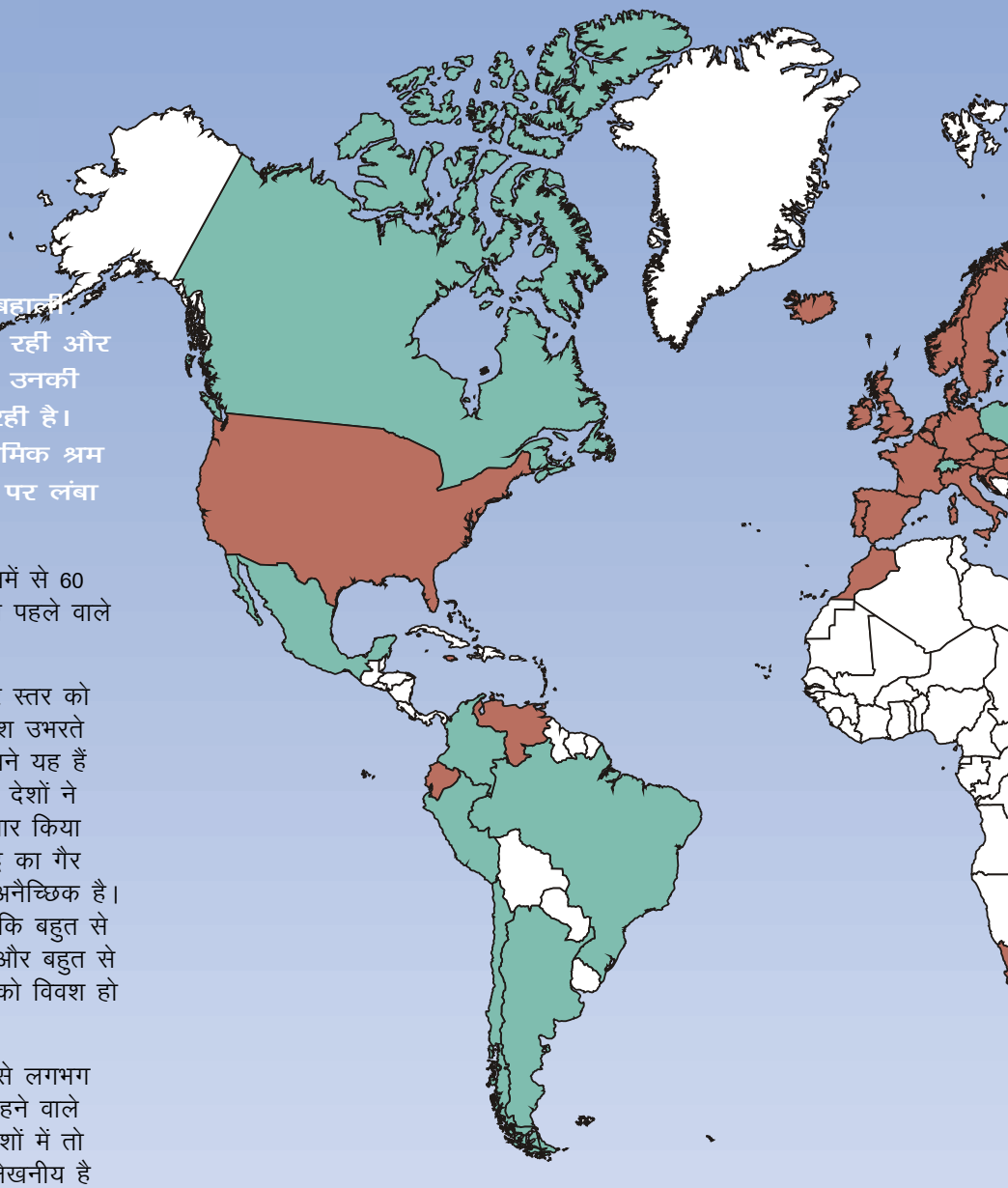

रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा आर्थिक बहाली पर्याप्त नौकरियों का सृजन नहीं कर रही और जिन नौकरियों का सृजन हो रहा है, उनकी गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई जा रही है। इस स्थिति से हतोत्साहित होकर, श्रमिक श्रम बाजार से हट रहे हैं। इसका युवाओं पर लंबा और घातक असर हो रहा है।

- जिन 68 देशों के आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से 60 प्रतिशत से अधिक देश आर्थिक संकट से पहले वाले रोजगार स्तर से नीचे हैं।
- जिन देशों ने संकट से पहले के रोजगार स्तर को पार कर लिया है, उनमें से दो तिहाई देश उभरते हुए और विकासशील देश हैं। इसके मायने यह हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले केवल नौ देशों ने संकट से पहले वाले रोजगार स्तर को पार किया है। इनमें से अनेक देशों में रोजगार वृद्धि का गैर अनुपातिक हिस्सा अल्पकालिक, अक्सर अनैच्छिक है। कुछ विकासशील देशों में स्थिति यह है कि बहुत से श्रमिक अपेक्षा से कम काम कर पाते हैं और बहुत से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने को विवश हो गए हैं।
- जिन देशों के आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से लगभग सभी देशों में एक साल तक बेरोजगार रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। कुछ देशों में तो यह वृद्धि बहुत अधिक है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जितने ज्यादा समय तक कोई श्रमिक बेरोजगार रहता है, उसकी श्रम बाजार से बाहर होने की

निम्न–मध्यम आय स्तर के देश

- अल्बानिया
- चीन*
- इक्वेडोर*
- मिस्र
- इंडोनेशिया
- मालदोवा गणराज्य
- मोरक्को
- फिलिपींस
- श्रीलंका
- थाईलैंड
- उक्रेन

उच्च मध्यम आय स्तर के देश

- अर्जेंटीना*
- बेलारूस
- ब्राजील*
- बुलगारिया
- चिली
- कोलंबिया
- जमैका
- कजाकिस्तान
- लातविया
- लिथुआनिया
- मकदूनिया, युगोस्लाव गणराज्य
- मलयेशिया
- मारीशस
- मैक्सिको
- पेरू*
- पोलैंड
- रोमानिया
- रूस गणराज्य
- सर्बिया
- दक्षिण अफ्रीका
- तुर्की
- वेनेजुएला, बोलीविया गणराज्य

संकट पूर्व रोजगार स्तरों के अनुसार विभिन्न देश

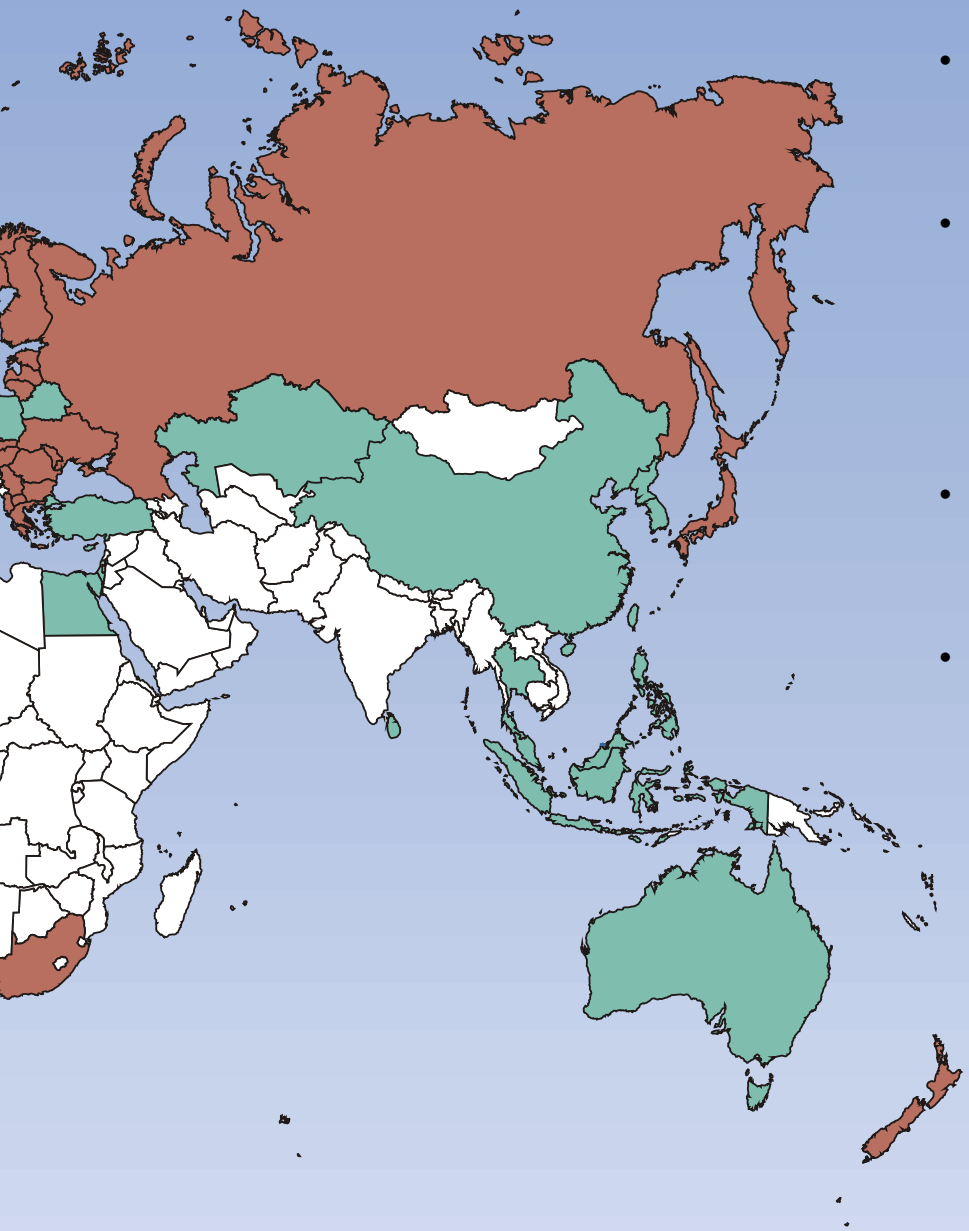

आशंका और अधिक बढ़ जाती है। अनेक देशों में यह प्रवृति लगातार देखने को मिल रही है।

- वर्ष 2010 के दौरान विकसित अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार वृद्धि स्थिर रही है और आर्थिक संकट से पहले के स्तर पर पहुंचने में अभी उसे पांच साल (वर्ष 2015) और लगेंगे।
- जिन उभरती हुए और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का विश्लेषण किया गया, वहां 'वी' आकार की बहाली की संभावना है। इन देशों में वर्ष 2010 की पहली छमाही में रोजगार वित्तीय संकट से पहले वाले स्तर पर पहुंच गया। उनके सामने चुनौती इस बात की है कि शुरुआती वर्षों के अतिरिक्त श्रमिकों और नए श्रमिकों को श्रम बाजार में किस प्रकार समाहित किया जाए।
- युवाओं पर वित्तीय संकट का गैर अनुपातिक रूप से असर हुआ। पहले के अनुभव बताते हैं कि मंदी से पहले के स्तर पर पहुंचने के लिए युवा बेरोजगारी को औसतन 11 वर्ष का समय लगता है।
- नीतिगत चुनौती यह है कि एक दीर्घकालीन और सबको सम्मिलित करने वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाए– एक ऐसी अर्थव्यवस्था का जो गुणवत्ता और मात्रा के लिहाज से समृद्ध हो। विश्लेषण बताते हैं कि जिन देशों ने रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी नीति अपनाई जो सबको साथ में लेकर चलती है, वे देश सबसे ज्यादा सफल रहे हैं। यह भी निर्णायक है कि ऐसी नीतियों को प्राथमिकता दी जाए जो लोगों को श्रम बाजार से हटने से रोके और उत्पादकता विरोधी समाधानों से बचे, जैसे खराब तरीके से तैयार किए गए श्रम बाजार सुधार। खराब तरीके से तैयार किए गए श्रम बाजार सुधार, बाजार में मंदी और सामाजिक असंतोष को बढ़ाते हैं (देखें अगला लेख)। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मांग और संतुलित वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास किया जाना आवश्यक है *(देखें लेख– बहाली के लिए योजना बनाना)*। ■

उच्च आय स्तर के देश

- ऑस्ट्रेलिया
- ऑस्ट्रिया
- बेल्जियम
- कनाडा
- क्रोएशिया
- साइप्रस
- चेक गणराज्य
- डेनमार्क
- इस्टोनिया
- फिनलैंड
- फ्रांस
- जर्मनी
- ग्रीस
- हंगरी
- आइसलैंड
- आयरलैंड
- इस्राइल
- इटली
- जापान
- कोरिया गणराज्य
- लक्समबर्ग
- माल्टा
- नीदरलैंड्स
- न्यूजीलैंड
- नार्वे
- पुर्तगाल
- सिंगापुर
- स्लोवाकिया
- स्लोवेनिया
- स्पेन
- स्वीडन
- स्विटजरलैंड
- त्रिनिदाद और टोबैगो
- युनाइटेड किंगडम
- युनाइटेड स्टेट्स

- संकट पूर्व स्तर से ऊपर
- संकट पूर्व स्तर से नीचे
- मालूम नहीं

*नोट्स : विश्लेषण हालिया उपलब्ध सूचना पर आधारित है। दिए गए आंकड़े कालानुसार समायोजित किए गए हैं। *चयनित शहरी आंकड़े*

स्रोत : आईआईएलएस आंकड़े, आईएलओ के अल्पावधि के इंडिकेटर डेटाबेस पर आधारित

© एम. क्रोजेट / आईएलओ

नौकरियों का घाटा

सामाजिक सुसंगति को खतरा

वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट 2010 **बताती है कि कम से कम 25 देश, जिनमें से बहुत से विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले हैं, वित्तीय और आर्थिक संकट से जुड़े सामाजिक असंतोष का शिकार हुए हैं। इन देशों में आय असमानता बढ़ने के साथ–साथ नौकरियां भी खतरे में पड़ रही हैं जिसके कारण सामाजिक सुसंगति खतरे में है। अमेरिका स्थित पत्रकार गैरी हंफ्रेज की एक रिपोर्ट।**

यूरोपीयन यूनियन ऑफ पब्लिक सर्विस यूनिट्स (ईपीएसयू) के प्रवक्ता विलेम गॉड्रियान को इस बात में कोई संदेह नहीं कि विश्वव्यापी वित्तीय और आर्थिक संकट के बाद यूरोपीय संघ के अनेक देशों में प्रस्तावित बचत कार्यक्रमों का असर समाज के सबसे संवेदनशील लोगों पर पड़ रहा है। गॉड्रियान कहते हैं, 'इन देशों की सरकारों ने सार्वजनिक व्यय कम किया है और सामाजिक हस्तांतरणों और लोक सेवाओं में कटौती की है। हालांकि यही वह दौर है जब यूरोपीय नागरिकों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।' उनकी अनुमान है कि यूरोपीय संघ के आठ करोड़ लोगों पर गरीबी का खतरा मंडरा रहा है।

इन देशों में निम्न आय वाले परिवार केवल वित्तीय मितव्ययता से ही प्रभावित नहीं हुए हैं। वे गैर अनुपातनिक रूप से भी प्रभावित हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आईएलओ) स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान (आईआईएलएस) के निदेशक और *वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट 2010* के रचनाकार रेमंड टोरेस कहते हैं, 'आय असमानताएं बढ़ी हैं। इसका असर वृद्धों और अकुशल श्रमिकों पर ही नहीं, युवाओं पर भी पड़ा है।' टोरेस के अनुसार, 'जिन देशों के आंकड़े उपलब्ध हैं, वहां युवा बेरोजगारी, वयस्कों के मुकाबले ढ़ाई गुना अधिक है।'

यहां यह उल्लेखनीय है कि फ्रांस में युवा लोगों ने बड़ी संख्या में पेंशन सुधारों के खिलाफ श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। फ्रांस की यूनियन फोर्स यूवेरे फंक्शनेयर्स की संघीय सचिव एने मेरी पेरेट कहती हैं कि अगर छात्र भी श्रमिकों के साथ–साथ सडकों पर उतर रहे हैं, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। 'हम जिस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें वह पसंद नहीं।' पेरेट श्रमिकों के संघर्ष को पेंशन से आगे का संघर्ष बताती हैं। वह कहती हैं, 'हमारे देश के युवा उस भविष्य के सपने नहीं देखते, जो उन्हें मिलने वाला है। कम से कम इस समय तो उन्हें जो भविष्य नजर आ रहा है, वह कोई आशा नहीं जगाता।'

© एम. क्रोजेट / आईएलओ

रेमंड टोरेस

असमानता की अवधारणा बिगाड़ रही है सामाजिक सुसंगति

आईएलओ के रिसर्च एनालिस्ट समीर खाटीवाड़ा मानते हैं कि असमानता की अवधारणा से सामाजिक सुसंगति को ज्यादा बड़ा खतरा है। वह कहते हैं, 'पिछले अनुभवों से पता चलता है कि सामाजिक असंतोष का बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी और आय असमानता का बढ़ना है।' मौजूदा संकट की एक विशेषता यह है कि विभिन्न देशों की सरकारें गरीबों की कीमत पर अमीरों को फायदा देने की कोशिश कर रही हैं। ईपीएसयू के गॉड्रियान कहते हैं, 'इस संकट के लिए जिम्मेदार बैंकों और बैंकरों को ही राहत के नाम पर अरबों–खरबों का फायदा पहुंचाया गया।' गॉड्रियान के अनुसार, यूरोपीय संघ में सामाजिक असमानता की शुरुआत नब्बे के दशक में ही हो गई थी। 'मुझे हैरानी है, तब लोगों ने अपना गुस्सा क्यों जाहिर नहीं किया?'

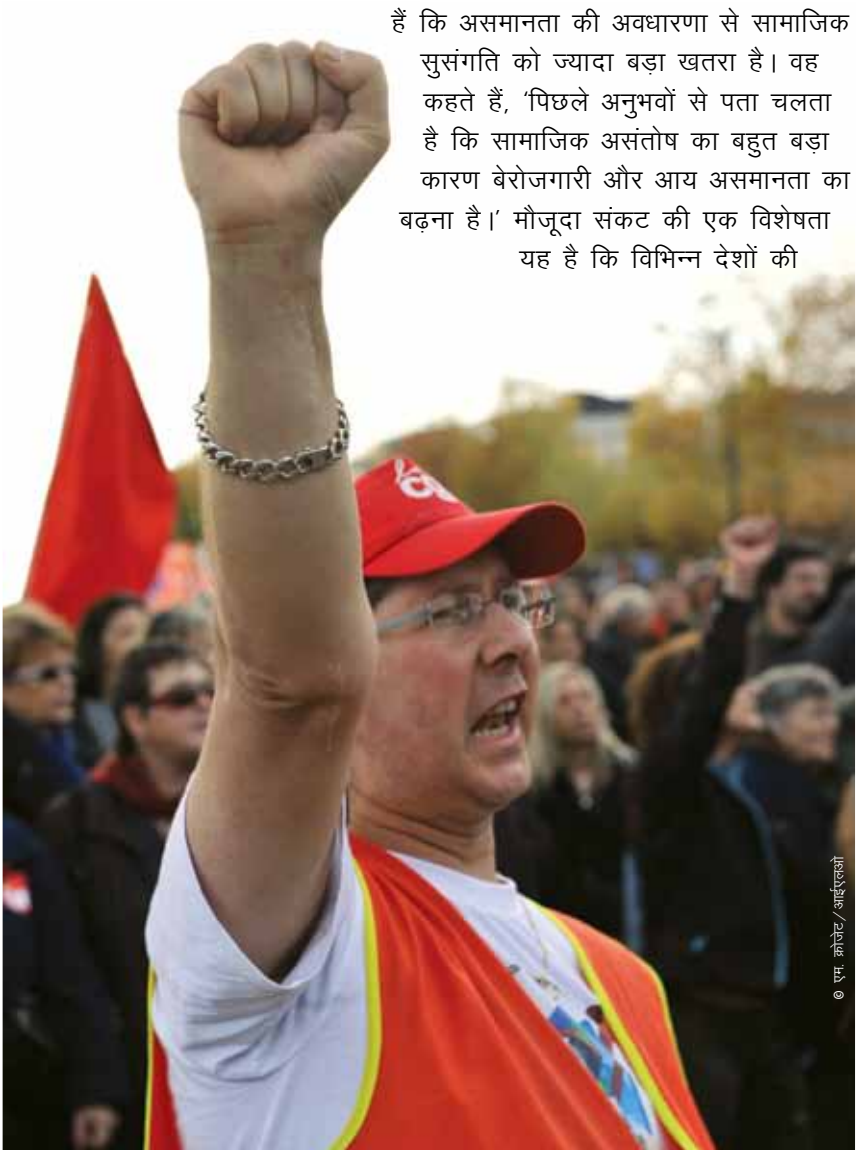

© एम. क्रोजेट / आईएलओ

इस समय सामाजिक असंतोष की सबसे स्वाभाविक और आसान अभिव्यक्ति औद्योगिक कार्रवाई है। खाटीवाड़ा के अनुसार, साल 2008 से ही बहुत से देशों (लगभग 25 देशों) में लोगों ने अपने गुस्से को जाहिर करना शुरू कर दिया था। इससे पहले लोग अपने देश की सरकारों के बचत कार्यक्रमों का बहुत अधिक विरोध नहीं करते थे। हालांकि वर्ष 2009 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन प्रारंभिक खबरों से पता चलता है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, जैसे चीन, भारत और लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में हड़ताल और तालाबंदी की घटनाओं में इजाफा हुआ है।

अमेरिका में, जहां से संकट की शुरुआत हुई, तनाव की शुरुआत तब हुई, जब सरकार ने बीमा संस्थानों और बैंकों को मदद देना आरंभ किया। तब लोगों को लगने लगा कि सरकार आम आदमी के बारे में नहीं सोच रही। उन्हें मदद नहीं दे रही। यह तनाव उस यादगार 'टी पार्टी' के बाद शुरू हुआ। इसके बाद स्वतंत्र सांसदों सहित कंजरवेटिव पार्टी के कुछ सांसदों ने अमेरिकी शहरों मे सरकारी राहत उपायों का विरोध करना शुरू किया। वे बुश प्रशासन के राहत उपायों का विरोध कर रहे थे और इस बात पर भी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि मौजूदा ओबामा सरकार ने भी उन उपायों को जारी रखा।

यूरोप में सामाजिक बुनावट खतरे में

इस समय यूरोप, खासकर पूर्वी और दक्षिणी यूरोप में सामाजिक संरचना सबसे ज्यादा दबाव में है। इस दशक की शुरुआत में पूर्वी यूरोप की जो अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं, वे सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं। खाटीवाड़ा लातविया का उदाहरण देते हैं। वह बताते हैं कि हाउसिंग के क्षेत्र में कीमतों के धराशायी होने और एक बहुत बड़े बैंक के दिवालिया होने के बाद लातविया की अर्थव्यवस्था बदहाल हो गई।

सितंबर में प्रकाशित आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2008 से वर्ष 2009 के दौरान लातविया की

आईएलओ के नए अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- लगभग 25 देशों में सामाजिक असंतोष के मामले सामने आए हैं जो वित्तीय संकट से संबंधित हैं। इनमें से अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं।
- जिन 82 देशों के आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से तीन चौथाई देशों के लोगों की अवधारणा पिछले तीन सालों में काफी बदली है। वर्ष 2006 की अपेक्षा वर्ष 2009 में जीवन की गुणवत्ता और उसके स्तर को लेकर लोगों की अवधारणा में गिरावट आई है। 83 देशों में से 46 देशों में रोजगार प्राप्त लोग भी अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं। उनमें यह भाव जग रहा है कि उनके साथ अन्याय किया जाता है।
- 72 देशों में से 36 देशों में लोगों का अपने देश की सरकार पर से भरोसा उठ रहा है। मंदी से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी।

अर्थव्यवस्था में 25 प्रतिशत की गिरावट आई। विश्व के किसी देश में इतनी ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई थी। जब लातविया को इस बात की आशंका हुई कि उसे आईएमएफ और ईयू की वित्तीय मदद भी नहीं मिलेगी तो वहां की सरकार ने अपने बजट में कटौती करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। यह कटौती देश की जीडीपी के 6.2 प्रतिशत के बराबर थी। इससे पहले लातविया के प्रधानमंत्री वालदिस डॉमब्रोविस्कस को अपने देश के लोगों का जबरदस्त विरोध देखना पड़ा था। सोवियत संघ से स्वतंत्र होने के बाद देश ने ऐसा विरोध प्रदर्शन पहली बार देखा था।

उधर ग्रीस की अर्थव्यवस्था भी गहरे संकट से जूझ रही थी। मई में आईएमएफ और ईयू के कुछ देशों के राहत पैकेज के चलते ग्रीस के लिए बड़ा उधार चुकाना संभव हो पाया था। 110 अरब यूरो की यह रकम ऋण के तौर पर तीन साल के लिए दी गई है। बदले में ग्रीस सरकार को कड़े आर्थिक कदम उठाने पड़े हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन में कटौती, पेंशन और सार्वजनिक क्षेत्र के वार्षिक बोनस– जो दो महीने के वेतन के बराबर होता है– को खत्म करना।

अक्टूबर की शुरुआत में ग्रीस के सरकारी कर्मचारियों ने सरकार का विरोध करते हुए 24 घंटे की हड़ताल की। इसके बावजूद कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों की छंटनी के संबंध में कोई घोषणा नहीं की थी। गौर करने की बात यह है कि ग्रीस में हर तीन में से एक श्रमिक सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता है। अक्टूबर में फिर हड़ताल हुई, इस बार ट्रेनों में। इसी बीच साल 2011 के लिए सरकार के बजट मसौदे में यह अनुमान जताया गया कि अगले साल बेरोजगारी बढ़कर 14.5 प्रतिशत हो जाएगी। साल 2010 में देश में बेरोजगारी का प्रतिशत 11.6 था। मसौदे में कहा गया कि इसके बाद यानी साल 2012 में बेरोजगारी बढ़कर 15 प्रतिशत हो सकती है।

ग्रीस की सामाजिक सुसंगति पर इसका क्या असर होगा, यह आने वाला समय बताएगा लेकिन लातविया ने दिखा दिया कि स्थिति को कैसे काबू में किया जा सकता है। वहां बचत उपायों के बावजूद प्रधानमंत्री वालदिस डॉमब्रोविस्कस अक्टूबर में पहले भी अधिक बहुमत से सत्ता में दोबारा लौटे।

नतीजे निकालना आसान नहीं

आईएलओ के खाटीवाड़ा कहते हैं कि लातविया में जो हुआ, उसे देखकर आप नहीं कह सकते कि मौजूदा आर्थिक परिदृश्य के सामाजिक परिणाम क्या होंगे? उनके अनुसार, समाज अनेक प्रकार की अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम अभी से यह नहीं कह सकते कि आने वाले सालों में क्या होने वाला है। दीर्घकालीन समाधान ढूंढने के लिए यह भी जरूरी नहीं कि हम प्रबंधन के किसी किताबी सूत्र को लागू करने बैठ जाएं। हम जिन स्थितियों का सामना कर रहे हैं, उनके विश्लेषण का आधार सिर्फ हड़ताल और तालबंदी से जुड़े आंकड़े नहीं होते। बेरोजगारी का दीर्घकालीन असर और सामाजिक सुसंगति पर बेरोजगारी का दीर्घकालीन असर जटिल होता है। यह जानना कि वह कितना असर करेगा, मुश्किल काम है।

दूसरी तरफ आईआईएलएस निदेशक टोरेस कहते हैं कि हमें इतिहास से सबक सीखना चाहिए। इससे पहले मंदी के चलते 40 प्रतिशत बेरोजगार लोग श्रम बाजार से बाहर निकल गए थे। इसके बाद इस बात की आशंका भी है कि वे हतोत्साहित होकर, श्रम बाजार से एकदम बाहर चले जाएंगे। इसका भी सामाजिक सुसंगति पर बहुत बुरा असर होगा। ■

सामाजिक सुसंगति : विश्व की एक तस्वीर

भले ही हर देश एक अलग तरह का उदाहरण पेश करता हो, उन उदाहरणों से एक संकेत तो मिलता ही है। विश्व के हर देश की प्रवृति अलग है पर वह प्रवृति क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेन्स यूनिट (ईआईयू) ने साल 2009 में इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए एक विश्वव्यापी जोखिम प्रबंधन किया। यूनिट ने इसके लिए सभी देशों को 0 से 4 की पायदान पर रखा। जिस देश को 0 की पायदान पर रखा गया, उस देश में सामाजिक असंतोष होने की सबसे कम आशंका थी, जबकि 4 की पायदान पर रखे जाने वाले देश में इस बात सबसे ज्यादा आशंका थी। इस विश्लेषण में साल 2008–09 के आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप होने वाले राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट में ज्यादातर देशों में सामाजिक असंतोष का खतरा मध्यम या उच्च दर्जे का बताया गया था। 179 देशों में 62 देशों में सामाजिक असंतोष का खतरा ज्यादा या बहुत ज्यादा था। जबकि 64 देशों में मध्यम दर्जे का खतरा बताया गया था।

जिन देशों के लोग अपने काम से सबसे कम संतुष्ट थे और जो अपनी सरकार पर सबसे कम भरोसा करते थे, उन्हीं देशों में सामाजिक असंतोष भड़कने का सबसे ज्यादा खतरा था। आय असमानता का सबसे ज्यादा शिकार देशों में भी सामाजिक तनाव की सबसे ज्यादा आशंका थी। हालांकि साल 2009 के आय असमानता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि संकट के दौर में आय असमानता बढ़ती है और इसकी शुरुआत होती है आय वितरण के सबसे निचले हिस्से में आने वाले लोगों से। आय असमानता को कम करने और सामाजिक परिवेश को बदतर होने से बचाने का एक ही उपाय होता है, श्रम बाजार के ऐसे कारगर उपाय और सामाजिक नीतियां, जो निम्न आय वाले परिवारों के लिए सुरक्षा कवच का काम करें।

© ज. रेबोलो / सीसीओओ

आर्थिक बहाली के लिए योजना निर्माण

किस प्रकार विश्वव्यापी वृद्धि और मांग को फिर संतुलित किया जाए

जैसे ही राहत उपायों की गति धीमी पड़ने लगी, बहुत से देशों की सरकारों ने कठोर आर्थिक कदम उठाने शुरू कर दिए। पर आईएलओ की रिपोर्ट (वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट 2010) कहती है कि ये दोनों तरीके काफी नहीं। इन दोनों उपायों से विश्वव्यापी आर्थिक अस्थिरता समाप्त होने वाली नहीं है। गैरी हंफ्रेज की एक रिपोर्ट।

आर्थिक संकट का अंत जल्दी आया लेकिन उसके प्रति प्रतिक्रिया भी बहुत जल्दी दिखाई देने लगी। सितंबर 2008 में लेहमैन ब्रदर्स के धराशाई होने के बाद जब बहुत से बड़े बैंकों पर ताले लगने शुरू हुए तो सेंट्रल बैंकों ने भारी सहयोग प्रदान किया। बैंकों ने ब्याज दरें कम की और ऋण गारंटी के साथ–साथ आर्थिक मदद भी की। कई बैंकों का राष्ट्रीकरण भी किया गया। यह एक महंगा सौदा था।

आईएलओ के अंतरराष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान के निदेशक रेमंड टोरेस के अनुसार, विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली को बेल आउट करने में अमेरिका और यूरोपीय संघ को 11.4 करोड़ खरब अमेरिकी डॉलर का खर्च करना पड़ा। यह विश्व की जीडीपी का एक बटा छह हिस्सा है।

जिस तरीके से बैंकिग क्षेत्र की मदद की गई, उसकी आलोचना पूरी दुनिया में की गई। ग्रीस के श्रमिक संघ एडैडी के अंतरराष्ट्रीय मामलों के महासचिव वसेर्लिस जेनाकिस के शब्दों में, 'बड़े बैंकों ने यह संकट पैदा किया और इसकी कीमत आम लोगों ने चुकाई।' लेकिन हाथ पर हाथ धरकर बैठने से भी काम नहीं चलने वाला था। बैंकिंग प्रणाली पर ताला लगाकर और विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था को भंवर में छोड़कर स्थिति और खराब होने वाली थी। टोरेस कहते हैं, 'अगर ये नीतियां न अपनाई जातीं तो विश्व अर्थव्यवस्था एक और महामंदी का शिकार होने वाली थी।'

© एम. क्रोजट / आईएसओ

© एम. क्रोजेट / आईएलओ

सरकारी सहायता सिर्फ बैंकों को नहीं दी गई थी। आईएलओ के आंकड़े कहते हैं, कई देशों ने टैक्सों में कटौती की और राहत उपाय पर सरकारी व्यय बढ़ाया। यह वर्ष 2009 की विश्वव्यापी जीडीपी का 1.7 प्रतिशत था। टोरेस संरक्षणवाद का सहारा लेने पर विभिन्न सरकारों की भत्सर्ना करते हैं। वह कहते हैं, 'व्यापार क्षेत्र महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए जो आर्थिक वृद्धि के लिए निर्यात पर निर्भर हैं।' वह संकेत देते हैं कि लगभग दो करोड़ नौकरियां नीतिगत प्रतिक्रिया के कारण बचाई जा सकीं,[1] जो कि बहुत मामलों में मांग को बढ़ाने पर केंद्रित थी। कई मामलों में इन प्रतिक्रियाओं के कारण आर्थिक संकट के सामाजिक असर को कम करना संभव हुआ।

प्रोत्साहन से मितव्ययता तक

पिछले कुछ समय में स्थितियों में बदलाव हुआ है, चूंकि विभिन्न देशों की सरकारों ने भी प्रोत्साहन पैकेजों की बजाय वित्तीय मितव्ययता की ओर ध्यान देना शुरू किया है। यह नीतिगत बदलाव बहुत जल्दी किया गया। 23 अप्रैल को जब जी 20 देशों के वित्त मंत्री वाशिंगटन में मिले, तब वे प्रोत्साहन पैकेजों की जरूरतों पर ही बातचीत कर रहे थे लेकिन 5 जून को जी 20 देशों का नजरिया बदल चुका था। तब ये देश वित्तीय दृढीकरण को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रहे थे।[2] इन दोनों तारीखों के बीच ग्रीस सार्वभौम ऋण (सोवेरिन डेट) की अदायगी न करने पाने की स्थिति में आ रहा था। ग्रीस की स्थिति से ही विश्वव्यापी नीतिगत बहस की दिशा बदल गई।

लेकिन क्या किया जाना उचित था? आईएलओ के एक रिसर्च एनालिस्ट एकेहार्ड अर्नेस्ट कहते हैं, 'सच्चाई यह है कि किसी भी सार्वभौम राज्य को बांड मार्केट से उधार लेना पड़ता है और इन सार्वभौम बांड के खरीदार यह जानना चाहते हैं कि उन्हें इस खरीद से फायदा होगा या नहीं।' अर्नेस्ट इस नीतिगत परिवर्तन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि एक देश की ऋण लेने की क्षमता, उसके खातों की स्थिति पर निर्भर करती है और खर्च में कटौती करने से उसकी ऋण लागत कम होती है। आईएमएफ और ईयू का समर्थन पाने के लिए ग्रीस यही करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मंदी से जूझने की कोशिश करने वाले किसी देश की व्यापक अर्थव्यवस्था पर इन प्रयासों का क्या असर पड़ेगा? उसके समाज पर इसका क्या असर होगा?

टोरेस के अनुसार, 'इस मितव्ययता से आर्थिक बहाली

[1] अंतरराष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान: वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट 2009: द ग्लोबल जॉब्स क्राइसिस एंड बियांड (जेनेवा, आईएलओ, 2009)

[2] जी 20 फाइनांस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स कम्यूनिक, बुसान, कोरिया गणराज्य, 5 जून 2010

कमजोर होगी।' टोरेस इशारा करते हैं कि इस मंदी का असर सबसे ज्यादा विकासशील देशों पर पड़ा है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं और लेहमैन ब्रदर्स के धराशाई होने के दो साल बाद भी दुनिया भर के कारखाने अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रहे।

ओईसीडी के खुद के अनुमानों के अनुसार, संगठन के ज्यादातर देशों में क्षमता और उत्पादन के बीच के अंतराल को भरने में वर्ष 2015 तक का समय लगेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यही वे देश हैं जो आर्थिक स्तर पर सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं– जिन्हें प्रोत्साहन की सबसे ज्यादा जरूरत है– और उन्हें पूंजी बाजार से धन उठाने के लिए सबसे ज्यादा कड़े उपाय करने पड़ रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों की छंटनी या कल्याण योजनाओं में कटौती से उपभोक्ता मांग कम होती है। इससे व्यापार क्षेत्र पर असर होता है, जोकि पहले से ही बैंक क्रेडिट के कारण कमजोर स्थिति में है (देखें अगला लेख)। लेकिन बांड जारी करने की संभावनाओं पर इसका अच्छा असर होता है।

कमजोर घरेलू मांग को देखते हुए बहुत से देशों की सरकारों ने निर्यात को मंदी से बाहर निकलने का साधन बनना शुरू कर दिया है। अमेरिका इसका हालिया उदाहरण है। जनवरी में राष्ट्रपति ओबामा ने निर्यात वृद्धि को अपने 'स्टेट ऑफ यूनियन' संदेश का मुख्य विषय बनाया और इस बात पर प्रतिबद्धता दर्शाई कि अगले पांच सालों में अमेरिकी निर्यात को दुगुना कर दिया जाएगा। इससे पहले भी इस तरह के उपाय का अच्छा असर हुआ था। स्वीडन और फिनलैंड ने नब्बे के दशक की शुरुआत में और कोरिया गणराज्य, मलयेशिया और थाईलैंड ने दशक के अंत में यही किया था।

लेकिन वर्ष 1999 के बाद विश्व का परिदृश्य बदल गया है, खासकर विकासशील देशों की मांगों के संदर्भ में। सच्चाई यह है कि कुछ वर्षों के दौरान अमेरिका विकसित देशों के मुकाबले उभरते हुए देशों को ज्यादा निर्यात कर रहा है और अगर वह अपना निर्यात बढ़ाना चाहता है तो उसे उन देशों, खासकर चीन में घरेलू मांग को बढ़ाना पड़ेगा। विदेशी मुद्रा विनिमय दरें भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और युआन के मूल्य को लेकर चीन और अमेरिका के बीच जारी बहस इस बात का संकेत है।

संकट से सबक

लेकिन क्या व्यापार संतुलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम संकट से सबक लेना भूल गए? आईएलओ के टोरेस ऐसा ही सोचते हैं। वह कहते हैं, 'निर्यात वृद्धि के विकल्प और आय असमानता के महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सोचने की भी जरूरत है। वह संकेत देते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में संपत्ति का असमान वितरण भी बढ़ता जा रहा है। यह विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था की अस्थिरता का बहुत बड़ा कारण है जिसने वर्ष 2008 के संकट को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिका में वर्ष 2000 से 2006 के बीच मध्यम वास्तविक वेतन में केवल 0.3 प्रतिशत वार्षिक की बढ़ोतरी हुई थी (जबकि वहां 2.5 प्रतिशत वार्षिक का उत्पादकता लाभ हुआ था), जबकि अमीरों को प्राप्त होने वाली आय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। टोरेस बताते हैं कि वर्ष 2003 से 2007 के दौरान अमेरिका के 15 सबसे बड़े कॉरपोरेशनों में एक्जीक्यूटिवों को होने वाला भुगतान, देश के औसत वेतन के संदर्भ में, 370 से 521 हो गया।

> "निर्यात वृद्धि के विकल्प और आय असमानता के महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सोचने की भी जरूरत है।"

वेतन में हुई इस गिरावट से विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, दोनों जगह कुल मांग में भी गिरावट हुई। लेकिन आयरलैंड, स्पेन, युनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे विकसित देशों में उधार लेने के सरल नियमों के कारण स्थिर वास्तविक वेतन वाले परिवारों ने भी उधार लेकर उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद जारी रखी।[3] कर्ज ही वह कारण था कि जिसकी वजह से अमेरिका में उधार लेने की सीमा तक घरेलू मांग बढ़ती रही। इसके बाद लोगों ने कर्ज चुकाना ही बंद कर दिया। ऐसी ही प्रवृति वृहद आर्थिक स्तर पर भी देखी गई। टोरेस कहते हैं: 'कुछ समय के लिए निर्यात आधारित उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे चीन ने दूसरे देशों को ऋण से उबरने में मदद की, लेकिन अंत में उधार लेने वाले देशों की ऋण चुकाने की क्षमता कमजोर साबित हुई।'

[3] इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज : *वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट 2008 : इनकम इनक्वालिटीज इन द एज ऑफ फाइनांशियल ग्लोबलाइजेशन* (जेनेवा, आईएलओ, 2008), जोसफ ई. स्टीग्लिट्ज : 'वॉल स्ट्रीट्ज टॉक्सिक मैसेज' (2009), रेमंड टोरेस : (अंतरराष्ट्रीय श्रम समीक्षा में लेख 2010)

श्रमिकों को उचित वेतन

अगर उत्पादकता लाभ के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी की जाती तो निम्न आय वर्ग वाले लोगों को समर्थन देने के लिए इनवर्क लाभ, नकारात्मक आय कर और ऐसी दूसरी नीतियों के साथ–साथ निजी ऋण या सरकारी सबसिडी की जरूरत नहीं पड़ती। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जी 20 देशों या विश्व व्यापार संगठन ने वेतन और उत्पादकता लाभ के बीच तालमेल बैठाने के मुद्दे पर कभी कोई चर्चा नहीं की। आर्थिक बहाली से जुड़ी किसी भी बहस के केंद्र में यह मुद्दा कभी नहीं रहा।

इस विषय पर भी बातचीत की जाए, इसके लिए श्रम बाजार संस्थानों को अपनी आवाज उठानी होगी। ऐसा नहीं है कि वे आवाज बुलंद नहीं कर रहे। हजारों लोगों ने एथेंस, मैड्रिड और पेरिस की सड़कों पर उतरकर अपनी बात कहने की हिम्मत दिखाई है। बचत कार्यक्रमों के नाम पर कल्याण योजनाओं को खत्म करने के विरोध में प्रदर्शन किए हैं। लेकिन उत्पादकता को वेतन से साथ जोड़ा जाए, इस विषय पर चर्चा करने की ज्यादा कोशिशें नहीं की गईं।

यह सीधी सी बात है। लोगों को उचित वेतन देने से विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था की अस्थिरता में कमी आएगी क्योंकि इससे कुल मांग में बढ़ोतरी होगी। इसका एक उदाहरण है, चीन का इंप्लॉयमेंट कांट्रैक्ट लॉ, जो साल 2008 में लागू किया गया था। इस कानून की मदद से श्रमिकों के अधिकार मजबूत हुए और वेतन बढ़ोतरी एवं काम की बेहतर स्थितियों के पेंट अप दबाव में कमी आई। इसका असर तेज गति से हुई आर्थिक वृद्धि में नजर आया।

इसके अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। मैकिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट के हाल के एक अध्ययन के अनुसार, चीन के सार्वजनिक पेंशन और स्वास्थ्य बीमा प्रणालियों के विस्तार से वर्ष 2025 तक चीनी जीडीपी में उपभोग का स्तर 0.2 प्रतिशत से बढकर 1.1 प्रतिशत हो जाएगा।[4] इससे घरेलू मांग बढ़ेगी और देश की आर्थिक वृद्धि होगी। इससे व्यापार क्षेत्र में चीन के सहयोगी देशों के लिए अवसरों में भी वृद्धि होगी।

वैसे व्यापार संतुलन उन अनेक समस्याओं में से एक है, जिनसे हम जूझ रहे हैं। आने वाले दशक में पश्चिमी यूरोप की श्रमशील आयु वाली जनसंख्या के प्रति वर्ष 0.3 प्रतिशत सिकुड़ने की आशंका है। जापान में यह आंकड़ा प्रति वर्ष 0.7 प्रतिशत का है। अमेरिका में भी, जहां जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक है, वहां भी श्रमशील आयु वाली जनसंख्या के विस्तार में 3 प्रतिशत की कमी आएगी, जो कि युद्ध पूर्व के औसत से एक तिहाई कम है।

इस स्थिति में, नौकरियों के लिए लोगों की प्रतिस्पर्धा कम होगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य योजनाओं पर अधिक दबाव पड़ेगा। प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाम बचत कार्यक्रम की बहस को बल मिलेगा। एडैडी के जेनाकिस के अनुसार, नीतिगत बहस में दूसरे मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। वह कहते हैं, 'हमें यह तय करना चाहिए कि हमें किस प्रकार का सामाजिक मॉडल चाहिए। नीतिगत बहस की शुरुआत इसी बात से होनी चाहिए।'

[4] मैकिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट : *बीटिंग द रिसेशन (2009)*

वित्तीय बाजार की बहाली : लुढ़कने की प्रवृति

वित्तीय क्षेत्र का निर्धारण

आईएलओ की हालिया *वर्ल्ड ऑफ वर्क* रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के सुधार पर भी चर्चा की गई है और यह भी बताया गया है कि ये सुधार किस प्रकार वास्तविक अर्थव्यवस्था–व्यापार, श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचा सकते हैं। संकट के मद्देनजर वित्तीय संस्थानों को भारी आर्थिक मदद के बावजूद अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी ऋण प्रवाह का परिणाम सामने आना बाकी है। और उससे भी बड़ी समस्याएं अभी सामने हैं, कहना है गैरी हंफ्रेज का। गैरी की एक रिपोर्ट।

यूके मैन्यूफैक्चरिंग की प्रतिनिधित्व इकाई ईईएफ के सीनियर इकोनॉमिस्ट जैगर कक्कड़ के लिए यह देखना तनाव भरा है कि किस प्रकार आर्थिक संकट के मद्देनजर बैंकों की उधारी धीरे–धीरे नियंत्रण मुक्त हो रही हैं। वह कहते हैं, 'बैंक अधिक से अधिक उधार दें, इस विषय पर लंबी चर्चा के बावजूद हमने यही पाया कि साल 2008 के बाद से ऋण की शर्तों या मात्रा में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया।' ईईएफ वर्ष 2007 की चौथी तिमाही से तिमाही आधार पर मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों के लिए ऋण की शर्तों का निरीक्षण कर रही है और हाल के सर्वेक्षण बताते हैं कि मैन्यूफैक्चरों के लिए उधारी के माहौल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है।

© सूरीना पाक

© एम. क्रोजेट / आईएलओ

अनेक विकासशील देश इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। आईएलओ के एक सीनियर इकोनॉमिस्ट एकाहार्ड अर्नेस्ट के अनुसार, 'वर्ष 2009 की दूसरी छमाही से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऋण संकुचन की शुरुआत हुई लेकिन साल 2010 की शुरुआत में भी धीमे होने के बावजूद यह प्रवृति समाप्त नहीं हुई।' हालांकि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों पर उस हद तक असर नहीं हुआ, चूंकि अर्नेस्ट के अनुसार, उन देशों के बैंकों और अमेरिकी बैंकों के बीच उतने मजबूत संबंध नहीं थे। अमेरिकी बैंक ही वे बैंक थे, जो सितंबर 2008 के आर्थिक संकट में धराशाई हुए थे।

विश्वव्यापी आर्थिक बहाली में निजी क्षेत्र के कामकाज के मद्देनजर, ऋण पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण समस्या है। यूके के फेडरेशन ऑफ स्मॉल बिजनेसेज के मुख्य प्रवक्ता स्टीफन आलमब्रिटिस के अनुसार, 'अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बैंक ऋण बहुत जरूरी है।' यह फेडरेशन स्वनियुक्त और छोटी कंपनियों के मालिकों का सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप है जो उनके हितों की रक्षा के लिए यूके में लगातार अभियान चला रहा है। 'अगर कंपनियों को ऋण नहीं मिलेगा तो वे समय पर निवेश नहीं कर पाएंगे। फिर लोगों को नौकरियों में रखने का काम भी आगे बढ़ जाएगा।'

सिर्फ बैंकों को दोष मत दें

लेकिन सिर्फ बैंकों को ही दोष देना ठीक नहीं। बीआईएस मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के प्रमुख और आर्थिक सलाहकार स्टीफन सेचेटी कहते हैं, 'ऋण मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है।' वह उपभोक्ताओं और कारोबारियों की इस प्रवृति की तरफ इशारा करते हैं कि वे संकट के मद्देनजर संचय करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ऋण चुकाने पर कम।

आईएमएफ के प्रकाश कन्नन भी इस बात का समर्थन करते हैं। हाल ही में कन्नन ने साल 1970 से अब तक 21 देशों में 83 बार आई मंदी पर एक अध्ययन प्रकाशित किया है। अध्ययन में उन्होंने बताया है कि वित्तीय संकट से पहले होने वाली मंदी में, 'सामान्य मंदी' की अपेक्षा ऋण वृद्धि कम हो जाती है। सामान्य मंदी में मांग अधिक तेजी से बढ़ती है।

संकट के मद्देनजर या नियमों के कारण मजबूर होकर बैंक अपनी बैंलेंस शीटों को दुरुस्त करने में लगे हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। जुलाई में अमेरिकी कांग्रेस ने वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए डॉड फ्रैंक ऐक्ट पारित किया है। ऐसा ही स्विट्जरलैंड में भी किया गया है। यहां सितंबर, 2010 में इंटरनेशनल बैंक रेगुलेटर्स की बेसल समिति ने तरलता और पूंजी से संबंधित नई शर्तों– बेसल–3 को मंजूरी दी है। बेसल 3 के अंतर्गत ग्लोबल बैंकों के पास अपनी जोखिमपरक परिसंपत्तियों के कम से कम 7 प्रतिशत के बराबर कॉमन इक्विटी होनी चाहिए। पहले यह 2 प्रतिशत ही था।

बेसल –3 पर मिली–जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मैरविन किंग के अनुसार, यह सिस्टमिक रिस्क की समस्या के साथ जुड़े अन्य मुद्दों को हल नहीं करती, जैसे इंटरबैंक मार्केट में पारदर्शिता का अभाव या उन बड़े बैंकों के लिए सुस्पष्ट सरकारी गारंटी जिनके दिवालियो होने की

आशंका कम है। दूसरी ओर, बैंकरों को इस बात की आशंका है कि बेसल– 3 उधारी पर रोक न लगा दे। इससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनांस (विश्व के सबसे बड़े कमर्शियल और इनवेस्टमेंट बैंकों का प्रतिनिधि)ने यह कहा था कि नियमों के कारण आने वाले पांच वर्षों में अमेरिका में वार्षिक आर्थिक वृद्धि 0.5 प्रतिशत तक, यूरोप में 0.9 प्रतिशत और जापान में 0.4 प्रतिशत सिकुड़ सकती है।

व्यवस्थागत कमियों को दूर करने के लिए कुछ प्रयास

डोड फ्रैंक और बेसल–3 के अतिरिक्त व्यवस्थागत कमियों को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए गए। उदाहरण के लिए टोरंटो में पिछले साल जून में हुई जी 20 देशों की बैठक में किसी कड़े नियम पर सफल बातचीत नहीं हो पाई और बैंकिंग करों के निर्धारण, जिससे यह क्षेत्र संकट के परिणामों के असर को कम कर सके, का भी विरोध किया गया। यूरोपीय आयोग भी बैंकिंग पर टैक्स लगाने का केवल मसौदा तैयार कर पाया। इस टैक्स का इस्तेमाल स्थिरता पूल को फंड करने के लिए किया जाएगा और यह वित्तीय बाजार की गतिविधियों को मजबूत करेगा।

इस बीच आईएमएफ सिर्फ कड़े नियमों का समर्थन कर रहा है। सुधारों पर उसका विरोध जारी है। आईएलओ के इकाहार्ड अर्नेस्ट कहते हैं, 'यूरोप में भी, जहां हम नियमों में रहकर काम करने के आदी हैं, सुधारों को छोटे मुद्दों तक सीमित रखा गया है, जैसे बोनस वेतन को सीमित या कम करने का कानून। बड़े मुद्दों जैसे यूरोपीय स्तर पर कुछ विशेष प्रकार के वित्तीय समन्वय को प्रतिबंधित करना, पर अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है।'

अर्नेस्ट के लिए विश्वव्यापी बैंकिंग प्रणाली की कमजोर स्थिति के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया का अभाव एक बड़ी समस्या है। वह कहते हैं, 'घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण सुधार करने बहुत जरूरी हैं। इसी प्रकार बैंकरों को विनियंत्रण मध्यस्थता में शामिल होने से रोका जा सकेगा।' बाजारों के अंतर्संबंध भी विश्वव्यापी विनियंत्रक संरचना का काम करते हैं।

अर्नेस्ट कहते हैं, 'यह सच्चाई कि किसी छोटे हाउसिंग उपक्षेत्र से उत्पन्न हुआ संकट इतने बड़े स्तर पर वित्तीय प्रणाली को धराशाई कर सकता है, उन लोगों के लिए चेतावनी है जो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उसे नियंत्रित करते हैं।' अर्नेस्ट के अनुसार, अगर इस प्रकार के जोखिम को रोकने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई नहीं की गई, जैसे बाजार गतिविधियों की अपारदर्शिता और वित्तीय क्षेत्र को अतिरिक्त जोखिम लेने के कारण राहत, तो हम आगे भी ऐसे संकट का सामना कर सकते हैं।

नैतिक जोखिम की भी समस्या

अर्थव्यवस्था में बिना कोई बड़ा सुधार किए बैंकों को वित्तीय सहायता देना, एक नैतिक जोखिम भी पैदा करता है। सरकार द्वारा इस प्रकार सहयोग देने का यह अर्थ भी होगा कि भविष्य में भी ये बैंक जोखिम उठाते रहेंगे।

अर्नेस्ट कहते हैं, 'जिन प्रस्तावों पर बातचीत की गई है, उनमें से सभी ऊपरी स्तर पर समस्या का समाधान करते हैं।' वित्तीय गतिविधियों पर टैक्स लगाने से कम से कम संकट के कुछ असर को तो कम किया जा सकता था और इस टैक्स से मिला राजस्व भविष्य के किसी संकट के लिए बफर की तरह काम करता। लेकिन ऐसे उपायों ने बड़ी समस्याओं को दूर करना शुरू नहीं किया।

और वे समस्याएं बहुत गहरी हैं– वे बैंकों के उद्देश्य और विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। रेमंड टोरेस कहते हैं, 'हम स्वयं से पूछते हैं कि बैंक किसलिए होते हैं। हम कहते हैं कि आज के लाभ कल का निवेश बनते हैं और उसके बाद नौकरियां का सा लाभ देते हैं। लेकिन सच्चाई में, बैंकिंग क्षेत्र के लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस व्यवस्था के भीतर ही रह जाता है। ये लाभ दिन पर दिन ज्यादा और बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं।' बेशक, संकट से पहले वित्तीय क्षेत्र का कुल कॉरपोरेट लाभ 42 प्रतिशत तक पहुंच चुका था, जो कि 1980 की शुरुआत में सिर्फ 25 प्रतिशत था।

बैंकर खुद भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी आत्मा में झांककर देखना चाहिए। द *इकोनॉमिस्ट* ने न्यूयार्क में फाइनांशियरों के लिए एक सभा की थी। उसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मैरविन किंग के भाषण से यह साफ जाहिर होता था। उन्होंने कहा था कि बैंकिंग को सुनियोजित करने के तमाम तरीकों में वह तरीका सबसे बदतर है जिसके तहत हम आज काम कर रहे हैं। हालांकि हमारा समुदाय इसे दुरुस्त करना चाहता है लेकिन कोई भी सुधार इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए कि दोषी को सजा मिलेगी– और यह कि जोखिम लेने से जिन लोगों को लाभ मिलता है, उन्हें भी परिणामों को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। ■

© एम. क्रोपेट / आईएलओ

युवा बेरोजगारी उच्चतम स्तर तक पहुंची

पिछले वर्ष 12 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष के मौके पर ही आईएलओ ने युवा रोजगार प्रवृतियों पर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि युवाओं की बेरोजगारी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है।

आईएलओ ग्लोबल इंप्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2010 नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 से 24 वर्ष के बीच के आर्थिक रूप से सक्रिय 62 करोड़ युवाओं में से 8 करोड़ 10 लाख साल 2009 के अंत तक बेरोजगार थे। यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। यह वर्ष 2007 में बेरोजगारों की कुल संख्या से 78 लाख अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, दो सालों में युवा बेरोजगारी दर में बहुत अधिक इजाफा हुआ। यह दर वर्ष 2007 में 19.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009 में 13.0 प्रतिशत हो गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन प्रवृतियों का युवाओं पर महत्वपूर्ण असर देखने को मिलेगा क्योंकि नए लोग पहले से बेरोजगार लोगों की स्थिति में पहुंच जाएंगे। रिपोर्ट में युवाओं की एक ऐसी लुप्त पीढ़ी का जिक्र किया गया है जो श्रम बाजार से गायब हो रही है क्योंकि उसने अच्छे जीवन की उम्मीद छोड़ दी है।

आईएलओ के अनुमान कहते हैं कि वर्ष 2010 में विश्वव्यापी युवा बेरोजगारी दर में वृद्धि जारी रहेगी। यह दर बढ़कर 13.1 प्रतिशत हो जाएगी। वर्ष 2011 में इसमें हल्की गिरावट आएगी और यह 12.7 प्रतिशत हो जाएगी। रिपोर्ट इस बात का संकेत भी देती है कि वयस्कों के मुकाबले युवाओं में बेरोजगारी दर, संकट के प्रति अधिक संवेदनशील साबित हुई है। इसीलिए वयस्कों के मुकाबले युवाओं के रोजगार को बहाल होने में भी समय लगेगा।

रिपोर्ट संकेत देती है कि विकसित और कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में युवाओं पर संकट के असर को केवल बढ़ती बेरोजगारी और सामाजिक जोखिमों के रूप में देखा गया। ये सामाजिक जोखिम हतोत्साहित होती नई पीढ़ी और निष्क्रियता से संबंधित थे।

आईएलओ रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों में, जहां 90 प्रतिशत युवा रहते हैं, युवा बेरोजगारी और अल्परोजगार के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। रिपोर्ट के अनुसार, निम्न आय वाले देशों में संकट का असर उन कुछ लोगों के काम के घंटे कम होने और कम वेतन के रूप में देखा गया जोकि भुगतान वाले और वैतनिक रोजगार में थे। एक असर यह भी देखने को मिला कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, जिसमें काम करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, के रोजगार में संवेदनशीलता भी बढ़ती गई।

रिपोर्ट अनुमान लगाती है कि विश्व के 15 करोड़ 20 लाख युवा या सभी युवा श्रमिकों का 28 प्रतिशत काम तो करता है लेकिन अत्यंत गरीबी में रहता है। उसका परिवार वर्ष 2008 में 1.25 अमेरिकी डॉलर प्रति दिन से भी कम पर जीवन व्यतीत करने को मजबूर था।

आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया के अनुसार, 'विकासशील देशों में संकट का असर गरीब लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर देखने को मिला। आर्थिक और वित्तीय संकट से पहले भी युवा लोग उत्कृष्ट श्रम से वंचित थे। संकट के बाद तो युवाओं की यह त्रासदी और बढ़ गई।' परिणाम के तौर पर श्रमशील गरीबी का शिकार युवाओं की संख्या बढ़ी है और इसका असर अगली पीढ़ी तक देखने को मिलेगा।

© एम. क्रोजेट / आईएलओ

रिपोर्ट कहती है कि इस संकट के चलते हमें ऐसी रणनीतियां बनाने की प्रेरणा मिलती है जो उस गंभीर समस्या का समाधान करे जिसका सामना युवा लोग श्रम बाजार में दाखिल होने के समय करते हैं। व्यापक और एकीकृत नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है जो शिक्षण और प्रशिक्षण नीतियों को युवाओं की रोजगार नीतियों से जोड़कर देखे।

ट्रेडिंग अपः व्यापार जगत ने नई पीढ़ी को दिया उद्यमिता का पाठ

© शेल लाइववायर

जैसे जैसे युवा बेरोजगारी का संकट बढ़ता जा रहा है, उद्यम जगत युवाओं को इस बात की प्रेरणा और मदद दे रहा है कि वे अपना व्यवसाय खुद शुरू करें। यहां ऐसे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिनमें युवाओं को अर्थव्यवस्था का भागीदार बनाने की कोशिश की जा रही है।

यूथ बिजनेस इंटरनेशनल (वाईबीआई)का गठन वर्ष 2000 में इंटरनेशनल बिजनेस लीडर्स फोरम के द्वारा किया गया था। अब यह समूह 38 देशों में काम करता है। शिक्षा और परामर्श पर बल देते हुए वाईबीआई नियमित रूप से उन लोगों के कारोबारी प्रस्तावों को आर्थिक सहायता भी देता है जिनके पास पूंजी का अभाव है। इकाई की वेबसाइट के अनुसार, उसके समूह ने वर्ष 2009 में 8500 से अधिक उद्यमियों को ऋण दिया था। समूह वर्ष 2020 तक हर साल एक लाख लोगों की मदद करना चाहता है।

कारोबार जगत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित उद्यमिता कार्यक्रमों के अलावा कुछ ऐसे कार्यक्रमों को भी सफलता मिली है जो कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित हैं। अप्रैल 2009 में गठित आईएलओ का **यूथ इंप्लॉयमेंट सपोर्ट जॉब्स फॉर द अनइंप्लॉयड एंड मार्जिनलाइज्ड यंग पीपुल** (येस जंप) ऐसा ही एक कार्यक्रम है। केन्या और जिम्बाब्वे में चलाए जाने वाले इस तकनीकी समन्वय कार्यक्रम को गरीबी कम करने के लिए तैयार किया गया है। इसे कूप अफ्रीका के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसका येस जंप कूप चैलेंज फंड इन दोनों देशों में अच्छे प्रस्तावों को मदद देता है। आईएलओ येस जंप की ही तरह के 29 तकनीकी समन्वय कार्यक्रम चला रहा है जिनका उद्देश्य युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इनमें से अनेक कार्यक्रम तभी शुरू किए गए जब वित्तीय संकट का प्रारंभ हुआ। ये कार्यक्रम शिक्षा, परामर्श और नेटवर्किंग सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ कार्यक्रम उद्यमों की इस बात में भी मदद करते हैं कि अपने शुरुआती दौर में वे प्रबंधन भी सीख लें। इससे नए उद्यमों के विफल होने की आशंका कम होती है।

वर्ष 1982 में शेल यूके लिमिटेड ने सामाजिक निवेश कार्यक्रम लाइववायर का गठन किया। इस कार्यक्रम को **शेल ऑयल** और क्षेत्रीय भागीदारों की आर्थिक सहायता प्राप्त है। यह एक प्रमुख कॉरपोरेट युवा उद्यमिता कार्यक्रम है जिसके तहत अफ्रीका, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में निशुल्क कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यह कार्यक्रम उद्यमिता से संबंधित शिक्षण–प्रशिक्षण देने के साथ–साथ कारोबार शुरू करने का परामर्श भी देता है। हाल ही में आईएलओ के एक वर्किंग पेपर में कहा गया था कि शेल लाइववायर ने एक लाख नए कारोबार शुरू करने में मदद की है जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक उद्यम के माध्यम से औसत 3 से 4 नई नौकरियों का सृजन हुआ है।

सामान्य लेख

पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़

नए जीवन और नई जीविका का सृजन

गांव मस्मा का शेर हसन मजबूर होकर बाढ़ के पानी को देख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिवाय इस बात के उसे अपने परिवार की जान बचानी है। बाढ़ का पानी उसके घर तक आ चुका था। डर और घबराहट में 24 साल के इस लड़के ने अपनी बूढ़ी मां, पांच बहनों और एक छोटे भाई को किसी तरह सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। वह आंसू भरी आंखों से अपने घर को देखता रहा, जो लगातार बाढ़ के पानी में डूब रहा था। सिर्फ एक घंटे के अंदर उसका घर दो मीटर खड़े पानी में कहां खो गया, उसे पता भी नहीं चला।

बाढ़ का पानी घटने में तीन दिन लगे। चौथे दिन शेर हसन ने देखा, उसका घर पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। उसके पड़ोसियों का भी यही हाल था। न सिर्फ घर, बल्कि घर का सारा सामान भी बर्बाद हो चुका था। शेर हसन की अम्मी ने उसकी बहनों के निकाह के लिए बड़ी मुश्किल से दहेज जमा किया था। पर अब तो कुछ भी नहीं बचा था।

पाकिस्तान के लिए बाढ़ कोई नई बात नहीं है। इस साल स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब रही। जुलाई और अगस्त के महीनों में, जो कि बारिश के महीने होते है– पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ आई। उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तुनखवा क्षेत्र में स्थित मस्मा उन अनेक गांवों में से एक था, जिन्हें विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। देश के सभी चार प्रांत बाढ़ से प्रभावित हुए। इसमें 1200 लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए।

© आईआरआईएन

आईएलओ का अनुमान है कि बाढ़ से कम से कम 18 लाख घर क्षतिग्रस्त हुए और 53 लाख लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोने पड़े या उनकी जीविका को खतरा हुआ। एशियाई विकास बैंक के अनुसार, पाकिस्तान में कृषि चक्र को सामान्य होने में दो साल का समय लगेगा।

बाढ़ के तत्काल बाद आईएलओ ने आंतरिक संसाधनों को लामबंद किया और पेशावर और नौशेरा जिलों में काम के बदले नकद रुपए दिए जाने का काम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत बाढ़ प्रभावित समुदायों को 3200 कार्यदिवसों की सुविधा दी गई। आईएलओ पुनर्निर्माण के लिए एक कार्यक्रम चलाता है जिसमें काम के बदले नकद राशि दी जाती है। इस कार्यक्रम का नाम कैश फॉर वर्क (सीएफडब्ल्यू)है और इसके तहत महिलाओं, पुरुषों और विकलांग लोगों की मदद की जाती है ताकि वे नष्ट हुए मकानों, सड़कें और काम करने वाली जगहों को फिर से बनाएं और इसके बदले नकद राशि भी पाएं।

आईएलओ के पाकिस्तान स्थित कंट्री ऑफिस के निदेशक डांगलिंग ली कहते हैं, 'प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए कैश फॉर वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम से न केवल प्रभावित लोगों को आय के अवसर उपलब्ध हुए बल्कि लोगो को अपना मकान बनाने, जीविका पाने का मौका मिला। ली के अनुसार, प्रारंभिक राहत अवधि के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को, जिनकी जीविका इस बाढ़ के कारण प्रभावित हुई थी, इकट्ठा करके, बेघर हुए लोगों के लिए बनाए गए टैंटों की सफाई करने और धुआं दिखाने का काम सौंपा गया।

आईएलओ संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए बाढ़ का पानी और मलबे को साफ किया गया, मकान दोबारा बनाए गए और सबसे ज्यादा प्रभावित समुदायों के बीच मच्छर मारने की दवा का छिडक़ाव किया गया। इसके बाद इन गतिविधियों को दूसरे जिलों में भी चलाया गया जिससे अनेक लोगों को अल्पावधि का रोजगार मिला। इस प्रारंभिक सफलता के चलते संगठन को अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैश फॉर वर्क गतिविधियां चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोऑरडिनेशन ऑफ ह्यूमैनेटेरियन अफेयर्स (ओसीएचए) ऑफिस की ओर से दो लाख अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं और पुरुषों के लिए 43,200 कार्यदिवस सृजित किए जाने का लक्ष्य था।

फिर बन गया शेर हसन के सपनों का घर

आईएलओ पाकिस्तान में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम भी चला रहा है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को पुनर्निर्माण के काम में दक्ष किया जा रहा है। आने वाले समय में इस काम की बहुत मांग होगी।

यह कार्यक्रम पेशावर, नौशेरा और चारसद्दा जैसे जिलों

© आईएलओ फोटो

में चलाया जा रहा है। इन जिलों में कार्यक्रम के तहत 300 युवा राजगीर, बढ़ईगिरी, वेल्डिंग और बिजली मरम्मत का काम सीख रहे हैं। इसके अलावा कनाडा सरकार की आर्थिक मदद से लैंगिक समानता और उत्कृष्ट रोजगार पर केंद्रित एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जो 1300 महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षित कर रहा है ताकि उन्हें भी काम करने का मौका मिले। आईएलओ एक मीडिया प्रॉजेक्ट (नार्वे सरकार के अनुदान से) भी चला रहा है। इसकी मदद से पाकिस्तानी मीडिया संगठन बाढ़ के कारण अगर बाल श्रम बढ़ता है तो उसे रोकने की कोशिश करेगा।

गौरतलब है कि कैश फॉर वर्क जैसे कार्यक्रम को आईएलओ संघटकों (सरकार, श्रमिक और नियोक्ता संगठनों) और नागरिक समाज के समूहों के माध्यम से लागू किया जाता है।

बड़े स्तर के इस राहत कार्यक्रम के अतिरिक्त, आईएलओ के स्थानीय और दूसरे देशों के कर्मचारियों की ओर से आर्थिक मदद भी की गई। संगठन ने इस राशि से रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीजें, खाना और दूसरी चीजें खरीदीं। इसके बाद उन चीजों को सुकर, पेशावर, नौशेरा और मुल्तान के सबसे ज्यादा प्रभावित समुदायों के बीच बांटा गया। इस मौके पर श्रम और मानव संसाधन के संघीय सचिव तारिक इकबाल पुरी, पाकिस्तान के नियोक्ता परिसंघ (ईएफपी) के अध्यक्ष हाजी मुहम्मद जावेद और पाकिस्तान के श्रमिक परिसंघ के महासचिव खुर्शीद अहमद मौजूद थे। ■

इस्लामाबाद में आईएलओ के कंट्री ऑफिस के सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर सैफुद्दीन चौधरी की पेशावर से रिपोर्ट

पिछले अगस्त में पाकिस्तान में आए भूकंप ने दो करोड़ लोगों को प्रभावित किया था। लाखों लोगों को अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा था। उन हालात में भी आईएलओ ने पाकिस्तान के स्थानीय प्रशासन की बहुत मदद की थी। संगठन ने सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में कई सफल कार्यक्रम चलाए थे। तब भी नौशेरा, पेशावर और सूकर जिलों में संरचनात्मक पुनर्निर्माण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कैश फॉर वर्क कार्यक्रम चलाए गए थे। इस कार्यक्रम की मदद से लोगों को अपना रोजगार वापस मिला और उन्हें सहारा मिला।

© एम. क्रोजेट / आईएलओ

ट्री ने दिया एक युवा को नया जीवन

© आईएलओ फोटो

ट्री यानी ट्रेनिंग फॉर रूरल इकोनॉमिक इंपावरमेंट आईएलओ का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने हमेशा अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं की मदद की है। कार्यक्रम यही प्रयास करता है कि अतिरिक्त आय हासिल करने के लिए लोगों में कौशल और क्षमता विकसित की जाए। प्रशिक्षण को समुदाय केंद्रित आर्थिक अवसरों से सीधे तरीके से जोड़ते हुए ट्री कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि जो कौशल प्रदान किया जा रहा है, वह प्रासंगिक हो। कोलंबो में आईएलओ के सीनियर ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट आर शिवप्रागसम की श्रीलंका पर केंद्रित एक रिपोर्ट।

17 साल का थंगावेल नादेसासीलन श्रीलंका के बट्टीकलोआ जिले के गांव पंचेनाई का रहने वाला है। जब वह दो साल का था, उसकी मां की मौत हो गई। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और सीलन, उसके दोस्त उसे इसी नाम से पुकारा करते हैं, और उसकी बड़ी बहन को रोता–बिलखता पीछे छोड़ गए। तब उसके नानी–नाना उसे अपने साथ ले गए। नानी–नाना के साथ वहां उनकी एक विधवा मौसी भी रहती थी।

सीलन ने गांव के स्कूल में आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की। फिर 14 साल की उम्र में वह काम पर लग गया। परिवार में कमाने वाला दूसरा कोई था भी नहीं। काम पर लगा, तो सीलन का स्कूल छूट गया।

चूंकि सीलन ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, इसलिए उसके लिए काम करने के अवसर भी सीमित थे। खेती के मौसम में सीलन धान के खेतों में काम करता और जब खेती का काम नहीं होता, तो वह सड़क बनाने का या जो काम उसे मिल जाता, वह काम करता। उसे हर हाल में अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना था। नानी की मौत के बाद सीलन पर और ज्यादा जिम्मेदारियां आ गईं क्योंकि उसके नाना बहुत बूढ़े थे और काम करने में असमर्थ थे। उसकी मौसी की आंखें भी इतनी कमजोर हो चली थीं कि उनके लिए भी काम करना मुश्किल था।

इन मुश्किलों के बावजूद सीलन ने किसी तरह अपनी बड़ी बहन की शादी की। अब घर पर उसके बूढ़े नाना, मौसी और वह खुद बचे थे।

वर्ष 2007 सीलन के लिए सबसे मुश्किल साल था। श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्र में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) और सरकारी सेना के बीच युद्ध भड़का। सीलन और उसके परिवार को अपना गांव छोड़कर पास के एक कैंप में आकर रहना पड़ा। उन्हें अपना सारा सामान घर पर ही छोड़कर आना पड़ा। जब वे अपने गांव वापस लौटे तो उनके पास जमीन के एक कोरे टुकड़े के अलावा कुछ नहीं बचा था। इसलिए सीलन को एक बार अपने और अपने परिवार के जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा। सरकारी और दूसरे मानवाधिकार संगठनों की मदद से किसी तरह उसने अपनी झोपड़ी फिर से बनाई और अकुशल श्रमिक के तौर पर फिर से काम करना शुरू किया।

सीलन की जिंदगी में आशा की किरण तब आई जब जुलाई 2009 को बट्टीकलोआ जिले में रिकवरी कोऑरडिनेशन इनीशिएटिव (आरसीआई) के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस चरण में चुने गए छह गांवों मे से एक गांव सीलन का भी था। सभी गांवों में संभावित रोजगार क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि इन क्षेत्रों में कृषि मशीनरी और मोटरसाइलिक रिपेयर के मैकेनिकों की मांग है। इसलिए इन गांवों के युवाओं के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि वे इस काम का प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। सेंट जॉन्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी की मदद से यह प्रशिक्षण दिया जाना था।

रिकवरी कोऑरडिनेशन इनीशिएटिव (आरसीआई)– चरण II एक संयुक्त प्रयास है। इस कार्यक्रम को लागू करने का दायित्व आईएलओ, फूड एंड एंग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ) और युनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) का है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (डब्ल्यूएफपी), युनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड (यूनिसेफ) और युनाइटेड नेशंस हाई कमीश्नर फॉर रिफ्यूजीस (यूएनएचसीआर) अनुपूरक भूमिका निभाते हैं। ये तीनों संगठन पुनर्वासित समुदायों (रीसेटेल्ड कम्यूनिटीज) के पुनर्वास में मदद देते हैं और उन्हें खाना उपलब्ध कराते हैं। आईएलओ की एक जिम्मेदारी यह भी है कि इन समुदायों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास प्रदान किया जाए। इसीलिए संगठन ने आर्थिक सशक्तीकरण के लिए समुदाय आधारित प्रशिक्षण (ट्री) कार्यक्रम का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और जीविका तलाशने में लोगों की मदद की।

पंचनेई से जिन सात युवाओं को प्रशिक्षण के लिए चुना गया, उनमें से एक सीलन भी था। प्रारंभ में समूह चर्चा में यह तय किया गया कि वे किस प्रकार आसानी से प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। ज्यादातर युवाओं की समस्या यही थी कि वे अपना परिवार छोड़कर कैसे प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वही अपने परिवार के कमाऊ सदस्य थे। दूसरी समस्या यह थी कि उन्हें रोजाना अपने घर से प्रशिक्षण केन्द्र तक आना पड़ता। इन बातों का ध्यान रखते हुए आईएलओ ने तय किया कि उनके लिए बट्टीकलोआ में सेंट जॉन्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में तीन महीने के आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भर्ती किया जाए।

> “सीलन को उम्मीद है कि नए कौशल और प्रशिक्षण की बदौलत एक दिन उसके सारे सपने सच होंगे”

आईएलओ ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (डब्ल्यूएफपी) के साथ प्रशिक्षुओं के लिए फूड फॉर ट्रेनिंग कार्यक्रम का प्रबंध भी किया। इससे वे आसानी से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और डब्ल्यूएफपी उनके परिवारों की देखभाल करे। बट्टीकलोआ स्थित डब्ल्यूएफपी के फील्ड ऑफिस ने इस प्रस्ताव पर प्रसन्नता जाहिर की और प्रशिक्षण अवधि के दौरान सभी प्रशिक्षुओं के परिवारों को सूखा राशन दिया। इसके अलावा यूएनडीपी बट्टीकलोआ ने इस कार्यक्रम के लिए सभी तरह की लॉजिस्टिक मदद की। आईएलओ ने प्रशिक्षुओं को आर्थिक मदद देने के साथ–साथ नैतिक सहयोग भी दिया। संगठन नियमित रूप से प्रशिक्षुओं के कामकाज पर नजर रखता और उन्हें प्रोत्साहित करता।

तीन महीने के संस्थागत प्रशिक्षण और दो महीने के ऑन जॉब प्रशिक्षण के बाद सीलन सहित 15 युवक कृषि मशीनरी मैकेनिक बन गए। अब सीलन उसी वर्कशॉप में काम करता है जहां उसने प्रशिक्षण हासिल किया था।

आरसीआई – चरण II के तहत आईएलओ ने 170 युवतियों और युवकों को कृषि मशीनरी की मरम्मत, मोटरसाइकिल की मरम्मत, भारी उपकरण चलाने, दर्जीगिरी, बढ़ईगिरी, राजगीरी, ट्रैक्टर चलाने और इलैक्ट्रिकल वायरिंग का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके बाद वैतनिक रोजगार तलाशने या समूह उद्यम शुरू करने के काम में आईएलओ ने उन सभी की मदद की। इसके अतिरिक्त आईएलओ ने 140

महिलाओं की सहायता की ताकि वे कौशल हासिल कर सकें। फिर उन्हें उपकरण, औजार और काम करने की जगह भी मुहैय्या कराई और संचालन संबंधी सहायता दी जिससे वे समुदाय आधारित लघु उद्यम शुरू कर सकें। इसके तहत 14 समूह उद्यम, जिसमें एक ग्रुफ फार्म भी है, गठित हुए।

सीलन का सपना है कि वह बट्टीकलोआ जिले का सबसे अच्छा कृषि मशीनरी मैकेनिक बने और एक दिन अपनी खुद की वर्कशॉप चलाए। वह अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाना चाहता है जहां उसके नाना और मौसी आराम से रहें। वह अपनी शादीशुदा बहन के परिवार की भी मदद करना चाहता है। दूसरे सभी युवाओं की तरह वह भी चाहता है कि एक दिन खुद की मोटरसाइकिल पर सैर करे। उसे यकीन है कि जो काम उसने सीखा है, उस काम की बदौलत एक दिन उसके सारे सपने सच होंगे। ■

द ट्रेनिंग फॉर रूरल इकोनॉमिक इंपावरमेंट (ट्री) प्रोग्राम

ग्रामीण स्तर पर आर्थिक सशक्तीकरण के लिए आईएलओ ट्री कार्यक्रम संचालित करता है। इस कार्यक्रम को सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के मौजूदा रोजगार सृजन कार्यक्रमों को मजबूत करने और असरकारक बनाने के लिए तैयार किया गया है। ट्री कार्यक्रम के तहत उन अंतरालों को भरा भी जाता है, जहां मौजूदा कार्यक्रम या तो खराब स्थिति में चलाए जा रहे हैं या फिर वे कागजी हैं– यानी उन्हें चलाया ही नहीं जा रहा। आईएलओ का यह कार्यक्रम रोजगार और आय सृजन के समुदाय आधारित प्रशिक्षण की आईएलओ पद्धति पर आधारित है।

हाल ही में विश्व के कई देशों, जैसे बांग्लादेश, बुर्किना फासो, मैडागास्कर, नाइजर, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका के तकनीकी समन्वय कार्यक्रमों के साथ ट्री कार्यक्रम को संलग्न किया गया। यह कार्यक्रम विश्व स्तर पर समुदाय आधारित प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के आईएलओ के लंबे अनुभव पर आधारित है। इस कार्यक्रम के तहत शुरुआत में संस्थागत प्रबंधन किया जाता है और फिर राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर के संगठनों के साथ योजना बनाई जाती है। ट्री कार्यक्रम सामुदायिक स्तर पर सुव्यवस्थित तरीके से रोजगार और आय उत्सर्जित करने के अवसरों को चिन्हित करता है, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने वाली सरकारी और निजी संस्थाओं के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता और उन्हें लागू करता है, और प्रशिक्षण के बाद बाजार तक पहुंच बनाने और ऋण लेने में आदि में मदद करता है।

सुदूर ग्रामीण इलाकों में औपचारिक प्रशिक्षण संस्थान मौजूद नहीं होते। ऐसी जगहों पर मोबाइल ट्रेनिंग का प्रबंध किया जा सकता है। इस प्रकार उपयुक्त प्रशिक्षण को चिन्हित करने के लिए शिक्षकों और उपकरणों का प्रबंध किया जा सकेगा। पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकेगा और स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इस तरह की पहल से अनौपचारिक संस्थानों को मजबूती मिलेगी और स्थानीय मांग के अनुसार नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकसित किया जा सकेगा।

© आईएलओ फोटो

स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति डोरिस ल्यूटहार्ड को इस बात की आशा है कि स्कोर इंडोनेशिया के अलावा दूसरे देशों के एसएमई के लिए भी उदाहरण पेश करेगा।

स्कोर को बरकरार रखने के लिए छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों को सहायता

विश्व की 95 प्रतिशत श्रमशील जनसंख्या को रोजगार देने वाले छोटे और मध्यम स्तर के उद्यम (एसएमई) विकासशील देशों में रोजगार का मुख्य साधन हैं। इन उद्यमों पर भी आर्थिक संकट का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। छोटे और मध्यम स्तर के उद्यम (एसएमई) अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धात्मक बनें, इसलिए आईएलओ ने अनेक देशों में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी : कंपीटीटिव एंड रिस्पांसिबल इंटरप्राइज (स्कोर)। फिलहाल चीन, कोलंबिया, घाना, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम में स्कोर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आईएलओ की कम्यूनिकेशन ऑफिसर गीता एफ. लिंगा की एक रिपोर्ट।

जकार्ता की ऑटो पार्ट कंपनी पीटी लक्समाना तेकनिक माकमूर में अब काम का माहौल बदल चुका है। काम करने की जगहें साफ सुथरी हैं। न तो अब वहां पेंट की धूल रहती है और न ही ऑटो पार्ट्स और औजार बिखरे पड़े रहते हैं– उन्हें बड़े स्टोरेज रैक में अच्छी तरह से रखा जाता है। यहां से उन्हें ढूंढना और रिकॉर्ड रखना अब बहुत आसान है।

कंपनी के निदेशक एच. सुवर्णो कहते हैं, 'पहले हमें हाइजीनिक उत्पादन के बारे में नहीं पता था। हमारे कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, खुले में ही पेंट करते थे। इससे पेंट की धूल सारे वातावरण को विषाक्त करती थी। इसका असर कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर पड़ता था। हमने अपने उत्पादों और औजारों को रखने के लिए स्टोरेज रैक का इस्तेमाल करने को कभी महत्व नहीं दिया था। सब सामान यूं ही बिखरा पड़ा रहता था।'

स्कोर कार्यक्रम का अंग बनने के बाद पीटी लक्समाना तेकनिक माकमूर कंपनी का माहौल बदल गया। सुवर्णो कहते हैं, 'अब हमारे कर्मचारी पेंट करने का काम पेंट बूथ में करते हैं जिससे माहौल और दूसरे कर्मचारी सुरक्षित रहें। हम हाइजीनिक उत्पादकता की प्रक्रिया का हिस्सा भी बन रहे हैं।'

अब श्रमिकों और प्रबंधन के बीच संवाद भी सहज हुआ है। सुवर्णो के अनुसार, 'पहले श्रमिकों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि कंपनी के लक्ष्य क्या हैं, जबकि प्रबंधन श्रमिकों की जरूरतों के बारे में नहीं जानता था। अब सब कुछ बदल गया है। हम आपस में अच्छी तरह से बातचीत करते हैं जिसका असर उत्पादकता पर साफ नजर आता है।'

कार्यगत परिवेश में बदलाव करने से सिर्फ प्रबंधन को लाभ नहीं होता– श्रमिकों को भी लगता है कि इससे

उनका काम आसान, तेज और अधिक कारगर हुआ है। कंपनी के एक कर्मचारी अगुंग नुग्राहा के अनुसार, 'अब हमें सभी सामान वक्त पर मिल जाता है, हमें सामान गिनने में आसानी होती है और इनवेंट्री को कंट्रोल करना आसान हो गया है।'

पीटी लक्समाना तेकनिक माकमूर कंपनी को जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, छोटे और मध्यम स्तर के दूसरे उद्यम (एसएमई) भी उन्हीं समस्याओं का सामना करते हैं। इंडोनेशिया सहित सभी विकासशील देशों में ये समस्याएं आम हैं। उन्हें दूसरी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा तो करनी ही पड़ती है, आस–पास के माहौल और स्थानीय कानूनों का दबाव भी झेलना पड़ता हैः उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक और उत्पादक, दोनों बनना पड़ता है और पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन भी करना होता है। ये उद्यम बाहरी आघातों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उन पर साल 2008 के वित्तीय संकट का बहुत बुरा असर हुआ है जिससे काम की उनकी गुणवत्ता खतरे में पड़ गई है।

आईएलओ की मेजबानी करने के लिए इंडोनेशिया को चुना गया क्योंकि यहां छोटे और मध्यम स्तर के उद्यम बहुत बड़ी संख्या में हैं। इनमें से अनेक को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सुधार की जरूरत है। इंडोनेशिया में स्कोर कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2010 में की गई। इस कार्यक्रम को स्विस स्टेट सेकेटेरियट फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स (सेको) और नार्वेइन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन (नोरद) की संयुक्त आर्थिक मदद से शुरू किया है। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाना, उनकी काम करने की स्थितियों में सुधार करना, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच सहयोग और संवाद को मजबूत करने का है। कार्यक्रम यह कोशिश भी करेगा कि ये उद्यम पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप काम करें। इस प्रकार उद्यम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक उत्पादक होंगे और रोजगार का सृजन होगा।

उत्पादकता केवल तकनीकी विषय नहीं

जैसा कि स्विटजरलैंड की राष्ट्रपति डोरिस ल्यूटहार्ड कहती हैं, 'किसी कारोबार की उत्पादकता में सुधार करना, केवल नई तकनीक या क्रांतिकारी उत्पादक पद्धतियों का मसला नहीं है।' इसे महिलाओं और पुरुषों, यानी श्रमशक्ति की पूर्ण और व्यापक भागीदारी और कंपनी से उनके संवाद के माध्यम से भी लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति डोरिस ल्यूटहार्ड ने इंडोनेशिया में प्रॉजेक्ट की शुरुआत करते हुए अपने भाषण में यह कहा और इस बात की आशा जताई कि स्कोर इंडोनेशिया देश के तथा दूसरे देशों के एसएमई के लिए भी उदाहरण पेश करेगा।

इस अवसर पर इंडोनेशिया के मैनपावर और ट्रांसमाइग्रेशन मंत्री मुहाइमिन इसकंदर ने कहा कि स्कोर इंडोनेशिया मैनपावर मंत्रालय के स्ट्रैटेजिक वर्किंग प्लान को भी निश्चित रूप से समर्थन देगा और उत्कृष्ट श्रम के लिए रोजगार अवसरों का सृजन करेगा। उन्होंने कहा, 'इस कार्यक्रम के माध्यम से औद्योगिक संबंधों में सुधार और श्रम योग्यता एवं उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।'

स्कोर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दो दिवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण मॉड्यूल के अंतर्गत आने वाले उद्यम में तीन साइट विजिट शामिल हैं। प्रशिक्षण स्कोर के विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है। इस कार्यक्रम में पांच मॉड्यूल आते हैं जिनके अंतर्गत आने वाले विषय हैं–कार्यगत समन्वय, गुणवत्ता, उत्पादकता और स्वच्छ उत्पादन, मानव संसाधन प्रबंधन और सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यगत परिवेश।

अब तक छोटे और मध्यम दर्जे के 11 उद्यमों ने, जो एस्ट्रा ग्रुप के नेटवर्क को अपने उत्पादों की सप्लाई करते हैं, स्वयं को पंजीकृत करते हुए स्कोर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा जाहिर की है। ये भी उन अंतिम लाभार्थियों के साथ पंक्तिबद्ध हैं– छोटे और मध्यम स्तर के ऑटो पार्ट मैन्यूफैक्चरों के श्रमिक और नियोक्ता, जिनमें 50 से 200 कर्मचारी तक आते हैं।

इंडोनेशिया के नियोक्ता संगठन (एपीइंडो) के अध्यक्ष सोफजान वानंदी इस कार्यक्रम का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं, 'स्कोर कार्यक्रम इंडोनेशिया के छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा।' इन उद्यमों को इस मदद की बहुत जरूरत है क्योंकि उन्हें उत्पादकता, योग्यता और प्रतिस्पर्धात्मकता की जरूरत है, साथ ही नियोक्ता और श्रमिकों के बीच सहयोग की जरूरत है जिससे काम का माहौल अच्छा हो।

इसी प्रकार इंडोनेशियाई यूनियन कनफेडरेशन भी इस कार्यक्रम का स्वागत करता है। कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडोनेशिया ट्रेड यूनियंस (केएसपीएसआई) के अध्यक्ष सजुकूर सर्तो के अनुसार, 'स्कोर कार्यक्रम नियोक्ताओं और श्रमिकों, दोनों के हितों की रक्षा करता है। मेरा मानना है कि श्रम उत्पादकता बढ़ने से कंपनी की उत्पादकता बढ़ेगी और राष्ट्रीय उत्पादकता में इजाफा होगा।'

ऑटो पार्ट कंपनी सीवी मित्रकर्सा के निदेशक यायात सुप्रियत्न कार्यस्थलीय सुरक्षा और स्वास्थ्य के महत्व

> **"किसी कारोबार की उत्पादकता में सुधार करना, केवल नई तकनीक या क्रांतिकारी उत्पादक पद्धतियों का मसला नहीं है।"**

पर बल देते हैं। उन्होने भी अपनी कंपनी को स्कोर कार्यक्रम के तहत पंजीकृत किया है। उनके अनुसार, 'हम श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी बहुत कम लेते थे। इसी कारण हमारा एक श्रमिक दुर्घटना का शिकार हो गया। पर स्कोर ने हमारे कारोबार करने के तरीके को बदल दिया है। हम अब पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं, अपने श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति भी। हमने अपने श्रमिकों को दस्ताने, मास्क और जूते जैसे सेफ्टी उपकरण दिए हैं।'

उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा और उत्तरदायित्वपूर्ण काम करने के तरीकों के बारे में अधिक जानकारी और जागरूकता से छोटे और मंझोले उद्यमों को अपने कारोबार में वृद्धि करने, गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही एक ऐसी कारोबारी संस्कृति को विकसित करने में सहायता मिलेगी जो कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सामंजस्य बढ़ाएगा और कार्यस्थलीय प्रबंधन को दुरुस्त करेगा जिससे काम के दौरान होने वाले हादसों और बीमारी अवकाश की संख्या कम हों। ■

© आईएलओ फोटो

सस्टेनेबिलिटी थ्रू कंपीटीटिव एंड रिस्पांसिबल इंटरप्राइज (स्कोर)

आईएलओ कार्यक्रम स्कोर छोटे और मंझोले उद्यमों (एसएमई) को समर्थन देता है जिससे वे अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करते हुए अधिक और बेहतर अवसरों का सृजन कर सकें। इस कार्यक्रम से इन उद्यमों को कई प्रकार के लाभ होते हैं जैसे उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार होता है। उनके कर्मचारी स्वस्थ और प्रतिबद्ध होते हैं। उन्हें स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तर के बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलती है। श्रमिकों के लिए इसका अर्थ यह होता है कि उन्हें अधिक उत्पादक और उत्कृष्ट श्रम और ऐसे कार्यस्थलों पर काम करने के अवसर मिलते हैं जो राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल होते हैं। स्थानीय संगठन और कारोबारी संगठन श्रमिकों और प्रबंधकों के लिए अल्पावधि का प्रशिक्षण सत्र चलाते हैं और उन्हें दूसरी कंपनियों में दौरे के मौके दिए जाते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत उद्यमों की विशिष्ट जरूरतों के संबंध में उन्हें परामर्श भी दिया जाता है। यह कार्यक्रम उन उद्यमों के लिए खास तौर से प्रासंगिक है जिन्हें गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रदूषण और कचरे, कार्यस्थलीय स्वास्थ्य और सुरक्षा, या मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अगर आपको स्कोर कार्यक्रम के बारे अधिक जानकारी चाहिए तो निम्नलिखित वेबसाइट देखें www.ilo.org/score.

निर्माण क्षेत्र में हरित रोजगार

छोटा बदलाव – बड़ा असर

आईएलओ के हरित रोजगार कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था के जिन विशिष्ट क्षेत्रों को महत्व दिया गया है, उनमें से एक निर्माण क्षेत्र भी है। विश्व का 25 से 40 प्रतिशत ऊर्जा उपभोग इसी क्षेत्र में होता है। यह क्षेत्र विश्व में 30 से 40 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार है। लंदन स्थित पत्रकार एंड्रयू बिब्बी केपटाउन की सबसे बड़ी अनौपचारिक बस्ती खायेलित्शा में गए और वहां उन्होंने देखा कि किस प्रकार कुयासा कार्यक्रम की मदद से 2000 घरों में बिजली बचाने के बुनियादी उपाय किए जा रहे हैं, साथ ही रोजगार का सृजन भी हो रहा है।

© ई.डेवेंवे / संरा

यह क्योटो प्रोटोकॉल के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत पंजीकृत पहला अफ्रीकी कार्यक्रम है। इसे कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने और स्थानीय प्रदूषण को कम करने के लिए तैयार किया गया था। इसके तहत इंसुलेटेड सीलिंग, सोलर वॉटर हीटर (बिजली से चलने वाले महंगे हीटर के बदले) और लो एनर्जी लाइट लगाने का काम किया गया। वहां के लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी बचत थी। उनके बिजली के खर्च में 40 प्रतिशत की कमी आ गई।

इस कार्यक्रम के तहत रोजगार सृजन हुआ और सामुदायिक सुसंगति कायम करने में मदद मिली। सोलर वॉटर हीटर और सीलिंग लगाने के काम में 76 लोगों को लगाया गया। इससे उन्हें सीधा–सीधा फायदा हुआ। तकनीक को मैन्यूफैक्चर करने वाली दक्षिण अफ्रीकी कंपनियों को भी अप्रत्यक्ष तौर से फायदा हुआ, क्योंकि कुयासा में मिली सफलता से उन्हें उम्मीद है कि उनके उत्पादों की मांग बढ़ेगी और रोजगार सृजन होगा। साइट मैनेजर जुको नदामानी के अनुसार, इस कार्यक्रम से समुदाय को बहुत लाभ हुआ। स्थानीय समाचार पत्र वेस्ट केप न्यूज को उन्होंने बताया कि 'इस कार्यक्रम से समुदाय में एकता आई है, जो आम तौर पर टाउनशिपों में देखने को नहीं मिलती।'

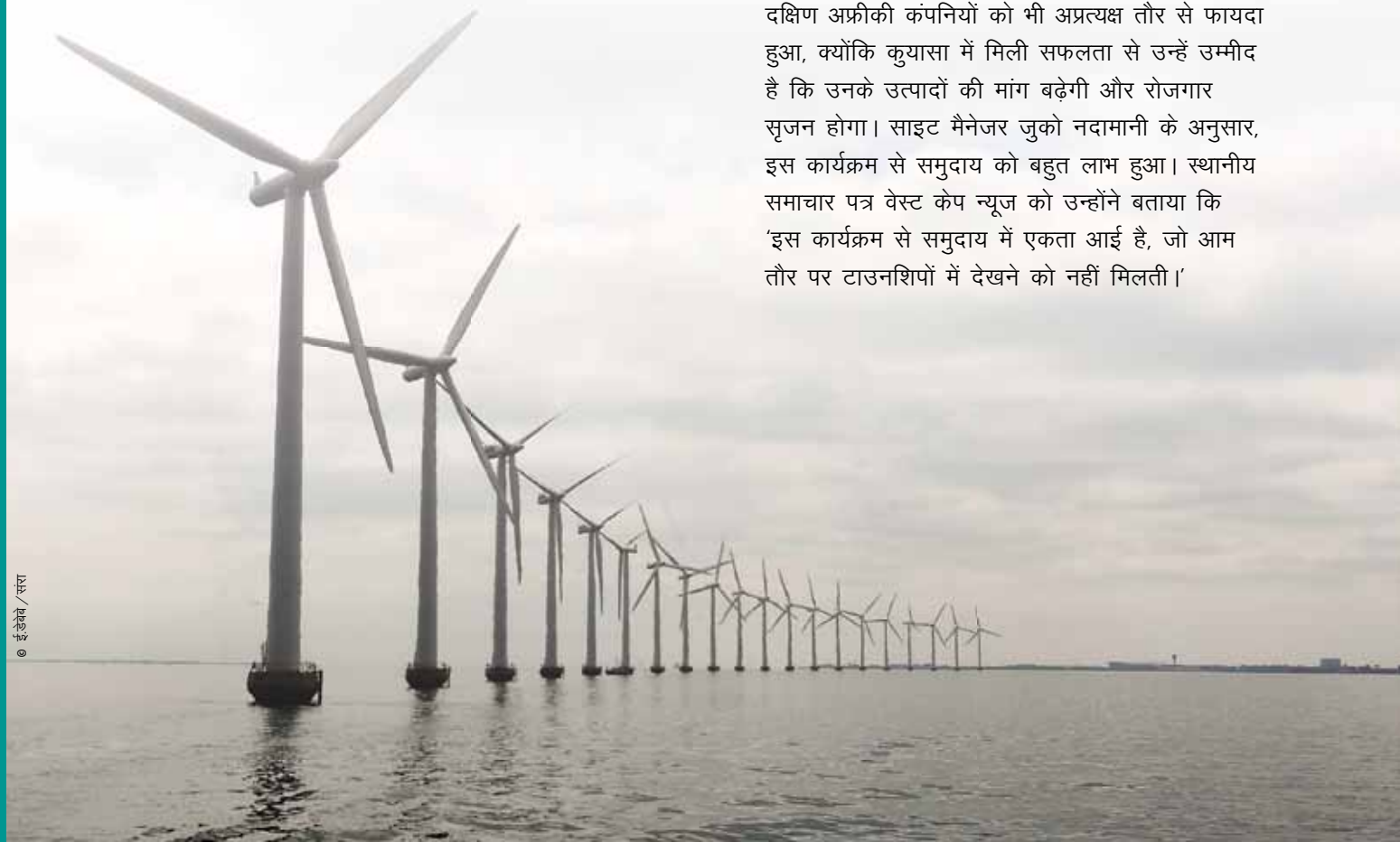

कुयासा कार्यक्रम एक छोटा सा संकेत है कि निर्माण क्षेत्र में हरित रोजगार का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। इस विषय पर आईएलओ ने हाल ही में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है।* दरअसल यह पहल व्यापक हरित रोजगार कार्यक्रम का एक अंग है (देखें श्रम की दुनिया का पिछला अंक) जोकि साल 2008 में आईएलओ और यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) के सहयोग से शुरू किया गया था। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंप्लॉयर्स और इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कनफेडरेशन भी शामिल हैं।

इस संदर्भ में आईएलओ के सेक्टोरल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट की निदेशक एलिजाबेथ तिनोको कहती हैं कि 'निर्माण क्षेत्र को ग्लोबल वॉर्मिंग में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला माना जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुधार की संभावना भी है। नई इमारतों और मौजूदा इमारतों में रिफरबिशमेंट से कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन और ऊर्जा उपभोग में कमी आती है और नई पेशेवर कौशल के विकास से रोजगार अवसरों को भी बढ़ावा मिलता है।'

विश्व में व्यापक निर्माण क्षेत्र को देखते हुए इस संदेश को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। कुयासा में घरों की मरम्मत करने वाले श्रमिक उन 11 करोड़ 10 लाख लोगों में शामिल हैं जो दुनिया भर के देशों में निर्माण क्षेत्र में काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। यह क्षेत्र विश्व की औपचारिक श्रमशक्ति के सात प्रतिशत भाग को रोजगार देता है और राष्ट्रीय जीडीपी में 5 से 15 प्रतिशत का योगदान देता है। पूरा आंकड़ा, जिसमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था भी शामिल है, बहुत अधिक है पर उसका अनुमान लगाना कठिन है।

इनमें से तीन चौथाई श्रमिक विकासशील देशों में हैं और जैसा कि आईएलओ की नई रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है–इसीलिए इन देशों में पर्यावरणीय समस्याओं का व्यावहारिक हल करने और नए हरित रोजगार सृजित करने के ज्यादा मौके हैं।

हालांकि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि नई इमारतों को पर्यावरणीय मानकों के अनुकूल बनाया जाएगा, फिर भी मौजूदा इमारतों में उपयुक्त रेट्रोफिटिंग करना और उनका रिफरबिशमेंट करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि विश्व में मध्यम अवधि का बिल्डिंग स्टॉक पहले ही बना हुआ है। इसलिए चुनौती इस बात की है कि हमारे पास जो कुछ मौजूद है, उसे कैसे बेहतर बनाया जाए।

हरित रोजगार और निर्माण उद्योग के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी आईएलओ अधिकारी एडमंडो वेर्ना के अनुसार, अध्ययन बताते हैं कि विश्व का 25 से 40 प्रतिशत ऊर्जा उपभोग इसी क्षेत्र में होता है। यह क्षेत्र विश्व में 30 से 40 प्रतिशत ग्रीस हाउस गैस उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार है। इमारतें 33 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करती हैं।

उनके अनुसार, निर्माण उद्योग का पर्यावरण पर जो असर होता है, उस पर काफी अध्ययन किया जा चुका है। ये असर इन बातों से जुड़े हुए हैं– निर्माण के लिए जगह और निर्माण प्रक्रिया को चुनना, बिल्डिंग मैटीरियल, उपकरण और उत्पाद को चुनना (जैसे इमारतों के प्रकार)। इसीलिए निर्माण उद्योग जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आईएलओ रिपोर्ट *ग्रीन जॉब्स क्रिएशन थ्रू सस्टेनेबल रिफरबिशमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज* में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स की केस स्टडीज दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि यहां 23 लाख लोग रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर फोटोवॉलटेइक्स और सोलर थर्मल्स में अभी से काम कर रहे हैं। अध्ययन में सलाह दी गई है कि विकासशील देशों में रिफरबिशमेंट में हरित रोजगार के बहुत से अवसर हैं।

* *इस रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए देखें http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/construction/wp275.pdf.*

एक अधिक दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था का प्रतीक

एडमंडो वेर्ना रिपोर्ट का संदेश सुनाते हैं। वह कहते हैं, हरित रोजगार दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था और समाज का प्रतीक हैं जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं। ये अधिक समतामूलक और सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं। निर्माण क्षेत्र में नए हरित रोजगार बहुत महत्वपूर्ण हैं, चूंकि यह क्षेत्र कम दक्ष श्रमिक का उपयोग करता है और श्रम बाजार में आने के लिए लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन वेर्ना इस बात की चेतावनी भी देते हैं कि इस नए हरित रोजगार की गुणवत्ता का ध्यान रखना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

वह कहते हैं, 'प्रमाणों से पता चलता है कि हरित रोजगार स्वतः उत्कृष्ट श्रम का सृजन नहीं करते। इनमें से कई रोजगार बहुत गंदे, खतरनाक और मुश्किल होते हैं। निर्माण और दूसरे उद्योगों में कुछ खास तरह के काम जैसे रीसाइकिलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट खतरनाक होते हैं और उनमें श्रमिकों को वेतन भी कम मिलता है। अगर हरित रोजगार को दीर्घकालीन भविष्य का सेतु बनना है तो उन्हें बदलने की जरूरत है।

अनेक औद्योगिकृत देशों से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि दूसरे क्षेत्रों के श्रमिकों के मुकाबले निर्माण उद्योगों के श्रमिक काम से जुड़े हादसों का ज्यादा बड़ी संख्या में शिकार होते हैं। इनमें भी विकासशील देशों के श्रमिक ज्यादा जोखिम में काम करते हैं। यूके स्थित एनजीओ हाजड्र्स (हाजड्र्स डॉट कॉम) ने ऊर्जा बचाने और रीसाइकिलिंग का काम करने वाले उद्योगों में हादसों और असुरक्षित और अस्वस्थ तरीके से काम करने के कई उदाहरण इकट्ठे किए हैं। इन्हीं जोखिमों ने सोलर फोटोवॉल्टेइक जैसी तकनीकों में विषैले सामान के इस्तेमाल को चुनौती दी है। हाजड्र्स के रोरी ओ नील कहते हैं, 'हरित रोजगार हमेशा संकट मुक्त रोजगार नहीं होते। बहुत से हरित रोजगार, पुराने रोजगार का ही बदला हुआ रूप हैं। रीसाइकिलिंग इंडस्ट्री ने वेस्ट इंडस्ट्री की जगह ले ली है और कई मामलों में ये उस उद्योग से भी ज्यादा खतरनाक है।'

जरूरी नहीं, हरित रोजगार, उत्कृष्ट रोजगार हो

एडमंडो वेर्ना के अनुसार, इन्हीं मुद्दों की वजह से इस बात का महत्व पता चलता है कि हरित रोजगार कार्यक्रम को आईएलओ की उत्कृष्ट श्रम कार्यसूची से जोड़कर देखा जाना चाहिए। वह कहते हैं, 'क्योंकि यह हरित रोजगार है, इसलिए हमेशा यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि यह श्रमिकों के लिए बेहतर है।' वह कहते हैं कि नई तकनीक श्रम प्रक्रिया में बदलाव लाएगी जिस पर विचार किया जाना जरूरी है। उन्होंने इस बात की चिंता भी जाहिर की कि निर्माण क्षेत्र की मौजूदा श्रम समस्याएं जिनमें अस्थायी श्रमिक, काम की खराब स्थितियां और कमजोर सामाजिक संवाद शामिल है, निर्माण क्षेत्र के नए हरित रोजगार में भी स्थानांतरित हो सकती हैं।

© एम. क्रोजेट/आईएलओ

© एम. क्रोजेट / आईएलओ

पहले विध्वंस, फिर हरित निर्माण

फिर भी यहां कई प्रकार के अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। वह कहते हैं, 'हरित रोजगार के सृजन से उन विशिष्ट समूहों जैसे महिलाओं के समूहों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिनकी पहुंच आम तौर पर निर्माण क्षेत्र तक सीमित है। युवाओं को भी लक्षित किया जा सकता है और हरित रोजगार में प्रशिक्षण लेने के बाद उन्हें पास बाजार में दाखिल होने की विशेषज्ञता भी मिल जाएगी। अगर प्रवासी श्रमिकों को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होगा तो वे बेहतर कार्यगत परिस्थितियों के लिए सौदेबाजी कर सकेंगे।'

हमें उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत से नियोक्ता और सरकारें हैं, जिन्होंने हरित निर्माण में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। यूएनईपी ने भी सस्टेनेबल बिल्डिंग्स एंड क्लाइमेट इनीशिएटिव के माध्यम से निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों, जैसे कन्सका एंड लाफार्ज, पेशेवर संगठनों जैसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स, प्रॉपर्टी इनवेस्टरों और निर्माण प्रबंधकों के साथ भागीदारी की है।

> **"प्रमाणों से पता चलता है कि हरित रोजगार स्वत: उत्कृष्ट श्रम का सृजन नहीं करते।"**

इस दिशा में निर्माण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के बीच तालमेल के भी बहुत से अवसर हैं जैसे निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, युटिलिटीज, वेस्ट मैनेजमेंट और रीसाइकिलिंग। वेर्ना कहते हैं, 'निर्माण उद्योग के विभिन्न क्षेत्र परस्पर जुड़े हुए हैं और अगर उन्हें एकीकृत तरीके से लक्षित किया जाता है तो इसका बहुत फायदा होने वाला है। हरित भवन केवल इमारतें नहीं हैं। ये दीर्घकालीन शहरों और समुदायों का आधार हैं।'

एलिजाबेथ तिनोको उन अवसरों पर भी बल देती हैं जो संयुक्त राष्ट्र की विकास पर केंद्रित कार्यसूची को आगे बढ़ाते हैं। वह कहती हैं, 'उत्कृष्ट हरित रोजगार सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन) और सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 7 (पर्यावरण का संरक्षण) को आपस में जोड़ते हैं। इस प्रकार दोनों लक्ष्य परस्पर सहयोगी हैं।' ■

गुंडो लाशू

दक्षिण अफ्रीका में आम ल

दक्षिण अफ्रीका में बेरोजगारी के हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। यहां 25 प्रतिशत से अधिक लोग बेरोजगार हैं। गरीबी का शिकार हैं और उनमें किसी प्रकार का कौशल नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की अस्थायी काम के माध्यम से गरीबी कम करने और आय बढ़ाने की सरकारी रणनीति के तहत वर्ष 2004 में एक्सपैंडेड पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम को आईएलओ का तकनीकी समर्थन प्राप्त है। संगठन नीतिगत विकास और प्रतिपादन में सरकार का सहयोग कर रहा है। जोहानसबर्ग से पत्रकार एलिएनोर मोमबर्ग की रिपोर्ट।

दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में लिंपोपो प्रांत के ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में घूमने से मालूम चलता है कि लोक निर्माण कार्यक्रमों से हजारों लोगों को बहुत फायदा हुआ है।

दक्षिण अफ्रीका के एक्सपैंडेड पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम (ईपीडब्ल्यूपी) को नवंबर 2003 में कैबिनेट से मंजूरी मिली थी और वर्ष 2004 में उन्हें लागू किया गया था।

© आईएलओ फोटो

(हमारी जीत)

लोगों ने बनाई अपनी राह

इसके बाद से अब तक इन लोक निर्माण कार्यक्रमों ने अनेक स्तर पर योगदान दिया है, जैसे आर्थिक वृद्धि और दीर्घकालीन विकास, बेरोजगारों– विशेष रूप से अकुशल श्रमिकों के लिए काम के अस्थायी अवसरों का सृजन।

ईपीडब्ल्यूपी के पहले चरण, जो काम के अवसरों के साथ–साथ प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करता है, का उद्देश्य वर्ष 2009 तक काम के कम से कम 10 लाख मौकों का सृजन करना था। इस चरण से जिन लोगों को लाभ हुआ, उनमें 40 प्रतिशत महिलाएं, 30 प्रतिशत युवा और 2 प्रतिशत विकलांग लोग हैं। यह लक्ष्य वर्ष 2008 तक ही पूरा हो गया और वर्ष 2009 में पहले चरण के समाप्त होने पर काम के 16 लाख अवसरों का सृजन हुआ।

इसी साल एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समिट हुआ जिसमें लोक निर्माण कार्यक्रमों के लिए 100 अरब आर. का आवंटन किया गया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका का यह कार्यक्रम इस मामले में अनूठा है कि यह पूरी तरह से सरकारी अनुदान पर निर्भर था। इसे किसी दूसरे आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं थी। यह आईएलओ के सहयोग से चलाए गए कार्यक्रमों के अनुभवों पर आधारित था। यहां गुंडो लाशू (हमारी जीत) नामक कार्यक्रम का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसे आईएलओ के सहयोग से लिंपोपो प्रांत चलाया गया था। सड़क निर्माण से

संबंधित इस कार्यक्रम को लिंपोपो रोड्स एजेंसी के माध्यम से साल 2001 में लागू किया गया था।

इस कार्यक्रम को युनाइटेड किंगडम डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने शुरुआत में वित्तीय सहयोग दिया। प्रांतीय सरकार, दक्षिण अफ्रीकी सरकार और आईएलओ के तकनीकी सलाहकारों ने नगर पालिकाओं के साथ मिलकर, स्थानीय ठेकेदारों को सड़कें, पुल बनाने और ररखाव का काम दिया। साथ ही प्रांत की ऊबड़ खाबड़ सड़कों की मरम्मत करने का काम दिया गया। आईएलओ से प्रशिक्षण प्राप्त इन ठेकेदारों ने स्थानीय श्रमिकों को काम पर लगाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इनमें से प्रत्येक श्रमिक को नया काम सीखने और कमाई करने का मौका मिला। इससे न केवल उनकी, बल्कि उनके परिवारों की जिंदगी में भी सुधार आया।

नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स (एनडीपीडब्ल्यू) में ईपीडब्ल्यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के इगनाटियस एरियो कहते हैं, 'ईपीडब्ल्यूपी का उद्देश्य यह है कि गांवों और कस्बों में सड़कों, पाइपलाइनों और नालों की मरम्मत की सरकारी योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक स्थानीय श्रमिकों को काम मिले। इसके लिए राज्य की प्रशिक्षण इकाइयों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जबकि डिपार्टमेंट ने प्रशिक्षु ठेकेदारों के लिए धन जुटाने का काम किया।'

लाखों नौकरियों के सृजन की संभावना

एरियो कहते हैं, 'ईपीडब्ल्यूपी बहुत सफल रहा है। हमें उम्मीद है कि दूसरे चरण के दौरान हम वर्ष 2014 तक काम के 45 लाख अवसरों या 20 लाख पूर्णकालिक रोजगारों का सृजन कर पाएंगे। इस चरण की शुरुआत साल 2010 में की गई थी। जून 2010 में पहली तिमाही के समाप्त होने तक काम के 193000 अवसरों का सृजन हो चुका था, जो कि 2010–2011 के वित्तीय वर्ष के 642000 के लक्ष्य का 30 प्रतिशत है। इसलिए हम अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में हैं।'

वह कहते हैं, सर्वेक्षण बताते हैं कि 100 दिनों के काम का लोगों की जिंदगी पर अच्छा असर होता है। वह कहते हैं, 'यह बेरोजगारी का सबसे अच्छा समाधान नहीं है लेकिन यह बहुत अच्छा बदलाव है। लोक निर्माण के श्रम केंद्रित कार्यक्रम से स्थायी रोजगार का सृजन नहीं होता। यह थोड़े से समय का लाभ देता है लेकिन इससे लोगों को आसानी से औपचारिक श्रम बाजार में दाखिल होने का कौशल नहीं मिलता। न ही यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

क्लेनिजी माथाबाथे एक ठेकेदार हैं और लिंपोपो प्रांत के मोकोपेन कस्बे में खडंजा बिछाने का काम सीख रही हैं। वह कहती हैं, 'पहले मेरे यहां 10 मजदूर काम करते थे। मई 2010 से मेरे यहां 28 लोग काम कर रहे हैं। मेरी जिंदगी में सुधार आया है और मेरे मजदूरों की जिंदगी भी बदली है क्योंकि अब हम पहले से ज्यादा कमाते हैं। मैं चाहती हूं कि जब मेरा प्रशिक्षण खत्म हो तो मैं लिंपोपो की सबसे अच्छी ठेकेदार बनूं।'

कार्यक्रम में क्लेनिजी माथाबाथे की मेंटर हैं ग्लोरिया रामदेला जिन्होंने आईएलओ की मदद से लेसोथो में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने गुंडो लाशू कार्यक्रम में भाग लिया और फिर वह सुपरवाइजर और साइट मैनेजर बनीं। अब वह दूसरो की मेंटर बन गई

© आईएलओ फोटो

© M. Crozet/ILO

हैं। 'मैं ठेकेदारों और मजदूरों को यह बताती हूं कि उन्हें कैसे काम करना है, फिर पीछे हटकर उन्हें काम करते देखती हूं। इसके बाद मैं उन्हें सलाह देती हूं और सिखाती हूं। इसके बाद अपने धन का कैसे प्रबंधन करना है, इस बात में उनकी मदद करती हूं।' ग्लोरिया स्वयं क्या बनना चाहती हैं? वह एक सिविल इंजीनियर बनना चाहती हैं।

आईएलओ की भूमिका

एरियो कहते हैं कि आईएलओ ने ढांचागत निर्माण क्षेत्र में मानक प्रदान करने, अच्छे प्रस्तावों का निर्धारण करने, प्रशिक्षण मैनुअल को विकसित करने और प्रशिक्षण में सहायता देने में ईपीडब्ल्यूपी को महत्वपूर्ण योगदान दिया।

दक्षिण अफ्रीका में आईएलओ के आठ तकनीकी सलाहकार हैं। ये सभी श्रम सघन तरीके के रोजगार में विशेषज्ञ हैं। राष्ट्रीय, प्रांतीय और म्यूनिसिपल स्तर पर श्रम सघन निवेश कार्यक्रमों को तकनीकी सहायता और परामर्श देने के अतिरिक्त ये सलाहकार ईपीडब्ल्यूपी के समूचे प्रबंधन में शामिल हैं। आठों सलाहकार प्रांतों की गतिविधियों को भी समन्वित करते हैं। प्रिटोरिया में आईएलओ कार्यालय के निदेशक वान वुरेन कहते हैं, 'हमारे दो सलाहकार सरकार को रोजगार से संबंधित नीतिगत और रोलऑउट से जुड़ी सलाह भी देते हैं।'

दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका के लिए आईएलओ की डीसेंट वर्क टीम में सीनियर स्पेशलिस्ट क्वाकू ओसेई–बोंसू दूसरे अफ्रीकी देशों की तरह दक्षिण अफ्रीका में भी प्रशिक्षण सुविधा दिए जाने की उम्मीद करते हैं। क्वाकू रोजगार सघन निवेश के विशेषज्ञ हैं। ऐसी सुविधाएं इथियोपिया, घाना, केन्या, मैडागास्कर, तंजानिया और उगांडा में पहले से मौजूद हैं। वह कहते हैं, 'औपचारिक प्रशिक्षण केंद्र होने से लोगों को स्थायी प्रशिक्षक पहले से उपलब्ध होंगे जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण अधिक अनुभव प्राप्त कर लेंगे।'

कौशल हस्तांतरण की आवश्यकता

दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी समस्या सामर्थ्य का अभाव है, विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग में

"पहले मेरे यहां 10 मजदूर काम करते थे। मई 2010 से मेरे यहां 28 मजदूर काम कर रहे हैं।"

तकनीकी और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का। इसका अर्थ यह है कि लिंपोपो में आईएलओ की तकनीकी टीम को अक्सर विभागीय काम भी करने पड़ते हैं। ओसेई–बोंसू कहते हैं कि उन्हें वह स्थिति ज्यादा अच्छी लगेगी जब आईएलओ दक्षिण अफ्रीका में केवल सलाहकार की भूमिका में हो। 'हम केवल विशेषज्ञता प्रदान करें और देश के लोगों की मदद करें।'

वान वुरेन कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में परियोजना का प्रबंधन कई बार कमजोर होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि कौशल का हस्तांतरण किया जाए जिससे लोग इस तरह के कार्यक्रम अपने आप चला सकें। उनका मानना है कि इस बात की जरूरत है कि बाजार में कौशल का प्रावधान हो और सरकार द्वारा मजबूत नेतृत्व दिया जाए। आंतरिक रूप से स्टाफ को प्रबंधित करने पर बल दिया जाए और ऐसा परिवेश तैयार किया जाए कि उचित पद पर उचित व्यक्ति नियुक्त हो।

ओसेई–बोंसू के अनुसार, 'दक्षिण अफ्रीकी सरकार के कदम की मैं प्रशंसा करता हूं। बेशक चुनौतियां मौजूद हैं लेकिन उन्हें दूर किया जा सकता है। अगर राजनैतिक प्रतिबद्धता मौजूद है तो उन चुनौतियों का बहुत आसानी से सामना किया जा सकता है।

आईएलओ की इंप्लॉयमेंट इनटेंसिव इनवेस्टमेंट यूनिट (ईएमपी आईएनवीईएसटी ईआईआईपी) ढांचागत निवेश के रोजगार सघन प्रस्तावों को विकसित और कार्यान्वित करती है। ईआईआईपी विश्व स्तर पर सरकारों, नियोक्ता और श्रमिक संगठनों, निजी क्षेत्र और सामुदायिक संगठनों को समर्थन देती है जिससे वे ढांचागत निवेश में रोजगार को बढ़ाने की कोशिश करें, साथ ही गरीब लोगों तक बुनियादी वस्तुएं और सेवाएं पहुंचाएं। ईआईआईपी 70 से अधिक देशों में काम करती है।

आईएलओ और दक्षिण अफ्रीका में श्रम आधारित सार्वजनिक सड़क निर्माण कार्यक्रम

वर्ष 1994 के नेशनल इंप्लॉयमेंट प्रोग्राम (एनईपी) की विकास प्रक्रिया के बाद परामर्श कार्य करते हुए आईएलओ का दक्षिण अफ्रीका में असल काम शुरू हुआ वर्ष 1996 में। पहले लोकतांत्रिक चुनावों के दो साल बाद। नटाल और विटवॉटर्सरैंड विश्वविद्यालयों के सहयोग से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिक आधारित सड़क निर्माण और अनुसंधान को प्रस्तावित करना था। स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए नए पाठ्यक्रम को विकसित करने के माध्यम से कार्यक्रम लागू किया जाना था।

वर्ष 1996 और 1997 में आईएलओ ने नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स से आग्रह किया कि वह समुदाय आधारित लोक निर्माण कार्यक्रम का मूल्यांकन करे जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने कार्यक्रम को गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, स्थानीय लोगों के सशक्तीकरण और कौशल विकास के उद्देश्य से दोबारा शुरू किया। वर्ष 2001 के मूल्यांकन में कार्यक्रम की सफलता के बारे में मालूम चला और यह भी पता चला कि लोगों के जीवन पर इसका बहुत अच्छा असर हुआ है।

वर्ष 1998 से 2000 तक आईएलओ ने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स को तकनीकी सहयोग प्रदान किया। संगठन ने सार्वजनिक निर्माण करने और रखरखाव के काम में रोजगार के मुद्दों को एकीकृत करने की नीतियों पर विभाग को परामर्श भी प्रदान किया। यह काम आज भी किया जा रहा है, साथ ही लिंपोपो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स की क्षमता निर्माण का काम भी जारी है।

वर्ष 2007 में डरबन में श्रमिक आधारित प्रैक्टीशनरों के 12 वें क्षेत्रीय सेमिनार की सफलता के बाद दक्षिण अफ्रीका में ग्लोबल जॉब्स पैक्ट (जीजेपी) के कार्यान्वयन के लिए आईएलओ ने एक उच्च स्तरीय अभियान चलाया। दक्षिण अफ्रीका के जीजेपी कंट्री स्कैन का पहला मसौदा सौंपा जा चुका है, प्राथमिकताओं, जैसे हरित रोजगार का सृजन, को चिन्हित किया जा चुका है और ढांचागत विकास के रोजगार प्रभाव का आकलन किया जा चुका है।

ट्यूरिन में आईएलओ के अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम पब्लिक इंप्लॉयमेंट प्रोग्राम्स (आईपीईपी) के तहत शुरू किए गए इनोवेशंस में जिन तीन देशों को शोकेस किया गया, उसमें से ईपीडब्ल्यूपी भी है। रोजगार और निवेश नीतियो के लिए एक वरिष्ठ आईएलओ विशेषज्ञ मितो सुकामोतो के अनुसार, 'रोजगार सृजन, आय उत्सर्जन, परिसंपत्ति का निर्माण और सामाजिक संरक्षण जैसे कई उद्देश्यों को पूरा करने और विशिष्ट परिस्थितियों में सही प्रतिक्रिया देने के कारण इन कार्यक्रमों को बहुत अच्छा माना गया है।'

इस बीच दक्षिण अफ्रीका में रोजगार केंद्रित कार्य ने परंपरागत ढांचागत और निर्माण कार्यक्रमों से आगे बढ़कर काम करना शुरू कर दिया है। साल 2010 में साउथ अफ्रीकन प्रेजिडेंसी में असमानता और आर्थिक सीमांतीकरण की रणनीतिगत प्रक्रिया का नेतृत्व करने वाली डॉ. केट फिलिप के अनुसार, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूपी) और इंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स (ईजीएस) ढांचागत और निर्माण कार्यों से गहराई से जुड़ी हुई हैं लेकिन अब ये सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरणीय सेवाओं और बहुक्षेत्रीय समुदाय आधारित कार्यक्रमों में भी शामिल हैं। ■

© एम. क्रोजेट / आईएलओ

भविष्य के शिक्षक और प्रशिक्षक

आईएलओ का अनुमान है कि वर्ष 2007 से अब तक विश्व में बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ से भी अधिक हो गई है। वर्ष 2009 में जब संगठन की विश्वव्यापी रोजगार संधि को मंजूरी मिली थी, तब इस नीतिगत समाधान पर भी सहमति बनी थी कि विश्वव्यापी रोजगार संकट को समाप्त करने का एक हल यह भी है कि लोगों को रोजगारपरकता के लिए जरूरी कौशल से लैस किया जाए। 29 से 30 सितंबर 2010 को जेनेवा में 43 देशों के श्रमिक, नियोक्ता व सरकारी– श्रम व शिक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने एक बैठक की और विश्व स्तर पर तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण (टीवीईटी) देने के लिए जरूरी नीतियों और उपायों को तत्काल अपनाए जाने का सुझाव दिया।

ग्लोबल डायलॉग फोरम ऑन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने इस बात की जांच की कि टीवीईटी प्रणाली संतुलित कौशल विकास के माध्यम से किस प्रकार रोजगार और कार्यस्थलों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करती है। यह प्रणाली ऐसी कौशल को विकसित करती है जिसकी जरूरत वास्तविक कार्यस्थलों पर होती है।

नियोक्ताओं और श्रमिक संघों के बीच सहयोग की आवश्यकता के मद्देनजर प्रशिक्षण स्कूलों और अन्य भागीदारों ने टीवीईटी को शामिल किया जिससे सही परिणाम हासिल किए जा सकें। इन चुनौतियों के प्रतिक्रियास्वरूप आर्थिक क्षेत्र के लिए विशिष्ट कौशल विकास रणनीतियां और जी 20 देशों द्वारा विकसित की गई रणनीतियां सामने आईं।

फोरम ने प्रशिक्षण, पारिश्रमिक, शिक्षण और टीवीईटी पेशेवरों के लिए काम की स्थितियों पर विशेष रूप से बात की। टीवीईटी प्रणालियों के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं। उन्हें टीचरों और ट्रेनरों की कमी का सामना करना पड़ता है। दक्ष पेशेवरों के लिए निजी

© वी. कुट्टी / आईएलओ

उद्यमों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, टीचरों को नया प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करनी पड़ती है। विकासशील देशों में उनके लोगों को कम वेतन में गुजारा करना पड़ता है और अक्सर उनके पास अप टू डेट इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरण भी नहीं होते हैं।

आईएलओ के वरिष्ठ प्रशिक्षण विशेषज्ञ माइकल एक्समैन कहते हैं, 'इन प्रणालियों को आर्थिक स्थिरता और सरकार के गंभीर वित्तीय बजटीय दबावों के कारण अनुदान की समस्या का सामना करना पड़ता है।'

इसके अतिरिक्त, विश्व स्तर पर टीवीईटी प्रणालियों को रोजगार और कार्यस्थलीय चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है जैसे बदलती तकनीक, छोटे होते उत्पाद चक्र, कार्य संगठनों के नए रूप, दीर्घकालीन विकास और हरित रोजगार। विश्व स्तर पर आर्थिक, रोजगार और सामाजिक एकीकरण की रणनीतियों में श्रमिकों को अच्छी शिक्षा और कौशल देना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए टीवीईटी नीतियों का उपयोग करना सबसे कारगर उपाय है।

उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार द्वारा नई मांगों को पूरा करना

टीवीईटी टीचरों और ट्रेनरों को समय और देश के अनुसार रोजगार मिलता है लेकिन बदलते समय के साथ–साथ उनमें वृद्धि हुई है। यूरोप के 23 देशों में से आधे से अधिक ने हाल के वर्षों में अपने सेकेंडरी स्तर के टीचरों की संख्या बढ़ाई है। इसी तरह तीन बटा पांच विकासशील देशों में इस क्षेत्र में रोजगार में बढ़ोतरी हुई है जिससे आर्थिक मंदी के बाद बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके। उच्च आय वाले देशों ने

> “इन प्रणालियों को आर्थिक स्थिरता और सरकार के गंभीर वित्तीय बजटीय दबावों के कारण अनुदान की समस्या का सामना करना पड़ता है।”

टीचरों की संख्या बढ़ाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जैसे दूसरे देशों से टीचरों की भर्तियां, फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण और भर्ती प्रक्रियाएं, पार्ट टाइम और लचीले कार्य प्रबंधन का सहारा लेना। दूसरी ओर निम्न और मध्यम आय वाले देश अक्सर टीवीईटी टीचरों के रोजगार और करियर स्ट्रक्चर से संबंधित नई मांगों को लेकर जूझते रहते हैं।

जैसा कि आईएलओ के वरिष्ठ शिक्षा विशेषज्ञ और प्रशिक्षकों पर तैयार की गई रिपोर्ट* के लेखक बिल रातरी कहते हैं, 'इस क्षेत्र में एक अच्छा बदलाव यह हुआ है कि महिला टीचरों और ट्रेनरों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यह वही क्षेत्र है जहां महिलाओं को परंपरागत तौर पर पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। सभी क्षेत्रों के अधिकतर देशों में कुल लोगों के मुकाबले महिला टीचरों और ट्रेनरों में उच्च रोजगार वृद्धि देखी गई।'

ट्रेनरों को प्रशिक्षण

टीचरों और ट्रेनरों की अनेक प्रकार की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि उन्हें भी नए अनुभव और प्रशिक्षण दिए जाएं। साथ ही कार्यक्रम से जुड़े फैसलों के संबंध में उन्हें स्वायत्तता मिले और श्रम की दुनिया तक उनकी पहुंच बढ़े।

अनेक देशों को गैर शैक्षणिक कार्य अनुभव की आवश्यकता है और वे ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के अंग के रूप में पैडागोगिकल ट्रेनिंग (शिक्षा शास्त्रीय प्रशिक्षण) पर बल दे रहे हैं। इससे टीवीईटी संस्थानों और कार्यस्थलों के बीच के अंतर को खत्म किया जा सकता है। टीवीईटी नौकरियों के लिए टीचरों को तैयार करने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने से संबंधित सुधारों में टीचर एसेसमेंट मैकेनिज्म को भी शामिल किया जा रहा है।

इस स्तर की शिक्षा के लिए जितने धन की जरूरत होती है, जोकि सामान्य शिक्षा के मुकाबले कहीं अधिक है, वह उपलब्ध नहीं हो पाता। विकासशील देशों में विकास सहायता के निम्न स्तरों का बहाना बनाया जाता है, जबकि औद्योगिक देशों में कहा जाता है कि आर्थिक मंदी का सरकारी बजट पर बहुत बुरा असर हुआ है। इस स्थिति में सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पीपीपी)काम आती है। भविष्य में भी इसके ज्यादा से ज्यादा उपयोग की कोशिश की जानी चाहिए।

अधिक व्यापक सामाजिक संवाद की आवश्यकता

बदलते समय ने टीवीईटी और श्रम की दुनिया के संबधों को भी बदला है। इसलिए सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच अच्छे सामाजिक संवाद से अधिक प्रासंगिक नीतिगत समाधानों को तलाशा जा सकता है। बिल कहते हैं, 'हालांकि सरकारों, नियोक्ताओं, श्रमिकों संघों और अन्य भागीदारों के बीच पहले से अधिक संवाद होता है, लेकिन अक्सर खराब स्थिति में चलने वाले या गैर मौजूद संस्थानों या प्रणालियों पर ही बातचीत होती है। यह मुद्दा टीवीईटी सुधारों में सबसे सामयिक, जरूरी और महत्वपूर्ण है।'

दो दिवसीय चर्चा के बाद फोरम ने टीवीईटी में सुधार से संबंधित सिफारिशों को स्वीकृत किया। इसमें शामिल है, टीवीईटी की उच्च स्थिति और नई प्रतिष्ठा, कौशल की मांग और आपूर्ति से संबंधित ताजा जानकारियों को एकत्र करना और उनका विश्लेषण करने के लिए विभिन्न देशों को विकास सहायता प्रदान करना, टीवीईटी टीचरों और ट्रेनरों की योग्यता, भर्ती और बहाली में सुधार करना योग्य महिलाओं और अल्पसंख्यकों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने की मानव संसाधन नीतियां, उचित तरीके से वित्त पोषित टीवीईटी संरचना और आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण, नियोक्ताओं और टीचरों एवं ट्रेनरों के श्रमिक संगठनों के बीच सामाजिक संवाद को मजबूत करना, कार्यस्थलों और प्रशिक्षण स्थलों के बीच प्रोत्साहनपरक संबंध हैं।

फोरम ने आईएलओ से अधिक प्रासंगिक आंकड़ों, अच्छे उदाहरणों और टीवीईटी से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने में सदस्य देशों की मदद करने का आग्रह किया है। ■

** टीचर्स एंड ट्रेनर्स फॉर द फ्यूचर– टेक्नीकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, आईएलओ, जेनेवा, 2010*

समाचार

- जी 20 देशों ने रोजगार, सामाजिक संरक्षण की प्रतिबद्धता को लागू करने की अपील की
- मिशेल बाचेलेट : सामाजिक संरक्षण का धरातल देता है अगला ठोस कदम
- आईएमएफ/आईएलओ ने रोजगार केंद्रित आर्थिक बहाली की प्रतिबद्धता दर्शाई
- आईएलओ महानिदेशक को मिला एमडीजी पुरस्कार
- आईएलओ महानिदेशक ने चिली के खान मजदूरों के बचाव अभियान की प्रशंसा की
- अर्थशास्त्र के क्षेत्र में साल 2010 का नोबल पुरस्कार
- विशेषज्ञों ने कृषि क्षेत्र में सुरक्षा और स्वास्थ्य पर आईएलओ की नई व्यवहार संहिता को मंजूरी दी

जी 20 देशों ने रोजगार, सामाजिक संरक्षण की प्रतिबद्धता को लागू करने की अपील की

रोजगार की धीमी बहाली पर व्यापक चिंता के बीच, आईएलओ महानिदेशक ने जी 20 देशों से आग्रह किया कि वे विश्वव्यापी बहाली में सामाजिक संरक्षण और उत्कृष्ट श्रम की केंद्रीय भूमिका के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लागू करें।

© योनहाप/ईपीए/कॉरबिस

जी 20 देशों के नेताओं के घोषणापत्र में कहा गया कि 'हम आर्थिक बहाली के केंद्र में रोजगार को लाने और सामाजिक संरक्षण व उत्कृष्ट श्रम देने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि निम्न आय वाले देशों में वृद्धि की गति तेज होगी।'

आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया ने भी सियोल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, 'रोजगार घाटे पर विश्वव्यापी चिंता ने जी 20 देशों को आर्थिक बहाली के लिए समन्वित कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने को मजबूर किया है। सियोल में आयोजित इस सम्मेलन ने पुष्टि की है कि विश्वव्यापी आर्थिक बहाली के केंद्र में अच्छे रोजगार का सृजन होना चाहिए। मैं जी 20 देशों ने यह आग्रह करता हूं कि इस प्रतिबद्धता को लागू करें। साथ ही मैं आईएलओ के पूर्ण सहयोग का वचन देता हूं।'

उन्होंने कहा, 'वृद्धि मजबूत और दीर्घकालिक हो, इसके लिए विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का केवल यह अर्थ नहीं कि मुद्राओं और वित्तीय क्षेत्र को समायोजित किया जाए। सामाजिक संरक्षण और अच्छे रोजगार में निवेश करना भी जरूरी है क्योंकि इससे वास्तविक अर्थव्यवस्था में उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा मिलता है और दीर्घकालिक वृद्धि संभव होती है।'

उन्होंने जी 20 सियोल समिट के 'शेयर्ड ग्रोथ' (सभी की वृद्धि) के संदेश की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि 'इस विचार से वृद्धि का लाभ देशों के भीतर और बाहर दोनों ओर होगा। देशों के भीतर वृद्धि के लाभ का सही बंटवारा होगा और विकासशील और उच्च आय वाले देशों के बीच का अंतराल भी कम होगा।' उन्होंने यह भी कहा कि 'दीर्घकालिक वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादकता के अनुसार वेतन में वृद्धि की जाए।'

आईएलओ महानिदेशक ने जी 20 देशों के नेताओं द्वारा स्वीकृत 'सियोल डेवलपमेंट कंसेंसेस फॉर शेयर्ड ग्रोथ' (सभी की वृद्धि पर सियोल सम्मलेन की आम सहमति) के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, 'मैं जी 20 देशों के निवेश, रोजगार और सामाजिक संरक्षण केंद्रित विकास प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। इस बात को मान्यता देना कि सामाजिक संरक्षण पर ध्यान देना, दरअसल उच्च उत्पादकता और लचीली वृद्धि में निवेश होता है, बहुत उत्साहजनक बात है।'

श्री सोमाविया ने कहा कि आईएलओ की उत्कृष्ट श्रम कार्यसूची और विश्वव्यापी रोजगार संधि, दोनों जी 20 देशों के संतुलित वृद्धि और विकास के प्रस्ताव की मुख्यधारा में आ रही हैं।

मजबूत, दीर्घकालिक और संतुलित वृद्धि को अपनी संरचना में गहराई से शामिल करते हुए जी 20 देशों ने समन्वित और देशकेंद्रित नीतिगत कार्रवाई पर सियोल कार्ययोजना को मंजूरी दी। इस मौके पर आईएलओ से आग्रह किया गया कि वह विभिन्न देशों की प्रतिबद्धता और संरचना के तहत उनकी प्रगति की समीक्षा करे। इस संबंध में जी 20 देशों के नेताओं ने आईएमएफ और आईएलओ के बीच गहरे संबंधों को बरकरार रखने का आग्रह भी किया।

आईएलओ से यह आग्रह भी किया गया कि वह वृद्धि के नौ स्तंभों वाली कार्रवाई योजना में भी अपना योगदान दे। इस बहुवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए निजी निवेश और व्यापार, कौशल विकास, सामाजिक संरक्षण और खाद्य सुरक्षा आदि शामिल हैं।

जी 20 देशों ने आईसीडी, आईएलओ, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ की एक संयुक्त रिपोर्ट पर भी चर्चा की। इस रिपोर्ट में व्यापार और रोजगार नीतियों के सुसंगत प्रस्ताव का आह्वान किया गया था। इन देशों के सियोल घोषणापत्र में निजी क्षेत्र के कारण उत्पन्न वृद्धि और रोजगार पर केंद्रित व्यापार शिखर सम्मेलन के योगदान को मान्यता दी गई है। जी 20 देशों के नेताओं ने व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जिसमें श्रमिक संगठन भी शामिल हैं, के साथ परामर्श बढ़ाने का निर्णय किया।

श्री सोमाविया ने सम्मेलन से एक दिन पहले श्रमिक संगठनों के नेताओं के कारगर प्रयासों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने रोजगार में सुधार को गति देने के महत्व पर बल दिया। गौरतलब है कि सियोल सम्मेलन को इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कनफेडरेशन, ओईसीडी की ट्रेड यूनियन एडवाइजरी काउंसिल, ग्लोबल यूनियंस और उनके कोरियाई गठबंधन ने आयोजित किया था। ■

मिशेल बाचेलेट: सामाजिक संरक्षण का धरातल देता है अगला ठोस कदम

© एम. क्रोजेट / आईएलओ

जेनेवा में पिछले साल 11 और 12 अगस्त को सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर एडवाइजरी ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की गई। आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया द्वारा आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट ने की।

सामाजिक संरक्षण धरातल यानी सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारों और हस्तांतरणों का एक समूह है। साथ ही रोजगार, स्वास्थ्य, पानी और सफाई, पोषण, शिक्षा और पारिवारिक सहयोग, गरीब और संवेदनशील लोगों को सशक्त करने और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए अनिवार्य है। इस सामाजिक नीति को एक सुसंगत और एकीकृत प्रस्ताव के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए जिसके केंद्र में महिलाएं, बच्चे और युवाओं समेत समाज के सबसे संवेदनशील समूह हों।

विश्व स्तर पर अनुमान लगाएं तो काम करने की उम्र वाले हर पांच में से एक व्यक्ति के पास कोई पर्याप्त सामाजिक संरक्षण नहीं होता। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उसकी पहुंच नहीं होती। बेरोजगारी की स्थिति में उसकी कोई मदद करने वाला नहीं होता। आर्थिक मंदी ने इन संवेदनशील समूहों को और अधिक प्रभावित किया है, चाहे वे विकासशील देश के लोग हों, या विकसित देशों के। विश्व स्तर पर बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ी है। साल 2010 तक इसके और बढ़ने की आशंका है।

यह भी अनुमान लगाया गया है कि आर्थिक और खाद्य संकट के चलते बहुत कम में गुजारा करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। साल 2009 में दो अमेरिकी डॉलर प्रति दिन से भी कम पर गुजारा करने वाले लोगों में 9 करोड़ 80 लाख लोग और शामिल हो गए हैं। युवा लोग खास तौर से प्रभावित हुए हैं।

दो दिवसीय बैठक के दौरान (देखें फोटो पेज 52–53) सुश्री बाचेलेट ने प्रमुख विशेषज्ञों और नीति निर्धारकों के

समूह के साथ बातचीत की। इस बातचीत में सामाजिक संरक्षण धरातल के अर्थ, उसके मुख्य उपादानों, उसकी राजनैतिक, आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता, संस्थागत आयाम और प्रतिकूल स्थितियों में दीर्घकालिकता और विभिन्न देशों की परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार वित्तीय उपलब्धता शामिल हैं।

इस समूह में आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की महानिदेशक मार्ग्रेट चान भी शामिल थे। ये दोनों पूर्व ऑफिशियो सदस्य हैं।

सुश्री बाचेलेट ने कहा, 'सामाजिक संरक्षण के कारण सामाजिक सेवाओं तक लाखों लोगों की पहुंच बनती है और वे गरीबी के गर्त में गिरने से बचते हैं। ऐसा होने पर लोगों में सामाजिक असंतोष नहीं बढ़ता और कुल मांग के गिरने की आशंका नहीं होती। इससे आर्थिक मंदी की आशंका भी कम होती है।'

सुश्री बाचेलेट के अनुसार, 'लेकिन सामाजिक संरक्षण नीतियां– और सामाजिक संरक्षण धरातल का लक्ष्य– आने वाले समय में और महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आर्थिक संकट का मानव मूल्य अत्यधिक है। अब वह समय आ गया है जब हम सब मिलकर अपनी गतिविधियों को इस प्रकार समन्वित करें कि सभी को सामाजिक संरक्षण का लाभ मिले। इस समूह को इसी दिशा में पहला कदम कह सकते हैं।'

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, आईएमएफ और विश्व बैंक ने सामाजिक संरक्षण धरातल को क्रियान्वित करने पर सहमति जताई। युनाइटेड नेशंस सिस्टम चीफ एगजेकेटिव्स बोर्ड फॉर कोऑरडिनेशन (यूएनसीईबी) ने अप्रैल 2009 में आर्थिक संकट से निपटने के लिए जिन नौ संयुक्त कार्यक्रमों पर सहमति जताई थी, यह उनमें से एक है। सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर नामक इस कार्यक्रम को आईएलओ और डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में चलाया जा रहा है और इसमें 17 अन्य एजेंसियां शामिल हैं। ■

आईएमएफ/आईएलओ ने रोजगार केंद्रित आर्थिक बहाली की प्रतिबद्धता दर्शाई

पिछले साल सितंबर में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने अन्य नेताओं के साथ, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के मद्देनजर व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता का आह्वान किया।

पिछले साल सितंबर में ओस्लो में एक ऐतिहासिक सम्मेलन किया गया। सम्मेलन की मेजबानी नार्वे के प्रधानमंत्री जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने की थी और इसके प्रायोजक आईएमएफ और आईएलओ थे। इस सम्मेलन में सरकार, श्रम, व्यापार और शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में साल 2008 के विश्वव्यापी वित्तीय संकट के बाद से बढ़ती बेरोजगारी और अल्प रोजगार को रोकने पर चर्चा की गई।

आईएमएफ के प्रबंध निदेशक डोमिनिक स्ट्राउस–कान ने कहा, 'वित्तीय संकट का कामकाजी लोगों पर जो असर हुआ है, उसके प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इस बैठक के माध्यम से पता चला है कि लाखों लोगों को श्रम बाजार में दोबारा लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। रोजगार संकट न केवल विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, बल्कि सामाजिक सुसंगति और शांति के लिए भी जरूरी है।'

'अगर अर्थव्यवस्था की वृद्धि का फायदा सभी को नहीं होता तो वह वृद्धि कभी दीर्घकालिक नहीं होती।' आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया ने यह कहते हुए स्पष्ट किया कि 'हमें दो साल पहले आई मंदी से यही सबक लेना चाहिए। इसका समाधान क्या है? यह कि हमारा आर्थिक लक्ष्य यह होना चाहिए कि निम्न मुद्रास्फीति और दीर्घकालिक बजट के अतिरिक्त उच्च स्तर का रोजगार सृजन किया जाए। हमें भूमंडलीकरण को सही दिशा में ले जाना चाहिए। इसके लिए हमें सुसंगत और संतुलित नीतियों की, संस्थानों और देशों के बीच समन्वय और संवाद की जरूरत है। यह सम्मेलन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।'

आईएलओ का अनुमान है कि साल 2007 से विश्व स्तर पर बेरोजगारों की संख्या तीन करोड़ से अधिक हो गई है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी में गंभीर वृद्धि हुई है लेकिन उभरते हुए बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका बुरा असर हुआ है।

ओस्लो सम्मेलन में विभिन्न देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया जिनमे लाइबेरिया की प्रधानमंत्री एलेन जॉनसन सिरलीफ, ग्रीस के प्रधानमंत्री जॉर्ज पापेनड्रेओ और स्पेन के प्रधानमंत्री जोस ल्युस रॉड्रिग्स जैपेटेरो शामिल थे। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कनफेडरेशन के महासचिव शैरेन बुर्रे के नेतृत्व में श्रम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन के दौरान आईएमएफ और आईएलओ दो विशिष्ट क्षेत्रों में नीतिगत विकास के लिए राजी हुए। पहला, यह कि वे वृहद आर्थिक नीतियों के लिए जरूरी संरचना और विकास की रणनीतियों के संदर्भ में गरीब और संवेदनशील लोगों के लिए सामाजिक संरक्षण धरातल की अवधारणा की खोज करेंगे। दूसरा, दोनों संगठन रोजगारोन्मुखी वृद्धि से संबंधित नीतियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

बाएं से दाएं : नार्वे के प्रधानमंत्री जेन्स स्टोलटेनबर्ग, लाइबेरिया की प्रधानमंत्री एलेन जॉनसन सिरलीफ, आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया और आईएमएफ के प्रबंध निदेशक डोमिनिक स्ट्राउस–कान

इस बात पर भी समझौता किया गया कि कारगर सामाजिक संवाद के माध्यम से आम सहमति कायम की जा सकती है और संकट से उत्पन्न हुई चुनौतियों से निपटा जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि संकट के सामाजिक परिणामों पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

दोनों संगठनों ने आम सहमति से कहा कि वे मजबूत, दीर्घकालिक और संतुलित विश्वव्यापी वृद्धि सुनिश्चित करने की जी 20 देशों की परस्पर विश्लेषण प्रक्रिया को अपना सहयोग जारी रखेंगे। ■

आईएलओ महानिदेशक को मिला एमडीजी पुरस्कार

आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया को सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के संदर्भ में महती योगदान देने और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्री सोमाविया को यह पुरस्कार एमडीजी पुरस्कार समिति द्वारा दिया गया। समिति ने विश्व के महिलाओं और पुरुषों के लिए उत्कृष्ट श्रम सुरक्षित करने के संबंध में उनके दृष्टिकोण और समर्थन की प्रशंसा की।

20–22 सितंबर को न्यूयार्क में यूएन एमडीजी समिट के दौरान श्री सोमाविया को इस पुरस्कार से नवाजा गया। इस दौरान सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विश्व नेता एकत्र हुए थे।

पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री सोमाविया ने अपने भाषण में कहा, 'इस संघर्ष में हमें बेहतर करना चाहिए और इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर उच्चतम शिखर की ओर कदम बढ़ाना चाहिए कि कामकाजी लोगों के परिवारों को प्रतिष्ठा और सुरक्षा मिले और वे एक शांतिपूर्ण दुनिया में सांस लें। अगर आपको विश्व शांति चाहिए तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित कीजिए।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के प्रति समर्थन जुटाने और जागरूकता बढ़ाने के मद्देनजर इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की जाती है। यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में विभिन्न सरकारों और नागरिक समाज के संगठनों के प्रयासों का सम्मान करता है। युनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर पार्टनरशिप्स (यूएनओपी) और मिलेनियम कैंपेन के सहयोग से यह पुरस्कार दिया जाता है।

वर्ष 1999 में महानिदेशक बनने के बाद से श्री सोमाविया आईएलओ की उत्कृष्ट श्रम कार्यसूची के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। आईएलओ की इस कार्यसूची में विश्व के सभी लोगों को स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और मानव प्रतिष्ठा की स्थितियों में उत्पादक और उत्कृष्ट श्रम प्रदान किए जाने का समर्थन किया गया है। यही बात मिलेनियम डिक्लरेशन में भी कही गई हैं।

आईएलओ महानिदेशक ने खान मजदूरों के बचाव अभियान की प्रशंसा की

13 अक्टूबर को आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया ने चिली में दो महीने तक खदानों में फंसे रहे 33 खान मजदूरों के बचाव अभियान की प्रशंसा की।

वह वक्त श्री सोमाविया के लिए बहुत भावनात्मक था। उत्तरी चिली की एक खदान में 33 खान मजदूर दो महीने से फंसे हुए थे। उनके लिए चलाए जाने वाले बचाव अभियान के प्रति अपनी भावनाओं को जाहिर करते हुए श्री सोमाविया ने एक वक्तव्य जारी किया। बयान में श्री सोमाविया ने कहा, 'आईएलओ का महानिदेशक होने के अलावा मैं चिली का नागरिक भी हूं। इन दो अलग–अलग और महत्वपूर्ण पहचान के साथ मैं दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ अपनी खुशी बांटना चाहता हूं। यह खुशी उन नायकों के लिए है जो पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलने वाले हैं।'

उन खान मजदूरों के धैर्य, साहस, संगठन और जिजीविषा के कारण ही यह संभव हुआ है। इस बात के लिए भी हम उनकी तारीफ करते हैं। उन्होंने त्रासदी

के समय अदम्य सहनशीलता का परिचय दिया, जिसके कारण बचाव अभियान को निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहा। हम सभी इस सहनशीलता से चकित हैं। मैं उन सभी लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं।'

श्री सोमाविया ने अपने बयान में इस सामूहिक सफलता में योगदान देने वाले, सावर्जनिक और निजी क्षेत्र के, चिली और चिली के बाहर के लोगों के कार्य, कौशल और योग्यता को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा, 'हमें खान मजदूरों और पूरे देश और उनके आत्मविश्वास की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया।'

अपने बयान में श्री सोमाविया ने कहा कि खान मजदूरों की इस कहानी से पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए। 'हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस हादसे की शुरुआत कैसे हुई। ये मजदूर सिर्फ इसलिए फंसे रहे क्योंकि खदान के सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं थे। कार्यस्थल पर पूरे सुरक्षा उपाय किए जाएं– आईएलओ की यही मुख्य चिंता है।'

श्री सोमाविया ने कहा, 'चिली में कार्यस्थल पर सुरक्षा का मुद्दा सरकार, नियोक्ता और श्रमिकों की संयुक्त कार्यसूची का अंग है। उत्कृष्ट श्रम के सिद्धांतों से मार्गदर्शन हासिल करते हुए आईएलओ उन लोगों के साथ काम करता रहेगा और उन लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करेगा।'

उन्होंने कहा, 'लेकिन खनन उद्योग और विश्व के अन्य जोखिमपरक उद्योगों में काम की स्थितियों को सुधारने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।'

श्री सोमाविया ने कहा, 'आईएलओ अनुमानों के अनुसार खनन उद्योग में विश्व की एक प्रतिशत श्रमशक्ति कार्यरत है, पर इसी के साथ इस क्षेत्र में आठ प्रतिशत घातक दुर्घटनाएं भी होती हैं..... हर दिन 6300 लोग व्यवसायगत दुर्घटनाओं या बीमारियों के शिकार भी होते हैं। यह आंकड़ा साल भर में 23 लाख से अधिक मौतों तक जाता है। इसमें साल भर में 33 करोड़ 70 लाख दुर्घटनाओं को भी जोड़ा जाना चाहिए।' ■

© एम. क्रोपेट / आईएलओ

अर्थशास्त्र के क्षेत्र में साल 2010 का नोबल पुरस्कार

साल 2010 में तीन प्रमुख अर्थशास्त्रियों को अल्फ्रेड नोबल की याद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाले स्वरेजेस रिक्सबैंक पुरस्कार से नवाजा गया। इस पुरस्कार के मद्देनजर आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया ने रॉयल स्विडिश अकादमी के निर्णय पर अपनी सहमति जताई।

नोबल पुरस्कार के मद्देनजर श्री सोमाविया ने कहा, 'जिस कार्य के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रियो को सम्मानित किया गया है, वह बहुत प्रासंगिक है। विश्व भर की सरकारें इस बात को लेकर चिंतित हैं कि किस प्रकार आर्थिक प्रगति को उन लोगों से जोड़ा जाए जिन्हें रोजगार और उत्कृष्ट श्रम की बहुत आवश्यकता है। इन अर्थशास्त्रियों का कार्य इसी विषय को केंद्र में रखता है।'

श्री सोमाविया ने कहा, 'रॉयल स्विडिश अकादमी का यह निर्णय रोजगार के महत्व, श्रम बाजार और सामाजिक संरक्षण नीतियों और सामाजिक नीतियों के साथ उनके संबंध और लोगों पर होने वाले उनके असर को रेखांकित करता है।'

स्वरेजेस रिक्सबैंक पुरस्कार को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के तौर पर अधिक जाना जाता है। आर्थिक नीति और नियम किस प्रकार रोजगार, रिक्तियों और वेतन को प्रभावित करते हैं, इस विषय पर काम करने के लिए इन तीनों अर्थशास्त्रियों को पुरस्कृत किया गया है। गौरतलब है कि आईएलओ भी इन मुद्दों पर काम करता है।

विशेषज्ञों ने कृषि क्षेत्र में सुरक्षा और स्वास्थ्य पर आईएलओ की नई व्यवहार संहिता को मंजूरी दी

29 अक्टूबर 2010 को कृषि क्षेत्र में सुरक्षा और स्वास्थ्य पर आईएलओ की नई व्यवहार संहिता को मंजूरी दी गई। श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों ने इस संहिता को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले एक अरब लोगों के काम की स्थितियों में सुधार करना था।

जेनेवा में आयोजित पांच दिवसीय बैठक में विशेषज्ञों के एक दल ने एक नई व्यवहार संहिता के मसौदे को मंजूर किया। इस दल में 15 देशों के सरकारी, नियोक्ता और श्रमिक सदस्य शामिल थे। इस संहिता को मार्च 2011 में होने वाली संचालन निकाय की बैठक में संपुष्टि के लिए भेजा जाएगा।

इस नई संहिता का उद्देश्य यह है कि कृषि क्षेत्र में ऐसी व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच)संस्कृति को प्रोत्साहित करने में मदद की जाए जो लोगों को अधिक से अधिक सुरक्षित रखें। गौरतलब है कि कृषि क्षेत्र में विश्व की कुल श्रमशक्ति का दो तिहाई से अधिक हिस्सा लगा हुआ। इससे अधिक लोग केवल सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह नई व्यवहार संहिता आईएलओ के समझौते, कृषि क्षेत्र में सुरक्षा और स्वास्थ्य, 2001 (संख्या 184) और उनकी अनुवर्ती सिफारिश (संख्या 192) की अनुपूरक है और इन दोनों उपायों में दिए गए सुझावों को लागू करने का मार्गदर्शन देती है।

अनेक देशों में कृषि क्षेत्र में महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में रोजगार करती हैं, खास तौर से अफ्रीका और एशिया के देशों में। इसी क्षेत्र में बाल श्रम भी पाया जाता है। लगभग 70 प्रतिशत बाल श्रमिक इस क्षेत्र में काम करते हैं।

संहिता का मसौदा कृषि क्षेत्र से जुड़े जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है और बताता है कि उनका कारगर प्रबंधन और

नियंत्रण कैसे किया जाए। यह भी कि व्यवसायगत दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम कैसे की जाए और काम के परिवेश में कैसे सुधार किया जाए। मसौदा सरकारों, नियोक्ताओं, श्रमिकों और अन्य भागीदारों को प्रोत्साहित करता है कि वे दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम करें और व्यवसायगत सुरक्षा व स्वास्थ्य के प्रति अधिक सकारात्मक रवैया अपनाएं।

कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मशीनों, पशुओं, पौधों और उत्पादों का उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के कृषि उद्यम भी हैं, जैसे छोटे स्तर पर किसानी से लेकर बड़े स्तर पर मैकेनाइज्ड कारोबार। आईएलओ के सेक्टोरल एक्टिविटीज प्रोग्राम की निदेशक एलिजाबेथ टिनोको के अनुसार, 'ऐसी विविध विशेषताओं, रोजगार और उद्यम दोनों के स्तर पर, के कारण इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम के लिए जोखिम का बड़े स्तर पर आकलन करने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। दूसरे उद्योगों की अपेक्षा यह उद्योग अधिक जोखिमपरक है। हर साल बहुत से खेत मजदूर व्यवसायगत दुर्घटनाओं और बीमारियों का शिकार होते हैं।'

इस नई संहिता के माध्यम से एक राष्ट्रीय संरचना की स्थापना होगी और प्रशासन, नियोक्ता, श्रमिकों और उनके संगठनों की भूमिकाएं तय होंगी। संहिता में कृषि क्षेत्र के मुख्य जोखिमों और खतरों की पहचान करने और उन्हें लक्षित करने के विशेष प्रावधान हैं।

आईएलओ की इस व्यवहार संहिता का उपयोग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों द्वारा किया जाएगा। उन पर विशिष्ट व्यवसायगत जोखिमों, काम के क्षेत्रों या उपकरणों से संबंधित सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संहिता किसी देश के कानून या नियमों या स्वीकृत मानकों की जगह नहीं लेगी। ■

महाद्वीपों के

© डी.रिउनोंद / आईएलओ

आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया और ब्राजील की राजदूत मारिया नजरेथ फरानी अजेवेरो

आईएलओ और ब्राजील साथ साथ हैं

पिछले साल अक्टूबर में, ब्राजील सरकार और आईएलओ ने तीन दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक और प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में विभिन्न देशों का सामर्थ्य बढ़ाना है। ट्यूरिन में आईएलओ प्रशिक्षण केंद्र द्वारा विकसित इस संयुक्त कार्यक्रम द्वारा मानवीय सहायता के संबंध में विभिन्न देशों के क्षमता निर्माण में सुधार किया जाएगा, उन्हें प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं की रोकथाम के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और संकट के बाद पुनर्वास करना सिखाया जाएगा। कार्यक्रम के शुरुआती लाभार्थी देश हैं हैती, नाइजर, अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र, पूर्वी तिमोर और पुर्तगाली भाषी अफ्रीकी देश। लगभग 276 सरकारी अधिकारियों को क्षमता निर्माण आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ब्राजील साल 2005 से आईएलओ के साथ बाल श्रम, बलात श्रम और सामाजिक संरक्षण आदि से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में भागीदार रहा है। यह पहली बार है कि श्रम की दुनिया में मानवीय सहायता पर किसी कार्यक्रम में आईएलओ और ब्राजील एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

यूथ इंप्लॉयमेंट नेटवर्क

JACOBS FOUNDATION

पिछले साल जुलाई में, आईएलओ के इंटरएजेंसी पार्टनरशिप, यूथ इंप्लॉयमेंट नेटवर्क (येन), संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और विश्व बैंक ने जेकब्स फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जेकब्स फाउंडेशन स्विट्जरलैंड स्थित एक निजी फाउंडेशन है। इस समझौते का उद्देश्य युवा रोजगार कार्यक्रमों के असर का मूल्यांकन करते हुए रोजगार के क्षेत्र में एक एविडेंस बेस बनाना है। तीन साल के लिए जेकब्स फाउंडेशन सीएचएफ 450000 का अनुदान देगा। युवा रोजगार के मूल्यांकन के लिए इस कार्यक्रम को फंड के जरिए लागू किया जाएगा। योग्य युवा रोजगार संगठन अपने आवेदन भेज सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रस्ताव भेजने पड़ेंगे। इसके बाद चुने हुए संगठनों को वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया ड्रयू गार्डिनर, यूथ इंप्लॉयमेंट नेटवर्क से संपर्क करें,
ईमेल: *gardiner@ilo.org*, फोन : *+4122/799-7824;*, वेबसाइट: *www.ilo.org/yen.*

© जेकब्स फाउंडेशन

डॉ. बर्नार्ड इबेरसोल्ड, सीईओ, जेकब्स फाउंडेशन

आईएलओ ने ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया

पिछले साल सितंबर में आईएलओ ने कंबोडिया सरकार के गारमेंट क्षेत्र के संगठनों और मैन्यूफैक्चरों के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया। यह समझौता इस क्षेत्र में सुधार करने से संबंधित है। समझौते में सामूहिक सौदेबाजी, मध्यस्थता, उत्पादकता के महत्वपूर्ण पहलू ओर क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट उपाय शामिल हैं। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली गारमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन इन कंबोडिया (जीएमएसी) देश की 300 बड़ी फैक्टरियों का प्रतिनिधित्व करती है। इन कारखानों में कंबोडिया के तीन लाख मजदूर काम करते हैं। इन मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले परिसंघ ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आईएलओ के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें, फोन: +66 2 288 1234; फैक्स: +66 2 288 3062, ईमेल: bangkok@ilo.org

इर्द गिर्द

सभी को मिले सामाजिक संरक्षण का लाभ

© आईएलओ फोटो

पिछले साल अक्टूबर में वियतनाम की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर एडवाइजरी ग्रुप की अध्यक्ष चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट ने विश्वव्यापी सामाजिक संरक्षण का आह्वान किया। सुश्री बाचेलेट यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक भी हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक संरक्षण उन सभी लोगों को 'फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस' (शुरुआती सुरक्षा) देता है जिन पर आर्थिक संकट का बहुत बुरा असर होता है। यह कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा सामाजिक संरक्षण से सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल करना आसान है। सामाजिक संरक्षण के संदर्भ में आईएलओ और डब्ल्यूएचओ ने एक यून इनीशिएटिव (संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम) की शुरुआत की है जो बुनियादी सामाजिक संरक्षण अधिकारों को प्रोत्साहित करता है। साथ ही गरीबों को सशक्त करने और संवेदनशील लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए रोजगार, स्वास्थ्य, पानी और साफ–सफाई, पोषण, शिक्षा और पारिवारिक समर्थन आदि प्रदान करता है। इस दौरान सुश्री बाचेलेट ने एन बिन्ह गांव का दौरा भी किया। इस गांव में ताओ येउ मे नामक फंड (टीवाईएम या पीपल लविंग पीपल फंड) की मदद से बहुत सी खेतिहर महिलाओं को लाभ हुआ है। इस फंड को साल 1992 में गठित किया गया था। अब तक इस फंड की सहायता से 55000 महिलाओं ने गरीबी के कुचक्र को तोड़ने में कामयाबी पाई है। सुश्री बाचेलेट एन बिन्ह गांव की उन महिलाओं से मिलीं जिन्हें इस फंड से लाभ हुआ है। गौरतलब है कि आईएलओ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, प्रारंभिक जांच और लघु वित्त उत्पादों के वितरण के माध्यम से इस फंड का क्षमता निर्माण करता है।

म्यूरल का उद्घाटन

24 सितंबर, 2010 को वियतनाम के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इनवैलिड्स एंड सोशल अफेयर्स, वितयनाम जनरल कनफेडरेशन ऑफ लेबर, वियतनाम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वियतनाम कोऑपरेटिव अलायंस और आईएलओ के प्रतिनिधियों ने एक म्यूरल का उद्घाटन किया जिसका नाम है 'डीसेंट वर्क एंड ट्राइपरटिज्म।' यह म्यूरल हनोई की नई सिरामिक रोड का हिस्सा है। इस सिरामिक मोजैक म्यूरल रोड की लंबाई चार किलोमीटर है। हनोई में होंग नदी के किनारे बने इस म्यूरल को विश्व के सबसे लंबे म्यूरल के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। डीसेंट वर्क एंड ट्राइपरटिज्म नामक टुकड़ा 70 मीटर लंबा है। इसे देश की सरकार, श्रमिकों और नियोक्ता संगठनों तथा आईएलओ का समर्थन प्राप्त है। यह वियतनाम के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, कृषि, हस्तशिल्प और एक्वाकल्चर आदि की गतिविधियों को चित्रांकित करता है। इस रंगीन सिरामिक में श्रम बाजार के विभिन्न कारकों– सरकार, श्रमिक और नियोक्ताओं– के साथ–साथ उनके बीच समन्वय, सामाजिक संवाद और वियतनाम में उत्कृष्ट श्रम को भी दर्शाया गया है।

© आईएलओ फोटो

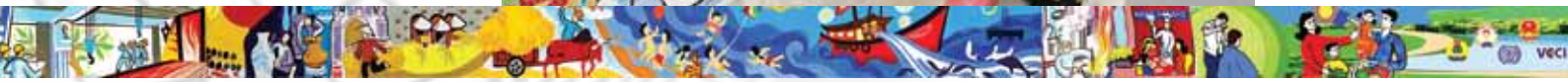

आईएलओ ने शुरू किया स्टैटिस्टिक्स डेटाबेस

20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे के अवसर पर आईएलओ ने एक नए स्टैटिस्टिक्स डेटाबेस की शुरुआत की। श्रम बाजार और उपभोक्ता मूल्यों की जानकारी वाले इस डेटाबेस का लाभ उन सभी को होगा जो आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। इस डेटाबेस को हर महीने श्रम बाजार के हालिया और अल्पावधि के बदलावों के मद्देनजर राष्ट्रीय आंकड़ों से अपडेट किया जाएगा। इसमें 70 देशों और क्षेत्रों के चुने हुए संकेतक शामिल हैं जिनमें मौजूदा वर्ष की वार्षिक सूचना शामिल है। इसके अतिरिक्त लिंग के आधार पर अलग–अलग किए गए 40 संकेतक भी इस डेटाबेस में उपलब्ध हैं।

इस नई सेवा में एक मानचित्र भी दिया गया है जिसमें देश और क्षेत्र के अनुसार आंकड़ों को संकलित किया गया है। देश के आधार पर संकलित आंकड़ों के अंतर्गत हर देश के खंड में उस देश के श्रम बाजार की स्थितियों की जानकारी है, जबकि विषय के आधार पर संग्रहित आंकड़ों के तहत विभिन्न देशों की तुलना और विश्वव्यापी विश्लेषण किया गया है। इन आंकड़ों को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों से संपर्क करके इकट्ठा किया गया है और ऐसी प्रक्रिया तैयार की गई है जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र की जा सके। सबसे खास बात यह है कि इस डेटाबेस में क्षेत्रीय आंकड़ों को भी शामिल किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट देखें http://laborsta.ilo.org/sti/sti_E.html

नए प्रकाशन

फ्रॉम द ग्रेट रिसेशन टू लेबर मार्केट रिकवरीः इश्यूज, एविडेंस एंड पॉलिसी ऑप्शंस

इयांतुल इस्लाम और शेर वेरिक (संपादन) आईएसबीएन 978–92–2–124031–0, जेनेवा, आईएलओ 2010, पैलग्रेव मैकमिलन के साथ सहप्रकाशित, 105 अमेरिकी डॉलर, 75 यूरो, 110 स्विस फ्रैंक्स

यह पुस्तक साल 2007–2009 के वित्तीय संकट के वृहद आर्थिक और श्रम बाजार आयामों पर प्रमुख विशेषज्ञों के अध्ययनों को प्रस्तुत करती है। विश्वव्यापी दृष्टिकोण प्रदान करते हुए पुस्तक विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों के परिप्रेक्ष्य में मंदी के कारणों, परिणामों और नीतिगत प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करती है। इस बात पर बल देते हुए कि उपयुक्त वृहद आर्थिक और श्रम बाजार नीतियों की जरूरत है, पुस्तक के संपादक संकट उपरांत नीतिगत विकल्पों को तलाशने की कोशिश करते हैं। पुस्तक इस बात की हिमायत करती है कि भविष्य में पूर्ण रोजगार के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई जानी चाहिए और निष्पक्ष वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने के लिए विश्वव्यापी सामूहिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2010–11 : वेज पॉलिसीज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस

आईएसबीएन 978–92–2–123621–04, जेनेवा, आईएलओ 2010, 50 अमेरिकी डॉलर, 35 यूरो, 50 स्विस फ्रैंक्स। फ्रेंच और स्पैनिश भाषाओं में भी प्रकाशित

आईएलओ रिपोर्ट्स की श्रृंखला में यह दूसरी रिपोर्ट वेतन प्रवृतियों पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट में साल 2008 और 2009 के आर्थिक संकट के दौरान विश्वव्यापी और क्षेत्रीय वेतन प्रवृतियों पर चर्चा की गई है। रिपोर्ट के भाग एक में मासिक औसत वेतन की वृद्धि में आई कमी और वेतन में होने वाले अल्पावधि के उतार–चढ़ावों की जानकारी थी। भाग दो में संकट और बहाली के दौरान वेतन नीतियों की भूमिका पर चर्चा की गई है। भाग तीन में रिपोर्ट का सार है और उन मुद्दों को रेखांकित किया गया है जो वेतन नीतियों में सुधार के लिए निर्णायक हैं।

वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट 2010: फ्रॉम वन क्राइसिस टू नेक्स्ट?

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज, आईएसबीएन 978–92–9014–948–4,, जेनेवा, आईएलआ 2010, 50 अमेरिकी डॉलर, 35 यूरो, 50 स्विस फ्रैंक्स।

साल 2008 में लेहमैन ब्रदर्स के धराशाई होने के बाद मंदी आई और इसके बाद अर्थव्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं आया। अधिकतर देशों में आर्थिक बहाली की दर कमजोर और असमान रही है। कुछ देशों में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक रही और लगभग सभी देशों में रोजगार में अस्थिरता बढ़ती गई। जिन देशों से संकट की शुरुआत हुई थी, वित्तीय प्रणाली दुष्क्रिय रही, जिससे उद्यमिता निवेश प्रभावित हुआ और रोजगार बहाली में विलंब हुआ। रिपोर्ट बताती है कि दीर्घकालिक, रोजगार समृद्ध बहाली संभव है– अगर संकट उत्पन्न करने वाले कारकों से अच्छी तरह से निपटा जाए।

ईयरबुक ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, 2010. टाइम सीरिज

आईएसबीएन 978–92–2–023438–9, जेनेवा, आईएलओ 2010, 275 अमेरिकी डॉलर, 205 यूरो, 290 स्विस फ्रैंक्स। अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पैनिश भाषाओं में प्रकाशित

साल 1935– 36 में अपने पहले संस्करण से लेकर अब तक, ईयरबुक ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स श्रम संबंधी मसलों पर सांख्यिकीय संदर्भ प्रस्तुत करने वाला सबसे उल्लेखनीय संकलन रहा है। विश्व के लगभग 190 देशों की अधिकृत सूचनाओं से एकत्र किए गए आंकड़ों को यह संग्रह बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। टाइम सीरिज में नौ प्रमुख अध्याय हैं। ये अध्याय आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या, रोजगार, बेरोजगारी, काम के घंटे, वेतन, श्रम मूल्य, उपभोक्ता मूल्य, व्यवसायगत चोट और हड़ताल–तालाबंदी पर केंद्रित हैं। इन अध्यायों में 31 तालिकाएं भी शामिल हैं।

ईयरबुक ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, 2010. कंट्री प्रोफाइल्स

आईएसबीएन 978–92–2–023439–6, जेनेवा, आईएलओ 2010, 190 अमेरिकी डॉलर, 140 यूरो, 200 स्विस फ्रैंक्स। अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पैनिश भाषाओं में प्रकाशित

कंट्री प्रोफाइल्स में 200 देशों, क्षेत्रों और उपक्षेत्रों के ताजा आंकड़ों (टाइम सीरिज के बिना)का प्रदर्शन करने वाले नए फॉरमैट को प्रस्तुत किया गया है।

दोनों टाइटिल्स के लिए विशेष प्रस्ताव : टाइम सीरिज और कंट्री प्रोफाइल्स : आईएसबीएन 978–92–2–023440–2, 375 अमेरिकी डॉलर, 275 यूरो, 390 स्विस फ्रैंक्स

ईयरबुक ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, 2010. सोर्सेज एंड मैथेड्स

लेबर स्टैटिस्टिक्स, अंक 1–10. सीडी रोम, आईएसबीएन 978–92–2–123441–8, जेनेवा, आईएलओ 2010, सिंगल यूजर : 275 अमेरिकी डॉलर, 205 यूरो, 290 स्विस फ्रैंक्स। मल्टी यूजर : 415 अमेरिकी डॉलर, 310 यूरो, 435 स्विस फ्रैंक्स। केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध

मेकिंग माइग्रेशन अ डेवलपमेंट फैक्टर : द केस ऑफ नार्थ एंड वेस्ट अफ्रीका

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज, आईएसबीएन 978–92–9014–928–6, जेनेवा, आईएलओ 2010, 20 अमेरिकी डॉलर, 14 यूरो, 20 स्विस फ्रैंक्स। फ्रेंच और स्पैनिश भाषाओं में भी प्रकाशित।

उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में विश्वव्यापी आर्थिक संकट से पहले भी रोजगार की स्थिति खराब थी। इसके बाद तो हालत और बदतर हो गई। इस क्षेत्र के बहुत से श्रमिक पहले से यूरोप के कई देशों, खास तौर से फ्रांस, इटली और स्पेन में पलायन कर चुके हैं। इस समय अफ्रीकी देशों के सामने मानव संसाधन बढ़ाने, विदेशों से भेजी जाने वाली रकम को बढ़ाने और प्रवासियों को वापस बुलाने जैसी चुनौतियां हैं। इस रिपोर्ट में उन तरीकों पर चर्चा की गई है जिसके तहत प्रवास और अच्छे श्रम बाजार उपायों के माध्यम से विकास को समर्थन दिया जा सके। रिपोर्ट में अल्जीरिया, मॉरितानिया, मोरक्को, सेनेगल और ट्यूनीसिया के मामलों को शामिल किया गया है।

ग्लोबल इंप्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ

आईएसबीएन 978–92–2–123855–3, जेनेवा, आईएलओ 2010, 39 अमेरिकी डॉलर, 28 यूरो, 40 स्विस फ्रैंक्स।

श्रम बाजार की ताजा उपलब्ध सूचनाओं वाली इस रिपोर्ट में बेरोजगारी और उत्कृष्ट श्रम घाटे के प्रति युवाओं की संवेदनशीलता की पड़ताल की गई है। रिपोर्ट बताती है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के लाभ के लिए युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और रचनात्मकता का कितना दोहन किया गया। इसमें विश्व और क्षेत्रीय स्तर के युवा श्रम बाजार संकेतकों की जानकारी है और युवा जनसंख्या, श्रमशक्ति, रोजगार और बेरोजगारी की दीर्घावधि की प्रवृतियों का विस्तृत विश्लेषण है। रिपोर्ट में पहली बार युवाओं के बीच श्रमशील निर्धनता के नए अनुमान भी दिए गए हैं।

आईएलओ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेज़ (रिवाइज्ड 2010). आईडेंटिफिकेशन एंड रेकोगनिशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेज: क्राइटेरिया फॉर इनकोऑपरेटिंग डिजीजेज इन द आईएलओ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेज

ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सीरिज, संख्या 74, आईएसबीएन 978–92–2–123795–2, जेनेवा, आईएलओ 2010, 30 अमेरिकी डॉलर, 22 यूरो, 30 स्विस फ्रैंक्स। फ्रेंच और स्पैनिश भाषाओं में भी प्रकाशित।

श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले भौतिक, रसायनिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक–सामाजिक कारणों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 1919 में अपनी स्थापना के समय से ही आईएलओ काम करने की सुरक्षित और स्वस्थ स्थितियों का समर्थन करता रहा है। सरकार, नियोक्ता व श्रमिक संगठनों द्वारा स्वीकृत इस नई सूची को मार्च, 2010 में मंजूर किया गया है। इसमें व्यवसायगत बीमारियों की पहचान की गई है और उन्हें मान्यता दी गई है। व्यवसायगत बीमारियों पर केंद्रित सिफारिश, 2002 (संख्या 194) की सूची में इस सूची को संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त इस सीरिज में व्यवसायगत बीमारियों की रोकथाम करने, उन्हें दर्ज और अधिसूचित करने और जहां जरूरी हो, वहां मुआवजा देने के संबंध में विभिन्न देशों का मार्गदर्शन किया गया है।

ऑफशोरिंग एंड वर्किंग कंडीशंस इन रिमोट वर्क

जॉन मैसेंजर एंड नाज घोशेष (संपादन)। आईएसबीएन 978–92–2–123001–4, जेनेवा, आईएलओ 2010, 100 अमेरिकी डॉलर, 75 यूरो, 110 स्विस फ्रैंक्स। फ्रेंच और स्पैनिश भाषाओं में भी प्रकाशित। पैलग्रेव मैकमिलन के साथ सहप्रकाशित।

इनफॉरमेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजीज में तरक्की, साथ ही लागत में कटौती करने के इच्छुक संगठनों के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग लगातार बढ़ी है। खासतौर से भारत जैसे विकासशील देशों की ओर। इस पुस्तक में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) उद्योग के विकास का ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हुए इस प्रक्रिया की व्याख्या की गई है। जिन चार देशों– अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत और फिलीपींस– में यह उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, इस पुस्तक में उन देशों के उदाहरण दिए गए हैं। पुस्तक में नीति निर्धारकों और कंपनियों को नीतिगत परामर्श दिया गया है कि किस प्रकार इन उद्योगों के बढ़ने के साथ–साथ अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

विमेन इन लेबर मार्केट्स: मेजरिंग प्रोग्रेस एंड आईडेंटिफाइंग चैलेंजेस

आईएसबीएन 978–92–123318–3, जेनेवा, आईएलओ 2010, 25 अमेरिकी डॉलर, 18 यूरो, 25 स्विस फ्रैंक्स।

15 वर्ष पहले बीजिंग में चौथा विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण पर कार्रवाई करने के लिए विश्वव्यापी मंच पर स्वीकृति बनी थी। इस रिपोर्ट में कार्यस्थल पर लैंगिक समानता की प्रगति का मूल्यांकन किया गया है और यह जानने की कोशिश की गई है कि इस दिशा में क्या अवरोध हैं। आईएलओ के नए *की इंडिकेटर्स ऑफ द लेबर मार्केट (केआईएलएम)* के माध्यम से इस रिपोर्ट में पुरुषों और महिलाओं द्वारा किए गए श्रम उत्पादनों की तुलना की गई है। निष्कर्ष के तौर पर कहा गया है कि दोनों के बीच रोजगार के अवसरों और गुणवत्ता में भेदभाव पाया जाता है।

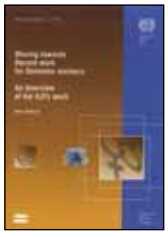

मूविंग टुवर्ड्स डीसेंट वर्क फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स: एन ओवरव्यू ऑफ द आईएलओज़ वर्क

वर्किंग पेपर 2/2010 आशा डिसूजा आईएसबीएन 978–92–122050–3, जेनेवा, आईएलओ 2010, 30 अमेरिकी डॉलर, 22 यूरो, 30 स्विस फ्रैंक्स। फ्रेंच और स्पैनिश भाषाओं में भी प्रकाशित।

घरेलू श्रमिकों को आम तौर पर लंबे घंटों तक काम करना पड़ता है। उन्हें बहुत कम वेतन और सामाजिक संरक्षण मिलता है। साल 2010 के अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन से पहले तेयार किए गए इस अध्ययन में घरेलू श्रम की विशेषताओं को रेखांकित किया गया है। अध्ययन घरेलू श्रमिकों से संबंधित आंकड़ों के अभाव की समस्या की पड़ताल करता है, घरेलू श्रमिकों के खिलाफ होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन की गणना करता है, श्रम से संबंधित मौजूदा आईएलओ मानकों और राष्ट्रीय कानूनों पर चर्चा करता है और अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघों और गैर सरकारी संगठनों की मौजूदा गतिविधियों का ब्यौरा देता है।

ऐक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2008–2009: आईपैक प्रोग्रेस एंड फ्यूचर प्रायोरिटीज

आईएसबीएन 978–92–2–123250–6, जेनेवा, आईएलओ 2010, 20 अमेरिकी डॉलर, 14 यूरो, 20 स्विस फ्रैंक्स। फ्रेंच और स्पैनिश भाषाओं में भी प्रकाशित।

बाल श्रम उन्मूलन हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों में से एक है। इस समय बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाने वाले आईपैक कार्यक्रम (अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम) के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं जिनमें मौजूदा आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध आदि ने और इजाफा किया है। इस रिपोर्ट में आईपैक के तहत आईएलओ के सदस्य देशों में चलाई जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। साथ ही बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए अधिक सुसंगत, अधिक दीर्घकालिक विश्वव्यापी प्रयासों को विकसित करने संबंधी मार्गदर्शन किया गया है।

ग्लोबल चाइल्ड लेबर डेवलपमेंट: मेजरिंग ट्रेंड्स फ्रॉम 2004 टू 2008

याकूबा डिएलो, फ्रैंक हगेमान, एलेक्स इटियाने, योंका गुरबुजेर और फरहाद मेहरान, आईएसबीएन 978–92–2–123522–4, जेनेवा, आईएलओ 2010, 20 अमेरिकी डॉलर, 14 यूरो, 20 स्विस फ्रैंक्स। फ्रेंच और स्पैनिश भाषाओं में भी प्रकाशित।

बाल श्रम पर अधिक जानकारी जुटाने के प्रयासों के मद्देनजर, आईएलओ ने साल 2008 के लिए नए विश्वव्यापी और क्षेत्रीय अनुमानों और साल 2004 से 2008 की प्रवृतियों को प्रस्तुत करने के लिए यह पुस्तक जारी की है। इस पुस्तक में कई प्रोत्साहनपरक प्रवृतियों का ब्यौरा है जैसे साल 2004 से 2008 के दौरान 5 से 17 साल के बाल श्रमिकों की संख्या विश्व स्तर पर कम हुई है (1 करोड़ 70 लाख के करीब)। इनमें बालिकाओं की संख्या (1 करोड़ 50 लाख) और जोखिमपरक काम करने वाले बच्चों की संख्या (1 करोड़ 30 लाख की कमी) काफी कम हुई है। फिर भी रोजगार करने वाले 30 करोड़ 60 लाख बच्चों में, बाल श्रमिकों की संख्या 17 करोड़ 60 लाख है और 7 करोड़ 60 लाख बच्चे जोखिमपरक कामों में लगे हुए हैं। उनके लिए आईएलओ के न्यूनतम आयु समझौते (1973, संख्या 138) और बाल श्रम के निकृष्ट रूप समझौते (1999, संख्या 182) के संदर्भ में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

माइक्रोइंश्योरेंस इनोवेशन फेसिलिटी: प्रोटेक्टिंग द वर्किंग पुअर, एनुअल रिपोर्ट 2009

आईएसबीएन 978–92–2–123050–2, जेनेवा, आईएलओ 2010, 15 अमेरिकी डॉलर, 12 यूरो, 15 स्विस फ्रैंक्स। फ्रेंच और स्पैनिश भाषाओं में भी प्रकाशित।

विकासशील देशों में निम्न आय वर्ग के अनेक परिवारों के लिए दुर्घटना, बीमारी, परिवार में होने वाली मौत और खराब मौसम बहुत बड़ी समस्याएं लेकर आते हैं। ऐसे समय में माइक्रोइंश्योरेंस (लघु बीमा) उनके लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। इसके तहत गरीब लोगों को तमाम तरह के जोखिमों से सुरक्षा मिलती है। इसे चुकाना आसान होता है क्योंकि इनका प्रीमियम उनकी प्राथमिकताओं और भुगतान की क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आईएलओ की माइक्रोइंश्योरेंस इनोवेशन फेसिलिटी खास तौर से उन लोगों के लिए है जिन्हें सचमुच इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस विस्तृत रिपोर्ट का उद्देश्य प्रबंधकों की मदद करना है जिससे वे लाखों गरीब कामगारों तक बीमा सुविधा पहुंचा सकें, खास तौर से अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले गरीब मजदूरों तक। माइक्रोइंश्योरेंस इनोवेशन फेसिलिटी पर दूसरी वार्षिक रिपोर्ट को साल 2008 में आईएलओ द्वारा जारी किया गया थ। बिल एंड मेलिंग गेट्स फाउंडेशन द्वारा इसे सहयोग प्राप्त है।

इंप्लॉयमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन इन द न्यू डेमोग्राफिक कंटेक्सट

आईएसबीएन 978–92–2–122689–5, जेनेवा, आईएलओ 2010, 30 अमेरिकी डॉलर, 22 यूरो, 30 स्विस फ्रैंक्स। फ्रेंच और स्पैनिश भाषाओं में भी प्रकाशित।

जीवन संभाव्यता में वृद्धि और प्रजनन में गिरावट, विश्व जनसांख्यिकी को अनेक प्रकार से प्रभावित कर रही है। विकसित देशों में वृद्धों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और अब यही प्रवृति विकासशील देशों में भी देखने को मिल रही है। औद्योगिकृत देशों में जहां सामाजिक सुरक्षा का दायरा बड़ा है, वृद्धों को लंबे समय तक काम करने का मौका नहीं मिलता। निम्न आय वर्ग के देशों में वृद्धों को बहुत कम संख्या में सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल पाता है। श्रम बाजारों और सामाजिक नीतियों को तत्काल ऐसे बदलते समय के तहत कार्य करना चाहिए। उन्हें वृद्धों को अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा की दुविधा का हल करना चाहिए।

ब्रिकी के लिए आईएलओ के प्रकाशन बड़े पुस्तक विक्रेताओं या विभिन्न देशों में स्थित आईएलओ के स्थानीय कार्यालयों या सीधे आईएलओ थियेटर कोर्ट, तीसरी मंज़िल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नयी दिल्ली–110 003 से प्राप्त किये जा सकते हैं। दूरभाष: 24602101, 2462102, फैक्स: 24602111, ई–मेल: delhi@ilo.del.org इस पते द्वारा कैटेलॉग और नए प्रकाशनों की सूची निशुल्क प्राप्त की जा सकती है। विकासशील देशों के ग्राहकों को पत्रिका में दर्ज मूल्य से छूट भी मिल सकती है। ग्राहक आईएलओ के फील्ड ऑफिस के जरिये स्थानीय मुद्रा में पत्रिका की कीमत चुका सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें pubvente@ilo.org

ग्लोबल साउथ– साउथ डेवलपमेंट एक्सपो 2010 (जीएसएसडी) www.southsouthexpo.org

संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जीएसएसडी विकासशील देशों और उनकी सहयोगी दाता एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को दक्षिण दक्षिण विकास समाधानों को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है। आईएलओ की मेजबानी में इस एक्सपो को 22 से 26 नवंबर के दौरान संगठन के जेनेवा स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। विकास के लिए आवश्यक उपायों में सामाजिक संरक्षण और उत्कृष्ट श्रम, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, एचआईवी एड्स, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि शामिल हैं। इन उपायो को दक्षिणी देशों की ऐतिहासिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थितियों के तहत विकसित किया गया है क्योंकि ये उपाय उस क्षेत्र में गहरे समाए हुए हैं।

" दक्षिणी देशों ने न केवल अपनी भौगोलिक सीमाओं के भीतर गरीबी से लड़ने का मन बना लिया है, बल्कि वे दूसरे विकासशील देशों के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। यह प्रवृति अनेक देशों में देखने को मिल रही है, जिनमें मजबूती से उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी हैं और दूसरे देश भी। "

बान की मून,
महासचिव, संयुक्त राष्ट्र

" दक्षिणी देश जिस विकासपरक दृष्टिकोण से वित्त और तकनीकी मदद कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही विकासपरक समन्वय के लिए भी उनका धन्यवाद किया जाना चाहिए। "

हेलन क्लार्क,
प्रशासक, संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम

" राष्ट्रीय स्वायतत्ता और प्राथमिकताओं के लिए सम्मान, परिस्थितियों और उपायों की विविधता, देशों के बीच एकात्मकता, यही सूत्र सभी समाधानों की शुरुआत करता है। दक्षिण दक्षिण समन्वय का यही स्वरूप आईएलओ की उत्कृष्ट श्रम कार्यसूची के अनुकूल है। आईएलओ दक्षिणी क्षेत्र के परस्पर समन्वय को देखते हुए अपनी कार्यसूची को मदद के लिए प्रस्तुत करता है जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित किया जा सके। हमारा निरंतर सहयोग आपके साथ है। "

हुआन सोमाविया,
महानिदेशक, आईएलओ

आप इन सभी फोटो को निम्नलिखित वेबसाइट पर देख सकते हैं:
http://www.ilo.org/dyn/media/mediasearch.specialDetail?p_lang=en&p_special_main_id=27

© सभी फोटो : एम. क्रोज़ेट, एल. फोरतुनाती, पी. एल्बॉय

हाथों में हुनर, चेहरे पर खुशी

घरेलू काम को पेशेवर बनाने और घरेलू श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, दिल्ली सरकार और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज अनेक घरेलू श्रमिकों के चेहरों पर खुशी है और हाथों में हुनर। भारत के 47 लाख से भी अधिक घरेलू श्रमिकों की जिंदगी बदलने की पहल पर दिल्ली से स्वतंत्र पत्रकार की एक रिपोर्ट।

कागज पर अपना नाम लिखते हुए उसके चेहरे पर गर्व से भरी खुशी साफ नजर आती है। अंग्रेजी भाषा में, टेढ़े–मेढ़े अक्षरों में ही सही, वह अपना नाम लिखना जानती है। दस साल पहले जब वह इस भीड़ भाड़ वाले शहर में आई थी, तब लिखे हुए शब्द उसके लिए काले–सफेद धब्बों के अलावा कुछ नहीं थे। पर आज कुंवारी सब कुछ सीख गई है।

कुंवारी... दिल्ली की पॉश कालोनी ग्रीन पार्क में एक उच्च वर्गीय परिवार की 22 साल की घरेलू नौकरानी। झारखंड के गांव सुंदरपुर से दस–ग्यारह साल पहले कितने सपने लेकर दिल्ली आई थी कुंवारी। यह सपने सिर्फ उसके अपने नहीं थे। उसमें उसके पांच बहन–भाइयों के सपनों भी शामिल थे। गांव में रहने वाले उसके पिता इतने गरीब थे कि बच्चों को पढ़ाना उनके बस में नहीं था। पढ़ाना तो दूर की बात है, परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। वह एक खेत मजदूर थे। तब कुंवारी ने यह तय किया था कि वह दिल्ली जाकर पैसा कमाएगी, ताकि उसके भाई–बहन भरपेट खा सकें, पढ़–लिख भी सकें।

कुंवारी अपनी एक सखी के साथ दिल्ली आई। एक परिचित व्यक्ति उसे दिल्ली लाया और यहां एक गैर सरकारी संगठन युवती निवास ने उसे आसरा दिया। उसे पढ़ना–लिखना सिखाया। उसके लिए काम की तलाश की। फिर काम करने के दौरान ही कुंवारी को आईएलओ के कार्यक्रम *स्किल्स डेवलपमेंट इनीशिएटिव फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स* (घरेलू श्रमिकों के लिए कौशल विकास पहल) की जानकारी मिली। इस कार्यक्रम की मदद से उसने अपने काम को और बेहतर तरीके से करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई है। वह कहती है, 'इस प्रोग्राम की मदद से मैंने बहुत कुछ सीखा। घर की साफ–सफाई, फोन अटेंड करना, मेहमानों का स्वागत करना, टेबल मैनेर्स आदि सब कुछ। इसके अलावा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम ने मेरे अंदर यह भरोसा जगाया कि मैं अकेली नहीं हूं। लोग मेरे साथ हैं और मेरी मदद करना चाहते हैं। मैंने महसूस किया कि जो काम मैं करती हूं, उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। मैं चाहती हूं कि मैं आगे भी बहुत कुछ सीखूं और अपनी जिंदगी सुधार सकूं।'

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय, दिल्ली सरकार और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने संयुक्त रूप से वर्ष 2008 में *स्किल्स डेवलपमेंट इनीशिएटिव फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स* नामक कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत दिल्ली में घरेलू श्रम को पेशेवर बनाए जाने की पहल की जा रही है। आंकड़े कहते हैं कि भारत में घरेलू नौकर–नौकरानियों की संख्या 47 लाख 50 हजार के करीब है। इनमें बड़े बड़े शहरों में काम करने वाली घरेलू नौकरानियों की संख्या 30 लाख से भी ज्यादा है। उन्हें पेशेवर बनाने का अर्थ है, दूसरे श्रमिकों की ही तरह उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाए। आईएलओ बहुत लंबे समय से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने की पहल कर रहा है जिससे उन्हें उत्कृष्ट रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। घरेलू श्रमिक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का ही अंग हैं और उन्हें उत्कृष्ट रोजगार प्राप्त हो सके, संगठन इसी उद्देश्य से इस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित कर रहा है।

आईएलओ के दिल्ली स्थित दक्षिण एशियाई उपक्षेत्रीय कार्यालय में घरेलू श्रमिकों के प्रशिक्षण प्राप्त दल के सदस्यों के साथ हॉलीवुड अदाकारा मोनिक कोलमैन।

कार्यक्रम के तहत घरेलू नौकर–नौकरानियों को पहले चरण के प्रशिक्षण में साफ–सफाई, रसोई में मदद करना सिखाया जाता है। वे कैसे साफ–सफाई के उत्पादों और उपकरणों पर लिखे संकेतों, दिशानिर्देशों को पढ़कर उनका इस्तेमाल करें, खाना पकाते समय, मसालों आदि के पैकेटों पर लिखे संकेतों को समझें, पहले चरण में यह भी सिखाया जाता है। दूसरे चरण में खाना पकाना, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना सिखाया जाता है। घरेलू श्रमिक अब तक इन दोनों चरणों का लाभ उठा चुके हैं। अब तीसरे और चौथे चरण की तैयारी चल रही है। इनमें बच्चों–बुजुर्गों की देखभाल और इसके बाद नर्सिंग, कम्यूनिटी हेल्थ, सेक्रेटेरियल, हॉस्पिटैलिटी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को कई गैर सरकारी संगठनों की मदद से चलाया जा रहा है।

इस कार्यक्रम की मदद से अपना जीवन संवारने की कोशिश जासिंता भी कर रही है। जासिंता की कहानी भी कुंवारी जैसी ही है। जासिंता असम के छोटे से गांव अमलाई गुड़ी की रहने वाली है। अपनी सही उम्र तो वह नहीं बता पाती, लेकिन यह जरूर बताती है कि जब तीन साल पहले वह अपनी बुआ के साथ दिल्ली आई थी, तब उसकी उम्र 12 या 13 साल थी। बुआ ने उसे अच्छा काम दिलाने का वादा किया था, पर बुआ ने जिस जगह उसे सबसे पहले काम दिलवाया, 'वह साहब लोग अच्छे नहीं थे', वह कहती है, 'सारा दिन काम करना पड़ता था, आराम करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता था।' तब उसे 1600 रुपए महीने मिलते थे। एक साल बाद उसने वह काम छोड़ दिया। जासिंता कहती है, 'फिर मैं अपनी छोटी बुआ, जो दिल्ली में ही रहती थी, उसके पास पहुंची। छोटी बुआ ने मुझे युवती निवास का रास्ता दिखाया। यहां सिस्टर ने मुझे अच्छा काम दिलवाया और ट्रेनिंग करवाई।'

जासिंता ने आईएलओ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखा। वह कहती है, 'प्रोग्राम में हमने सीखा कि घर का काम करने का भी तरीका होता है। जब मैं गांव से दिल्ली आई थी, तब मुझे कुछ नहीं आता था। पर मैं सब कुछ सीख गई हूं। साफ–सफाई करने के लिए ही मुझे साढ़े तीन हजार रुपए मिलते हैं। मेरी मेमसाहब लोग बहुत खुश हैं कि मैं इतना सीख गई हूं। मैं प्रोग्राम से आगे भी बहुत कुछ सीखना चाहती हूं।'

वेतन में बढ़ोतरी की बात विलासी भी कहती है। दक्षिणी दिल्ली में घर सफाई का काम करने वाली विलासी ने जब प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, तब उसे 1800 रुपए मिलते थे। उसकी 'मेमसाहब' ने ही उसे कोर्स में दाखिला दिलाया। अब उसे अपने काम के लिए 2200 रुपये मिलने लगे हैं। पर बात सिर्फ रुपयों की नहीं है। विलासी कहती है, 'यह हमारे लिए इज्जत की बात भी है कि हमने कुछ सीख लिया है। हम बेकार और निकम्मे नहीं हैं।'

ये कुछ खुशकिस्मत महिलाएं हैं जिन्हें अपनी स्थिति से ऊपर उठकर कुछ नया सीखने का मौका मिला। आईएलओ की डीडब्ल्यूटी फॉर साउथ एशिया की निदेशक टिने स्टीयरमोस कहती हैं, 'ये महिलाएं खुशकिस्मत हैं कि उनके सपने सच हुए। देश के बड़े बड़े शहरों में लोगों के घरों में बर्तन–सफाई करके, अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली सभी महिलाएं इतनी खुशकिस्मत नहीं होतीं। उनके काम को काम ही कहां माना जाता है? अक्सर वे कम तनख्वाह के, बिना किसी छुट्टी के सालों–साल काम करती रहती हैं, शारीरिक–मानसिक–यौन शोषण का शिकार होती रहती हैं।'

आईएलओ दुनिया भर में घरेलू श्रम को श्रम का दर्जा दिलाने का प्रयास कर रहा है। 1948 से यह आईएलओ की चिंता का विषय रहा है। सिद्धांत रूप से आईएलओ के सभी श्रम समझौतों और सिफारिशों में सभी श्रमिकों को शामिल किया जाता है, जिसमें घरेलू कामगार भी शामिल है। पर वर्ष 2010 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में घरेलू श्रम से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। पहले दौर के विमर्श के बाद अब इस साल आयोजित होने वाले श्रम सम्मेलन में दूसरे दौर का विमर्श किए जाने की संभावना है। इसके बाद घरेलू श्रमिकों पर केंद्रित समझौते और संबंधित सिफारिश की दिशा में बढ़ना आसान होगा।

इसके अतिरिक्त संगठन घरेलू श्रमिकों के लिए समर्थन जुटाने का एक अभियान भी चला रहा है। *योर वर्क इज इंपोर्टेंट* (आपका काम भी महत्वपूर्ण है) नामक इस अभियान में घरेलू श्रमिकों के लिए उत्कृष्ट श्रम को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है। अभियान के तहत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज के संगठनों, रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशनों, घरेलू श्रमिकों और युवाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। घरेलू श्रमिकों के लिए उत्कृष्ट श्रम कार्यसूची के चार सिद्धांत हैं– कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांत और अधिकार, सामाजिक संरक्षण बढ़ाना, उत्कृष्ट और उत्पादक रोजगार तक पहुंच और कार्यस्थल पर अभिव्यक्ति और प्रतिनिधित्व।

हॉलीवुड की मशहूर ऐक्ट्रेस मोनिक कोलमैन घरेलू श्रमिकों की युवा ब्रिगेड को सलाम करती हैं। संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में मना रहा है। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने मोनिक को अपना युवा चैंपियन नियुक्त किया है। मोनिक विश्व के विभिन्न देशों का दौरा कर रही हैं और युवाओं से जुड़े मसलों पर सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। भारत आने पर उन्होंने युवा घरेलू श्रमिकों के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'अगर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता को समझकर उसे संवारने का प्रयास करे तो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पूरी दुनिया में युवाओं को अपनी शक्ति पहचाननी होगी और खुद को अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना होगा। इस काम में हम सब उनके साथ हैं।'

दक्षिण एशिया में बेरोजगारी का खतरा ज्यादा : आईएलओ

नई दिल्ली। भारत सहित दक्षिण एशिया में नौकरियों पर खतरा ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वार्षिक ग्लोबल इंप्लायमेंट ट्रेंडस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इलाके में 58 करोड़ लोग इस श्रेणी में आते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में नौकरियों पर खतरे वाली श्रेणी के लोगों का वेतन कम है और उनकी सामाजिक सुरक्षा भी बहुत थोड़ी है। वास्तव में पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में नौकरियों पर खतरे का मामला विश्व के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा है। बहरहाल इस हफ्ते जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और दक्षिण एशिया में बेरोजगारी की दर स्थिर है। इसमें कहा गया है कि तेजी से आर्थिक विकास फिर शुरू हो गया है और क्षेत्र में बेरोजगारी की दर स्थिर है जो वर्ष 2007 से 2010 के बीच 4.3 और 4.5 के बीच है।

इसमें कहा गया है कि बहरहाल क्षेत्र में नौकरियों पर खतरा पूरी दुनिया की तुलना में ज्यादा है जो वर्ष 2009 में कुल रोजगार का 78.5 फीसदी है। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि श्रम बाजार की चुनौतियों में सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं हैं। इसमें युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है और कहा गया है कि युवा लोग वयस्कों की तुलना में 3.5 गुना ज्यादा बेरोजगार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लिंग आधारित असमानता भी है। जैसे कम उत्पादकता या ज्यादा खतरे वाली नौकरियों में महिलाओं की संख्या कम है।

वर्ष 2011 में 20 करोड़ 33 लाख लोग रहेंगे बेरोजगार : आईएलओ

जेनेवा (ए)। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने विकसित देशों में रोजगार वृद्धि की दर धीमी रहने पे चेतावनी देते हुए कहा है कि वर्ष 2011 में दुनिया भर में तकरीबन 20 करोड़ 33 लाख लोग बेरोजगार रहेंगे।

आईएलओ ने यहां जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि आर्थिक संकट के तीसरे वर्ष भी बेरोजगारी दर में वृद्धि हो रही है और यह वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। हालांकि विकसित देशों में रोजगार बहाली की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाएं उछाल पर हैं, लेकिन रोजगार से जुड़े आंकड़े निराशाजनक रहे हैं। वर्ष 2010 में तकरीबन 20 करोड़ 50 लाख लोगों के पास रोजगार नहीं था। आईएलओ की वैश्विक रोजगार 2011 रोजगार सुधार की चुनौतियां रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि की दर अलग-अलग हैं। बेरोजगारी की दर में इजाफा हो रहा है और विकसित देशों की स्थिति हताश करने वाली है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं उछाल पर है और निजी निवेश, व्यापार और श्रम बाजारों से मजबूती के संकेत मिल रहे है लेकिन रोजगार की स्थिति इतनी बेहतर नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अनेक देशों में आर्थिक वृद्धि की गति तेज रही है लेकिन वर्ष 2011 में इस क्षेत्र में रोजगार की दर में वृद्धि होगी ऐसा नहीं लगता। क्षेत्र का रोजगार परिदृश्य अनिश्चित और अस्पष्ट है। एशिया ओर प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न देशों की सरकारें इस साल बेरोजगारी, संवेदनशील रोजगार, निर्धन श्रमशक्ति और सामाजिक सुरक्षा के अभाव जैसे मसलों से जूझती रहेगी।

मंदी के बादल छंटे पर बेरोजगारी कम नहीं हुई : आईएलओ

"दुनिया भर के श्रम बाजारों में अलग-अलग तरह से सुधार हुआ, मंदी की भारी मानवीय कीमत हमें अब तक चुकानी पड़ रही है।"

-जुआन सोमाविया

जिनीवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने चेतावनी दी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुधार के बाद भी बेरोजगारी में कमी नहीं आई है और 2010 में भी दुनिया के कुल बेराजगारों की संख्या 20.50 करोड़ रही।

श्रम संगठन ने एक रपट में कहा कि अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी के सुधार के बावजूद भी 2010 में कुल 20.5 करोड़ लोग बेरोजागार रहे, जो पिछले साल 2009 के बराबर हैं, जबकि यह संख्या 2007 के कुल बेरोजगारों से 2.76 लाख अधिक है।

इस रपट में आईएलओ ने वैश्विक बेरोजगारी दर 6.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, जिसके लिहाज से 2011 में यह आंकड़ा बढ़कर 20.33 करोड़ तक पहुंच जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी के मुताबिक इसके आधे से ज्यादा 2007 के दौरान आर्थिक मंदी की शुरुआत के समय बेरोजगार हुए। जबकि अनेक लोग नौकरी करने की उम्र में पहुंच गए, लेकिन उन्हें अभी तक काम नहीं मिला।

हालांकि ब्राजील, कजाखस्तान और थाईलैंड जैसे विकासशील देशों की बेरोजगारी दर में आर्थिक मंदी से पहले की बेरोजगारी दर की तुलना में गिरावट आई है।

आईएलओ के महानिदेशक जुआन सोमाविया ने कहा कि दुनियाभर के श्रम बाजारों में अलग-अलग तरह से सुधार हुआ, मंदी की भारी मानवीय कीमत हमें अब तक चुकानी पड़ रही है।

बेरोजगारी के अलावा अभी भी करीब 1.53 अरब लोग अस्थाई किस्म के कभी भी छूट जाने वाले काम में लगे हैं।

मोनक ने जताई डोमेस्टिक वर्कर्स की स्थिति पर चिंता

नई दिल्ली (एसएनबी)। यूनाइटेड नेशन यूथ चैंपियन और हॉलीवुड अभिनेत्री मोनक कोलमैन ने कहा कि घरेलू नौकरों से जुड़े मुद्दे दुनियाभर में कमोबेश एक जैसे ही हैं। चूंकि एशिया देश अभी विकासशील हैं लिहाजा यहां घरेलू नौकरों के साथ समस्याएं ज्यादा हैं। हाई स्कूल म्यूजिक फिल्म में टेलर मेकेंसी का किरदार निभाने वाली मोनक विश्व टूर के दौरान इन दिनों भारत दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने राजधानी की डोमेस्टिक वर्कर्स से मुलाकात की। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस (आईएलओ) के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में अपने अनुभव को उन्होंने आंख खोलने वाला बताया। इस अवसर पर घरेलू नौकरों की समस्याओं और उनकी घटनाओं पर प्रकाश डालता एक नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया। मोनक ने वहां घरेलू नौकरों पर आयोजित फोटो प्रदर्शनी भी देखी।

पिछले दो महीने से टूर कर रही मोनक कोलमैन ने कहा कि अपने टूर के दौरान मैंने युवाओं, महिलाओं और डोमेस्टिक वर्कर्स से मुलाकात की। उनकी समस्याएं और चुनौतियों से भरी उनकी जिंदगी देखकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि घरेलू नौकरों की दयनीय स्थिति और उनके मुद्दों पर पूरे समाज को विचार करना होगा। पुरुषों को यहां अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल पर किसी भी महिला घरेलू नौकर के साथ दुर्व्यवहार न हो। ज्ञात हो कि वे अपने टूर के दौरान आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलिपीन्स, बीजिंग और बांग्लादेश का दौरा कर चुकी हैं। कोलमैन ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। यह रंगों से भरा देश है।

▶ हॉलीवुड अभिनेत्री मोनक कोलमैन ने की डोमेस्टिक वर्कर्स से मुलाकात

मैंने यहां बेहद दिलचस्प अनुभव किए हैं, गाय को सड़क पार करते देखा है। फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से युवाओं में जागृति फैला रही हॉलीवुड अभिनेत्री ने कहा कि यूएन द्वारा निर्धारित मिनिमम डवलपमेंट गोल को हमें हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि युवा हमारा भविष्य नहीं वर्तमान है। कोलमैन ने घरेलू नौकरों के साथ बातचीत की और उनके साथ फोटो खिंचवाई। इस अवसर पर रीना कुकरेजा द्वारा बनाई गई फिल्म दिल्ली बाउंड फॉर वर्क भी दिखाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दक्षिण एशिया के लिए आईएलओ डीब्लूटी की निदेशक टिन स्टेरमोस ने कहा कि घरेलू नौकरों के मुद्दे हम सभी से जुड़े हैं। यह हमारे आसपास की वे चीजें हैं जिनका हम सभी को एहसास होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की युवा आइकॉन भारती ने कहा कि हम सभी को घरेलू नौकरों का भरपूर सम्मान करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि अगर हमारे कार्यस्थल पर हमारे साथ कुछ गलत होता है, बुरा सुलूक होता है तब हमें कैसा लगता है। डोमेस्टिक वर्कर भी हमारी तरह इंसान हैं और हमें उनका व उनके कार्य को इज्जत की नजर से देखना चाहिए।

मंदी के बादल छंटे पर बेरोजगारी नहीं हुई कम

जनीवा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन [आईएलओ] ने चेतावनी दी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुधार के बाद भी बेरोजगारी में कमी नहीं आई है और 2010 में भी दुनिया के कुल बेरोजगारों की संख्या 20. 50 करोड़ रही। श्रम संगठन ने एक रपट में कहा कि अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी के सुधार के बावजूद भी 2010 में कुल 20.5 करोड़ लोग बेरोजगार रहे, जो पिछले साल 2009 के बराबर हैं, जबकि यह संख्या 2007 के कुल बेरोजगारों से 2.76 लाख अधिक है।

इस रपट में आईएलओ ने वैश्विक बेरोजगारी दर 6.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, जिसके लिहाज से 2011 में यह आंकड़ा बढ़कर 20.33 करोड़ तक पहुंच जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी के मुताबिक इसके आधे से ज्यादा 2007 के दौरान आर्थिक मंदी की शुरुआत के समय बेरोजगार हुए। जबकि अनेक लोग नौकरी करने की उम्र में पहुंच गए, लेकिन उन्हें अभी तक काम नहीं मिला। हालांकि ब्राजील, कजाखस्तान और थाईलैंड जैसे विकासशील देशों की बेरोजगारी दर में आर्थिक मंदी से पहले की बेरोजगारी दर की तुलना में गिरावट आई है।

मंदी के बादल छंटे पर कम नहीं हुई बेरोजगारी

जेनेवा (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने चेतावनी दी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुधार के बाद भी बेरोजगारी में कमी नहीं आयी है और 2010 में भी दुनिया के कुल बेराजगारों की संख्या 20.50 करोड़ रही।

श्रम संगठन ने सोमवार को एक रपट में कहा कि अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी के सुधार के बावजूद भी 2010 में कुल 20.5 करोड़ लोग बेरोजगार रहे, जो पिछले साल 2009 के बराबर हैं, जबकि यह संख्या 2007 के कुल बेरोजगारों से 2.76 लाख अधिक है।इस रपट में आईएलओ ने वैश्विक बेरोजगारी दर 6.1 फीसद रहने का अनुमान लगाया है, जिसके लिहाज से 2011 में यह आंकड़ा बढ़कर 20. 33 करोड़ तक पहुंच जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी के मुताबिक इसके आधे से ज्यादा 2007 के दौरान आर्थिक मंदी की शुरुआत के समय बेरोजगार हुये। जबकि अनेक लोग नौकरी करने की उम्र में पहुंच गए, लेकिन उन्हें अभी तक काम नहीं मिला। हालांकि ब्राजील, कजाखस्तान और थाईलैंड जैसे विकासशील देशों की बेरोजगारी दर में आर्थिक मंदी से पहले की बेरोजगारी दर की तुलना में गिरावट आई है।

एशियाई देश मंदी से बेअसर

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया खुलासा

अजयभान सिंह @ नई दिल्ली

दुनिया भर के शक्तिशाली बाजारों को ताश के पत्ते की तरह जमीन सुंघा देने वाली आर्थिक मंदी के तीन साल पूरे होने और उसकी धार कुंद होने के बावजूद सम्पन्न देश आज भी औंधे मुंह पड़े हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुमान है कि लोगों को रोजी रोटी देने के मामले में भारत समेत तमाम एशियाई देशों ने इस बार भी बाजी मार ली है और इनके प्रदर्शन में सुधार जारी रहने की उम्मीद है।

आईएलओ ने सोमवार को जारी वैश्विक रोजगार के हालात विषयक रिपोर्ट में विकसित देशों के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि 2011 में भी उनके रोजगार के हालात सुधरने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। 2010 में भी पिछले साल की तरह वैश्विक बेरोजगारी का आधिकारिक स्तर करीब 25 करोड़ पर अटका रहा। 2011 में भी बेरोजगारी की दर 6.1 यानी बीस करोड़ से ऊपर रहने की उम्मीद है। खासतौर से विकसित देशों के श्रम बाजार में बहुत सुधार नजर नहीं आ रहा है जबकि वह देश अब मंदी के घटाटोप से उबरने लगे हैं।

दक्षिण एशिया की चर्चा करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र के देशों की आर्थिक तरक्की बहुत तेज रफ्तार से हो रही है इस कारण यहां रोजगार के हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं। इस साल भी यहां रोजगार बढ़ने की संभावना है। पिछले तीन सालों में पूरे क्षेत्र में बेरोजगारी की दर यूरोप के 6.1 के मुकाबले 4.3 से लेकर 4.5 के बीच झूलती रही। इस प्रदर्शन को बेहतर कहा जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में कभी भी बेरोजगारी का शिकार हो जाने वाले लोगों का औसत दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 78.5 प्रतिशत है। गौरतलब है कि दक्षिण एशिया में भारत और उसके पड़ोसी देश शुमार किए जाते हैं।

दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र को लेकर रिपोर्ट कहती है कि इस क्षेत्र में भी मंदी के शुरुआती हिचकोले खाने के बाद अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ गई है जिसके कारण बेरोजगारी की दर लुढ़ककर 4.1 प्रतिशत तक आ गई है। हालांकि यह दर मंदी के पूर्व की दर से कहीं अधिक है। लेकिन सेवा क्षेत्र में लगातार बढ़त दर्ज किए जाने से रोजगार के अवसर बढ़ते जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की भी कमोबेश ऐसी ही हालत रही। मंदी के कारण इस क्षेत्र में रोजगार की संख्या नहीं गुणवत्ता प्रभावित हुई थी। बाजारों के उबरने के बाद यहां भी बेरोजगारी की दर में कमी आई है।

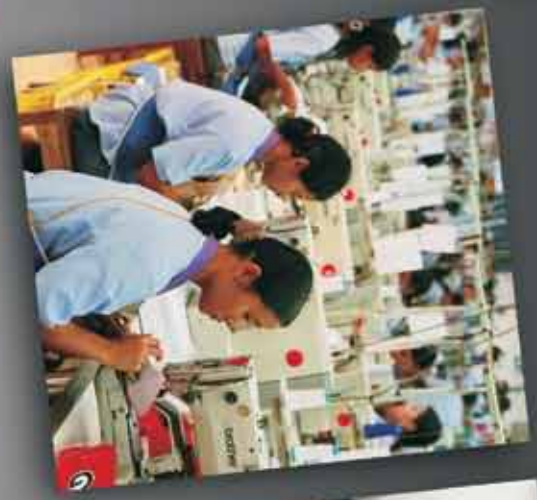

© आईएलओ फोटो